भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था :- किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या या समाज की भौतिक जरूरतों की पूर्ति करने वाली गतिशील प्रणाली को अर्थ० कहते हैं, जो सभी प्रकार के आ० क्रिया०, आ० अभिकर्ताओं, संबंध संस्थाओं एवं इन सबके पारस्परिक संबंधों से मिलकर बनी होती है। (निश्चित उद्देश्य से कार्य करने वाला व्यक्ति)

कर्ता
⇓
बिना किसी निश्चित उद्देश्य के काम

- भौतिक / आर्थिक → उपभोग की जरूरत
  - → आवश्यक
  - → आरामदायक
  - → विलासितापूर्ण
  - } तर्कपूर्ण
  - → नई हीन
- उत्पादन
  - → संसाधन / मुद्रा
  - → आय प्रवाह
  - → रोजगार

NOTE
आवश्यकता कि सही पूरी

APL
———— गरीबी रेखा।
BPL
(कम क्षमता)
⇓
आय प्रवाह < need
⇓
रोजगार no

यू => APL↑ BPL↓ => अर्थ० की गुणवत्ता ↑

गरीबी - ~~व्यक्तिनिष्ठ~~ तथ्य है
Subjective

आयोजन - aim ⟶ ~~गरीबी~~

अर्थ० की संरचना

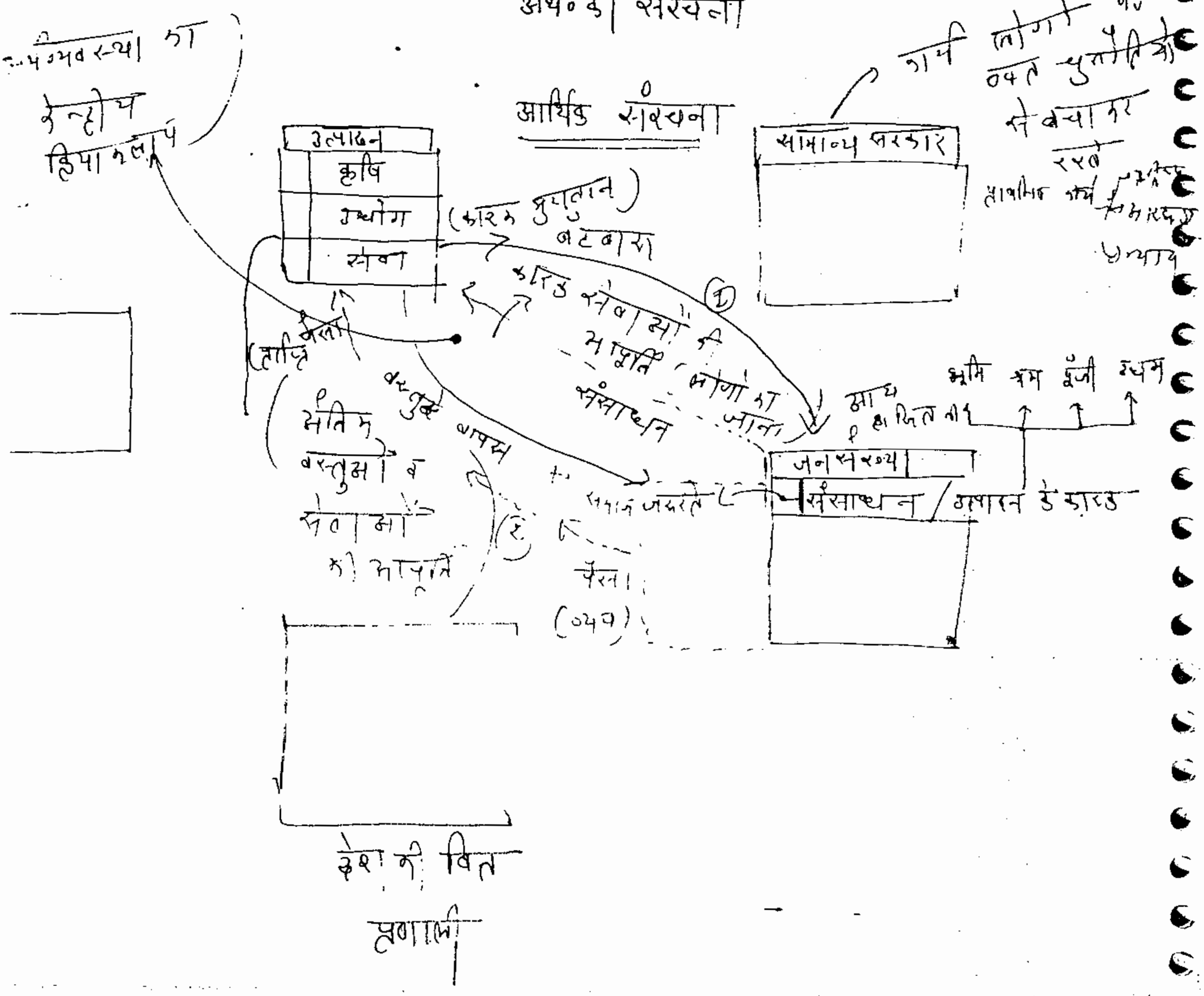

आय का चक्रीय प्रवाह :- कारक सेवाओं की आपूर्ति तथा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के परस्पर निर्भर चक्रीय प्रवाह को आय का चक्रिय प्रवाह कहते हैं। स्वरूप/पक्ष के आधार पर दो प्रकार

1) वास्तविक आय का चक्रिय प्रवाह

2) मौद्रिक आय का चक्रिय प्रवाह

(1) गैर मौद्रिक अर्थात भौतिक रकाइयों में आकलित कारक सेवाओं तथा उत्पादित व० एवं सेवाओं के चक्रिय प्रवाह को वास्तविक आय का च० प्रवाह कहते हैं।

(2) मौद्रिक इकाइयों में आकलित कारक सेवाओं तथा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के चक्रिय प्रवाह को मौ० आ० का च० प्र०

- inf + Def both are आ० विचलन
  ⇓
  दोनों में संतुलन

आदर्श स्थिति की

कीमत में स्थायित्व बना रहे।

1000 रु = मौद्रिक
100 इकाई => वास्तविक
मौद्रिक आय / वास्तविक आय = कीमत

कीमत स्तर पर वृद्धि => Inf

अनिश्चितता का परित्याग

कीमत कमी when unit बढ़े

चक्रीय प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक –

- Inflation – Deflation (कीमत निर्धारण) (मांग की कीमत : आर्थिक चुनौती)
- बाह्य आक्रमण
- आंतरिक अस्थिरता
- अन्याय

(शासन प्रणाली के अंदर ही जन्म)

बाजार प्रणाली के बाहर पैदा

केन्द्रीय आर्थिक चुनौतियाँ

- आंतरिक
- बाह्य

प्र

सरकार –

शासन का मुख्य उद्देश्य समाज के भौतिक जीवन में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर अंकुश बना कर रखें

- प्राकृतिक एवं अस्थिरता, आक्रमण, अन्याय
- द्वितीयक कार्य (कल्याण)

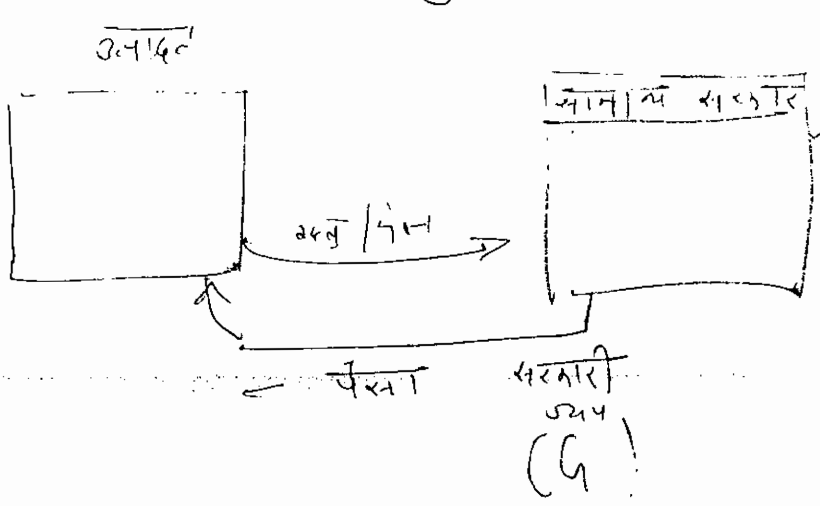

शासन के उद्देश्य

शासन व्यवस्था है सर्वव्यापी की ?

शासन व्यवस्था है ——→ उत्पादन प्रेरणा

शासन
Governance

- अच्छा शासन (सुशासन)
- खराब शासन (कुशासन)

Case study ⇒ U.P.

(शासन ... प्रेरणा)

कल्याण व अवधारणा ... की आवश्यकता (समाज) पूरी करने हेतु प्रयास

- भौतिक
- गैर भौतिक

सब्सिडी
उपभोक्ता राज्य सहायता (सामाजिक कल्याण)

सरकार → समाज

गुणकारी सब्सिडी ⇒ only for असमर्थ वर्ग

गैर गुणकारी सब्सिडी ⇒ समर्थ वर्ग तक ⇒ इसकी पूर्ति हेतु

Direct
Indirect
उत्पादन
सरकार
जनसंख्या
APL
सभी

tax, why सरकार विनियमन की सुरक्षा हमारा है + सुविधाएं देती है।

if all चीज सही मार्ग तो गुणात्मक वृद्धि स्वतः उत्पन्न होगा।

गुणात्मक वर्गीकरण

आय का सुचक्र (Spiral up)
⇓
उत्पादन + उपभोग का स्तर उत्तरोत्तर बेहतर होता जाये।

उदाहरण Spiral up होगा

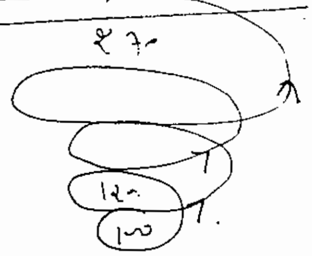

आय का कुचक्र
⇓
उत्पादन + उपभोग का स्तर उत्तरोत्तर गिरता जाये

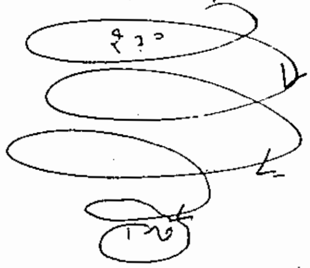

Spiral down होगा

शासन में सुधार →
⇓
आय का कुचक्र ——→ सुचक्र में बदल

अर्थव्यवस्था में प्रशासन की क्या भूमिका

आय ⇒ उपभोग + बचत

आय ⇒ उपभोग
(निर्वाह अर्थ.)

↳ व्यवसाय कार्य कर्ताओं की आय इतनी कम हो, कि सिर्फ वर्तमान जरूरतें ही

पूर्ति हो पाये। भविष्य की जरूरतों के लिए आय का कोई अंश बच नहीं पाये।

(अधिशेष अर्थ०)

← आय => उपभोग + बचत

=> इसके ज्यादातर कार्यकर्ताओं की आय इतनी ऊँची हो कि वर्तमान जरूरतों की पूर्ति के बाद भविष्य की जरूरतों के लिए भी आय का पर्याप्त अंश बच जाये।

हड़प्पा => पहली अधि० अर्थ०

उदा० - [illegible]

उभरू → सुदृढ़ → सतत → Surplus Economy

1947 → now

↳ निम्न स्तरीय अधिशेष — उच्च स्तरीय अधि० (Maximum)

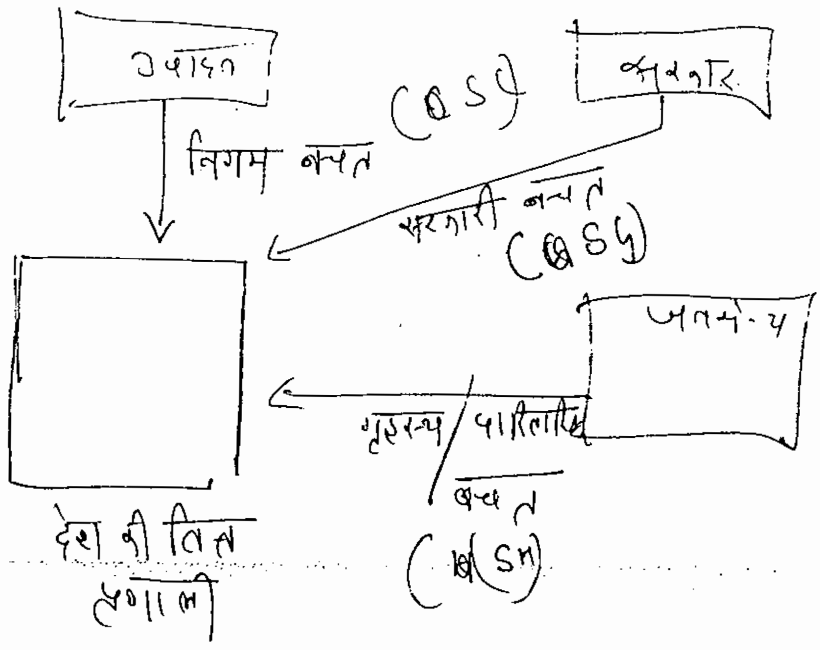

किसी भी Co. में बचत के तीन प्रमुख स्रोत → [illegible], [illegible], उत्पादक स्रोत

तीनों बचतों के योग को सकल घरेलू बचत कहते हैं। (Gross Domestic Saving)

$GDS = S_h + S_c + S_g$

- निजि
- सार्वजनिक

निगम बचत के दो घटक

- सरकारी / वर्तमान (जोकि ऋणात्मक हैं)
- सार्वजनिक

सकल घरेलू बचत के योगदान

$S_h > S_{c निजी} > S_{c सर}$

ऋणात्मक / नकारात्मक बचत : वित्त प्रणाली से जो (राजकोषीय घाटा) भाग सरकार लेती है।

राज० अधिशेष → सकारात्मक बचत

राजकोषीय घाटा ⟹ GDS ⟹ निवेश

निवेश : उगाही राशि का उत्पादन में प्रयोग

→ उपगाहि सकल राशि का उत्पादन में प्रयोग
सकल घरेलू निवेश

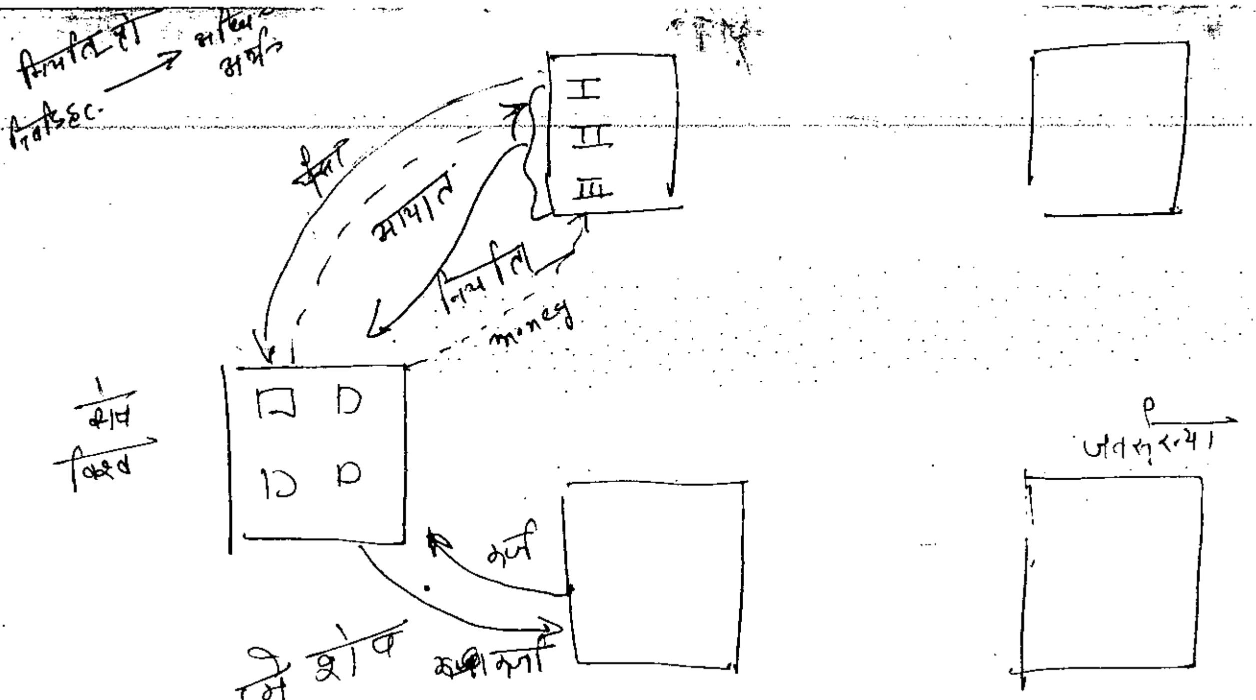

Ques क्या हमें शोध विश्व के साथ किसी तरह का ~~कोई~~ रिश्ता हो या नहीं

बंद अर्थ० वो देश जो दुनिया के किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का आ० लेन-देन ना करे, उसको अर्थ० ।

खुली अर्थ० (open economy) है जो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ विभिन्न प्रकार के आ० लेन-देन के लिए सहर्ष तैयार हो ।

Ques खुली अर्थ०

इंजिलेन्ट ओपन eco. (प्रशासित खुली अर्थ०)

eco लेन-देन but सहर्ष नहीं

आयोजन

क्या है – राज्य/सरकार के नेतृत्व में सभी प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से प्रबंधन, ताकि निर्धारित रा० उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित हो।

दोहन

1) आयोजन की परिभाषा

2) Goal – सबके लिए गरिमापूर्ण जीवन + liberty

3) Aim

संसा० का आंकलन → घरेलू / विदेशी

↓

घरे० / विदेशी → दोहन (mobilisation)

↓

घरेलू / विदे० → आवंटन

↓

निवेश ० (उत्पादन कार्य में उपयोग)

↓

प्रतिफल

P० प्रारंभ से ही खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित रहा है।

राष्ट्रीय उद्देश्य

↳ संविधान में उल्लिखित – भाग-3 / भाग-4

– रोजगार

Goal :- A-21 ⇒ सबके लिए गरिमायुक्त जीवन + liberty

(ध्येय)

↓

How

↓

उपभोग के लिए सामग्री मिले

Objective

- औद्योगीकरण
- उत्पादन ढांचे में परिवर्तन हो – कृषि ↓, सेवा ↑
- क्षेत्रीय विषमता ↓
- ~~बुनियादी~~ ढांचा ↓
- उत्पादन संवृद्धि ↓
- गरीबी + बेरोजगारी ↓
- कौशल + प्रौद्योगिकी स्तर ↑

प्राक्कथन : कथन से पहले वाला कथन।

प्रश्न → 250 शब्द
- → प्राक्कथन
- → कथन
- → निष्कर्ष (अपना विचार)

आलोचना

संतुलित निष्कर्ष

Ques भूमण्डलीकरण ने भारत वर्गहीन (2009) समाज की रचना के बजाये वर्गभेद की ओर बढ़ा दिया है।

जाति गरीब

↳ वर्गहीन समाज (वर्ग के आधार पर भेदभाव)

→ तर्कपूर्ण

कृषि ज्यादा — शहरी — ग्रामीण

अमीर — गरीब

आलोचनात्मक परीक्षण :

निष्कर्ष : संतुलित

आलोचना
↓
किसी वस्तु की सूक्ष्मता से परीक्षण / अवलोकन

समालोचना
↳ निष्पक्ष होकर अवलोकन करना।

आयोजन के प्रकार

1) आयो॰ के प्रकार
a) क्षेत्र
b) समय सीमा
c) संसाधन आकलन + आवंटन की ईकाई

I) क्षेत्रिय व्यापकता के आधार पर

1) राष्ट्रीय/विकासीयो॰ → Whole India, Ex:- 12th 5 yp
2) प्रांत विशेष → State level Plan; राज्यों का स्तर
3) स्थानीय आयोजन → जिला, तहसील, ग्राम

Shows → बहुस्तरीय
why → संविधान (7वी अनुसूची)
11 → स्थानीय ग्राम
12 → शहरी

II) समय सीमा के आधार पर

1) अल्पकालिक → वार्षिक
2) मध्यम कालीक → पंचवर्षीय/सप्तवर्षीय
3) दीर्घकालिक (दि॰ट) → दिशा बोधक → भारत में no समय सीमा

5yp को कार्यकुशला → हेतु

5yp ⇒ मूल्यांकन में उपयुक्त

उद्देश्य

5yp के आयोजन में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु दि॰ट का ...

उदा:- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 77 साल को पहले

राष्ट्रीय कृषि नीति

2003 - रा॰ S & T

2016 - 17

Ans 11 5yp का मूल्यांकन

III) संसाधन आकलन + आवंटन की ईकाई

भौतिक ↓

वित्त → मौद्रिक मूल्य

भारत में आयोजन भौतिक + वित्तीय का ~~समन्वय~~ समन्वय
(ग्रामीण क्रियाकलापों, शहरी)

4) अर्थ० में भाग

IV) अर्थ० में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर :-

केन्द्रीकृत प्लानिंग
(i) आर्थिक निर्णय
(ii) विशालकाय प्रशासनिक ढाँचे

आदेशात्मक / Imperative

- एक केन्द्रीय आयोजन निकाय (केआनि) जो सभी प्रकार के आर्थिक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होता है
- निर्णयन में अन्य किसी संस्था की भागीदारी नहीं।
- निर्णय में एक संस्था के एकाधिकार के कारण इसे केन्द्रीकृत P. भी कहते हैं।

केआनि के कार्य क्षे० — Policy

उदा :-
1951 — 91

- केआनि के निर्णयों (नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं etc) को लागू करने के लिए विशालकाय प्रशा० ढाँचा होता है।

(ii) भागीदारी / निर्देशात्मक / Directive

आर्थिक निर्णय
- केआनि होता है जो विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर व्यापक नीतियाँ बनाता है, लेकिन अंत में नीतिगत निर्णय के लिए विभिन्न विभागों में एवं विभिन्न स्तरों पर सक्रिय संस्थाओं को भागीदार बनाते हैं।
- निर्णय में सबकी भागीदारी के कारण, निर्देशात्मक आयोजन को भागीदारी P. भी कहते हैं
- ~~केआनि के कार्य~~

1991 — 2013

- पंचायत
- सहकारी संस्थाएँ
- ~~प्रांतों की भागीदारी~~

क्यों 1991 से हमने निर्देशात्मक नियोजन को अपनाया।

समन्वयकर लक्ष्य — (गैर लचीले लक्ष्य) — जिसके प्रत्येक अधिकरण को एक समयबद्ध लक्ष्य दिये जाते हैं।

दण्ड विधि — लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी प्रशा० संस्थाओं को मुख्यतः दण्ड विधि द्वारा सक्रिय रखा जाता है।

(उदा० कर्म मनोलिया)

पुरस्कार अधिकारी, प्राइज मनी, अवार्ड

iii) लघुकाय प्रशा० ढांचा — विभिन्न स्तरों पर बनायी गयी नीतियों/कार्य० के क्रियान्वयन हेतु एक लघुकाय प्रशा० ढांचा होता है। जिसे एक समयावधि में प्राप्त होने योग्य

iii) लचीले या सांकेतिक लक्ष्य — लचीले या सांकेतिक लक्ष्य दिये जाते हैं। तथा जिसकी प्राप्ति के लिए प्रशा० सक्रिय संस्थाओं

iv) पुरस्कार गाजर विधि — को मुख्यतः पुरस्कार विधि या गाजर विधि द्वारा सक्रिय रखा जाता है।

v) बाजार वितरण प्रणाली — (+)

- सक्रिय रखने की विधि अधिक कारगर
- Positive प्रयास
- उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए निजि संस्थाओं के समाज को सक्रिय रखा जाता है
- अर्थात् बाजार

vi) प्रशासित वितरण प्रणाली

vii) प्रशा० कीमतों पर

- उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को विभिन्न उपभोगता वर्गों तक पहुँचाने के लिए एक प्रशासित वितरण प्रणाली विकसित की जाती है। (PDS)

(निजि इकाइयों का संचालन नहीं)

- प्रशा० कीमतों पर वस्तुओं का वितरण।
- प्रशासित कीमत प्रणाली

(−) misuse

(VI) प्रभाव. के नियामक निगरानी — तथा इस० संस्थाएं बाजार की निगरानी करती हैं ⇒ (ताकि शोषण न हो) ⇓ निगरानी

(VII) → स्वतंत्रता — **Ques** क्यों नियामक सं० की संरचना post 1991 में बनी है

- देमानि की पूर्व मान्यता होती है कि दिन-प्रतिदिन के ज्यादातर मामले में विवेकशील चयन की क्षमता उपभोक्ता में होती है। इसलिए उन्हें उपभोग ढांचे की स्वतंत्रता दी जाती है। तथा उत्पादन ढांचे का विस्तार एवं विविधिकृत करके उप चयन के व्यापक विकल्प सुनिश्चित किये जाते हैं।

(VII) उपभोग ढांचा की स्वतंत्रता — देमानि की पूर्व मान्यता होती है कि उपभोक्ता

(VIII) ... विवेकशील नहीं होते हैं। और विवेकशील उपभोग ढांचे का चयन नहीं कर पाते हैं, इसलिए (Planing Commission) देमानि ही उपभोग ढांचे का निर्धारण कर देता है और उसी ढांचे के अनुसार उपभोग के सीमित विकल्प होते हैं इस० → कार

- आदेशात्मक आयोजन वहाँ जहाँ साम्यवाद क० लोकतंत्र

Ques लोकतंत्र + आदेशा० आयोजन साथ-साथ नहीं

भारत में शुरू से ही निर्देशात्मक आयोजन रहा है
⇓
70 → केन्द्रीय करण

Ans 1991 से पूर्व के आयोजन को आदेशात्मक कहना

नहीं → आलोच.

why
- सत्ता का केन्द्रीकरण
- स्थानीय स्तर पर आयोजन

(70.60%) + आयात प्रतिस्थापन नीति

स्तर कमजोर

(i) 1951 – 71 → केन्द्रीकरण ज्यादा नहीं

(5) लक्ष्य प्राप्ति के बुनियादी स्वा० के आधार पर

1) संरचनात्मक आयोजन

2) प्रकार्यात्मक आयोजन

में परिवर्तन

(सं० आयो०)	(प्रक० आयो०)
यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए वर्तमान घटक ढाँचे, उत्पादन की विधि, संसाधन स्वामित्व की संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन करने की नीति अपनायी जाये, तो ऐसे आ० को सं० आ० कहते हैं।	1) लक्ष्य प्राप्ति के लिए वर्तमान सं० ढा०, उत्पादन की विधि या संसा० स्वामित्व की संरचना में परिवर्तन के बजाय उनके बेहतर दोहन / इष्टतम दोहन की नीति अपनायी जाये
उदा० → भू सुधार में तीन चीजें	उदा० → हरित क्रांति है
(1) खेती योग्य जमीन के	–

(II) चकबंदी / हदबंदी (Land Ceiling)

→ Surplus की मात्रा को निश्चित करना
⇓
अधिशेष भूमि का अधिग्रहण

3) अधिशेष भूमि का भूमिहीनों में पुनःवितरण

कुछ विफल किन्तु केरल ⇒ सफल
गारंटी मुआवजा
मुख्य कमियाँ
D.M.

भारत में Land reform सफल नहीं bcoz निम्न ↓
Lack of political will

(III) भू-स्वामी एवं भूधारक संबंधों में गुणवत्ता के सुधार (टेनेंसी सुधार)
↓ बेदखल करने का भू-स्वामी के पास अधिकार नहीं

अंग्रेजों के समय
⇓
जमींदार
भूस्वामियों के अधिकार
शोषणकारी

(III) प्रति व्यक्ति भू-जोत का आकार कम होता जाता है। → भू-जोत का अविभाजन

अपखण्डन ⇒ चकबंदी
⇓
छोटा खण्डन
अधिखण्डन
⇓
अट्ठा खण्डन
(−) प्रभा
दक्षिण भारत

(−)
- भूमिहीनों की आय नहीं बढ़ेगी
- आ० विषमता ↑
- हरित क्रांति ⇒ क्षेत्रीय असमानता ↑

हरित क्रांति के अधिकतर आधारित आपूर्ति

(+)
- खाद्यान्न में खाद्य सुरक्षा
- समृद्धि

Overall संवृद्धि लाने but समावेशी नहीं।

Ques Inclusive growth के लिए which P. is best.

(+) i) मु० आयो० सफलता
१९० की गुणवत्ता।

(-)
व्यावहारिक
तरीका
राजनीतिक स्तर
पर लागू करना चुनौती

शब्द के अर्थ → अभिधा ×
→ लक्षण
→ व्यंजना

योजना आयोग

पदाधिकारी स्वरूप	1. अध्यक्ष 2) उपाध्यक्ष 3) सांसद – मनोनित	
गैर पदाधिकारी	जन प्रतिनिधि	नए उद्देश्यों की निगरानी
	विशेषज्ञ	अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, गणितज्ञ, प्रबंध विशेषज्ञ,

रणनीति / मॉडल :
संसाधन उपयोग के सिद्धांत maybe → गणितीय विधि
(तालमेल युक्त समुच्चय)

रणनीति :- किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों के उपयोग संबंधी तथा निवेश संबंधी परस्पर समंजित सिद्धांतों का समुच्चय रण० / नि० मॉडल कहलाता है।

12th 5yr के उद्देश्य ?

Ques :- बारहवी योजना की रणनीति का विवरण दें

उद्देश्य
↓
सिद्धांत → सामाजिक सिद्धांत (A-14)
↙ वितरण (i) आवरण को हटाये

अंगुल म.

परिचय → view देते हैं
100 (-) अपना
⇓ मत
विवरण 50 (+)

Ques 12th 5yp की रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए

50
⇓
विवरण

1952
फैमिली प्लानिंग
⇓
75 में भाग
⇓
1991 से

उद्योग सांख्यिकी कार्य काम को लागू करना

प्रक्रिया

मंत्री परिषद उद्देश्यों को निर्धारित करता है।
⇓ PMO भेजता है।
योजना आयोग के पास भेजा
उस रणनीति बनायी
प्रकाशित (दृष्टिकोण पत्र)
⇓
फिर मं० प० को भेजा
कैबिनेट में चर्चा, अनुमोदित
⇓
NDC की बैठक
⇓
... के बीच रखा जाता है
विपक्ष / NGO's / मीडिया

Phase (दृष्टिकोण पत्र पर सामाजिक संगठनों में चर्चा होती रहे)

if they ...

⇓ अंतिम उद्देश्य को पुनः निर्धारित
⇓
प्रारूप योजना
⇓
कैबिनेट
⇓
NDC

मंत्रि परि. →	योजना आयोग →	NDC →	तत्काल
उद्देश्यों का निर्धारण →	रणनीति पत्र →	अनुमोदन →	हाँ / नहीं
उद्देश्यों का पुनः निर्धारण →	प्रारूप योजना →	,,	↑ ↑ ↑ → दोहराई जाती नहीं
उद्देश्यों का परिमार्जन	अंतिम योजना →	NDC की बैठक *	

आधिनायकवादी

/ रूस व चीन के
जैसे जनता की राय नहीं

/ नाति
आधिकाशों का
संतुष्ट

भारत का नियोजन
हमेशा से ही लोकतांत्रिक
रहा है।

1951 – 1991

1951 – 2011 : 60 वर्ष (हॉरोड जयंती)

* उद्देश्य → मंत्री
आग → मंत्रियों +
जनता का सलाप

यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी
⇓ ⇓
वांछ ⇒ शासन अतः जनता
उसका शासन के जाये

+ प्रगतिशील निकर्ष

1 : पहले की योजनाओं की विशेषता

लगभग
○ सभी योजनाएँ रमोवेश महालनोबिस रणनीति पर आधारित थी।

(दल के अध्यक्ष / अनुयायी के तिल रम रमन)

⇓

सर्वोच्च वरीयता पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर b/o सम्पूर्ण आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार

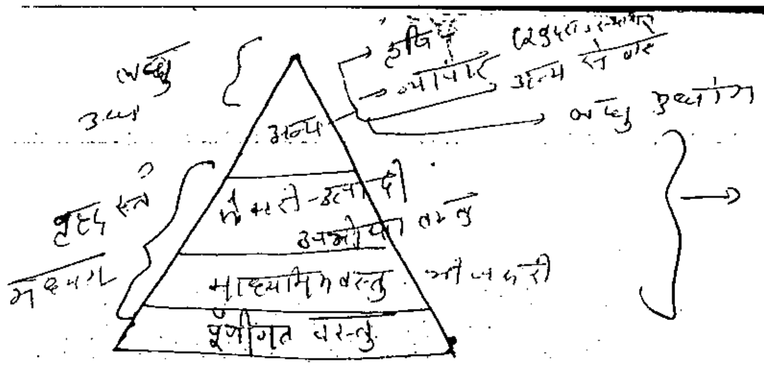

→ निवेश योग्य संसाधन का वितरण

(इस्पात, लोहा, कोयला, सीमेंट, ...)

why
bcoz पहली मे कृषि पर ध्यान
कृषि विकास हेतु उक्त चीजो की जरूरत

2nd 5yp में → कृषि को इग्नोर

56 से 91 में यही रणनीति अपनायी

1991
राव — मनमोहन मॉडल

1951

पूँजीगत (लोहा)
माध्यमिक वस्तु (स्टील)
उपभोक्ता वस्तु (कार) → bcoz यह बढ़ेगा तो माध्यमिक वस्तु की जरूरत →

परिवर्तन
- बदलता हुआ के
- सिद्धांत के हृदय के

पहले supply ⇓ माँग

now माँग ⇓ supply

आपूर्ति पक्षीय रणनीति

माँग पक्षीय रणनीति
bcoz Income ↑

जब लोग बाजार पर जायेंगे
⇓ उत्पादन

रोजगार ↓ → माँग

• पूँजीगहन रणनीति ना कि श्रम गहन

pop.

1951 → 1991
36 85

लगभग 50 करोड़ की वृद्धि

संस्कृति के हिसाब से

गाँधी → कृषि + लघु उद्योगों पर बल

Ques ??
क्या महा० मॉडल इंटरव्यू
अपनाना था

(−)
• होते उद्योगों पर बल बल
• चीन ने अपनाया
but वहाँ चीन में
60 लाख लोग
छोड़ा
• उद्योग ~~...~~ गई

(+)
माहौल बनाया
मजदूर ने
मितव्ययिता
हरित क्रांति
फायदा ही
continue

(चीन में स्थिति अलग)

ज्यादातर लोग श्रम में → माँग

श्रम का महत्व अपेक्षित रूप से ज्यादा होगा।

1991 — 2011
85 121

बेरोजगारी ↓ + गरीबी ↓

इससे उत्पादित बेरोजगारी + गरीबी के ~~...~~ लिए उपयोगी

दोनों पूरक → अच्छा फायदा

91 तक पूँजीगत वस्तुओं की संभावना का दोहन

होयुका था => किट्टो नहीं

ग्राहक ——> उपभोक्ता वस्तु को

बढ़ाना (1991)

फेल, CIC में बन गई

(ज्ञान को हटा इसको का सिद्धांत) महालनोबिस

- घरेलू उद्योग को विकसित करने हेतु 85 तक आयात प्रस्थापन की नीति आयात नियंत्रण की नीति अपनायी गयी

↓

मूल उद्योग को बढ़ाने का सिद्धांत

Ques क्या यह बंद दर्शन पर आधारित

Ques ऐ. क्या महा. रणनीति ने आ. का भरपाइयों का मिटाने के आंशिक भूमिका निभाई - 1947 समस्या रूप

पूँजीगत I ↓ ——! (—)

गरीबी ——> कम फायदा

क्षेत्रीय असंतुलन ——> देश के विभिन्न अंचलों में उद्योगों का विस्तरण बढ़ा | but पूर्ण स्थापना नहीं

91—2011

- आयात उदारीकरण + निर्यात प्रोत्साहन की नीति पर आधारित (why not in 60's → b/c no surplus) → b/c → उद्योग परिपक्व → surplus

Ques क्या यह खुले दर्शन पर आधारित

- स्वाभाविकता / प्रसार की दर

परमानेन्ट
सेटलमेन्ट

(+) (−)

1947
आवश्यकता को
स्तर

भारत-नेहरू
के दृष्टिकोण के
मदद

but
सार्वजनिक
नहीं
PSU's
के प्रगति
संदिग्धग्रस्त
कर रही

विषमता की
प्रवृत्ति में बदलाव
हुआ

• हरित : क्रांति का बदला
ज्यादा हालात
ज्यादा से ज्यादा
लोगों को मजदूरी
के कारण

इसी है जिन पेशों
में उसी को रहे हैं

अलवर्ती
इलाका का
पिछड़ा

उड़ीसा का
कलिंग इलाका
91 के बाद
पिछड़ापन

तटवर्ती
• निर्यात
के विकल्प
सीमित

• 91.5 लाइन की
निर्यात लॉकलाइन

Ind महात्मा गांधी मॉडल

(+)

• गाँव के लोगों
की मांग हालात
• शहरी - ग्रामीण विषमता ↓
• रोजगार ↑
• लोकतांत्रिक प्रगति
•

निष्कर्ष है

(−)

• पूंजीगत लाभ नहीं
• निर्यात नहीं हो
पाता
• पैसों के गुणात्मक कंवर्जन
नहीं हो पाता
रोजगार की गुणवत्ता
• राष्ट्र की मानव पूंजी
विकसित नहीं हो पाती
• सहायक नीति की विवाद

माओत्से तुंग applied in चीन (गाँधी वादी मॉडल)
↳ दबाव (अधिनायक तंत्र)

गाँधी : निर्माण
ग्राम : घर

(1991 का विवरण) ?

1991 का आर्थिक सुधार / New eco. policy

घटक

- स्थिरीकरण उपाय (Stablization Measure)
- संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment prog.)

why उक्त घटक

(i) तात्कालिक reason ?

(a) बाह्य असंतुलन ?

विनिमय दर के उच्चावचन

↳ bcoz of Trade Defi (GDP का 3%) → CAD 3.1%

↳ सेवा Trade Defi (0.1%)

($ Expand)

S < D

↳ CAD

↳ रु कमजोर ↓

↳ विदेशी मुद्रा भंडार : $ 1 अरब ↓ (अनाज का कच्चे का आयात बिल ...)

(1 के 3 b का आयात)

(b) आंतरिक कारण

कीमत उच्चावचन (महँगाई)

bcoz (I) माँग ↑

(i) bcoz of pop

(ii) सरकारी व्यय एवं (राजकोषीय घाटा) (8.6%)

⇓

रा० घा० की पूर्ति हेतु मुद्रा आपूर्ति की दर तेज की

89 → 91

मुद्रा आपूर्ति — 17% बढ़ी

मॉनटिक

(प्रश्न) आपूर्ति में अपेक्षित जड़ता (S = 6%, D = 8%)

① आपूर्ति में जड़ता के कई कारण थे —
देश में व्यापक लाइसेंसिंग नीति लगाई गई थी, इसलिए क्षमता का विस्तार, नई संयंत्र की स्थापना करना मुश्किल हो गया।
निजी इकाइयों में लालफीताशाही

② देश के सभी वित्तीय संस्थान पर सरकार का नियंत्रण था, तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण का ब्याज बहुत ऊँची थी। → मुनाफा ↓ निवेश ↓

③ करों की दरों को भी काफी ऊँचा रखा गया था।
लागत ऊँची → महँगी →
10 + 7 ⇒
कर आंकलन की पद्धति गलत कर का भार बढ़ता जाता था →
लागत 10, कर 17 ... 17 ही था
(मुनाफा घटता) — बढ़ी लागत 10 17

④ कारोबार का विनियमन करने वाले कानून एवं प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बनाकर रखा गया एवं आम कारोबारी उतना बोझ सहन नहीं पाते थे
(उदासीनता कमजोर)

Que 1991 के आर्थिक संकट का परीक्षण कीजिए

स्थिरीकरण (SM)

1) विनिमय दर स्थापित

(3) रुपये का अवमूल्यन किया गया।

(2) IMF से ऋण → अनुरक्षा के वातावरण को कम

2) कीमत स्थिरीकरण

- सरकार ने व्यय कम किया
- रा० घाटे को 6.6% किया
- RBI को नोट कम छापने (मुद्रा आपूर्ति↓)

आज भी 1991 की तरह CAD↑ है।

संरचनात्मक adjustment

Que पहली पीढ़ी का सुधार (Ist Gen.)

(1991 – 1996)

चार दिशाओं में सुधार

1. औद्योगिक
2. केंद्रीय राजकोषीय सुधार
3. वित्तीय सुधार
4. व्यापारिक सुधार (विदेश व्यापार)

IInd Gen. 1996 – 2013

सुधार का गहनीकरण

सुधार का विस्तारीकरण।

Ques:- नवोत्पाद से आप क्या समझते हैं कि (1995)

(2007)

(2012)

नवाचार क्या है

diff b/w आदेशात्मक ~~hfw~~ निदेशात्मक म०

गहनीकरण :- 91 से शुरू किये गये सुधार कार्य को जारी रखते हुए निम्नतर स्तर की संस्थाओं को सुधार की प्रक्रिया में शामिल करने को सुधार का गहनी० कहते हैं

औद्योगिक सुधार

Ist

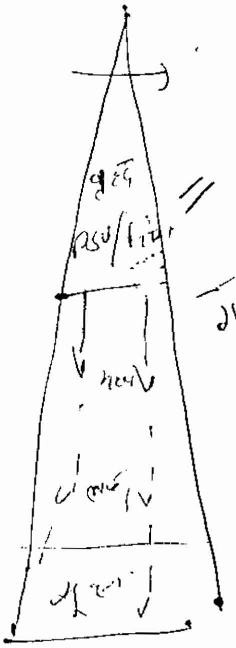

IInd

वृहद PSU/निजि के सुधार पर बल

गहनीकरण

\+ सूक्ष्म, मध्यम

\+

लघु पर भी ध्यान देना है

प्रशासनीय सुधार — वित्तीय सुधार

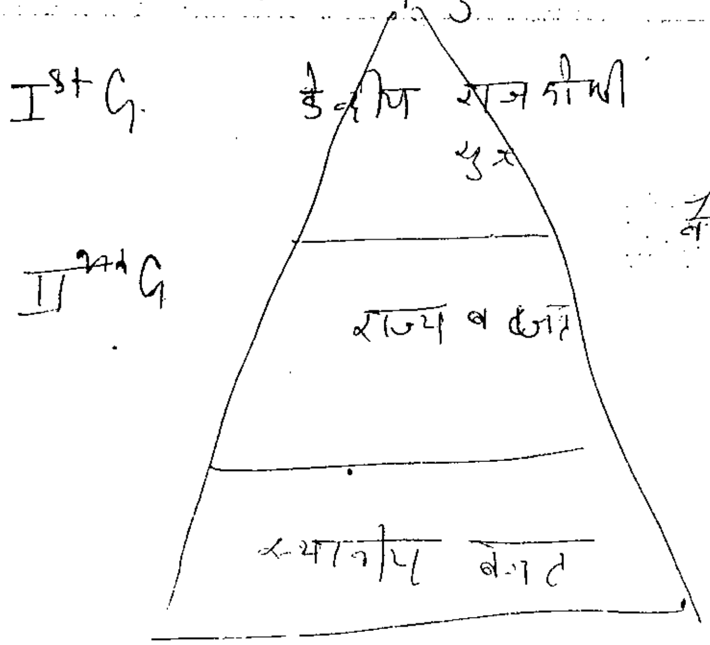

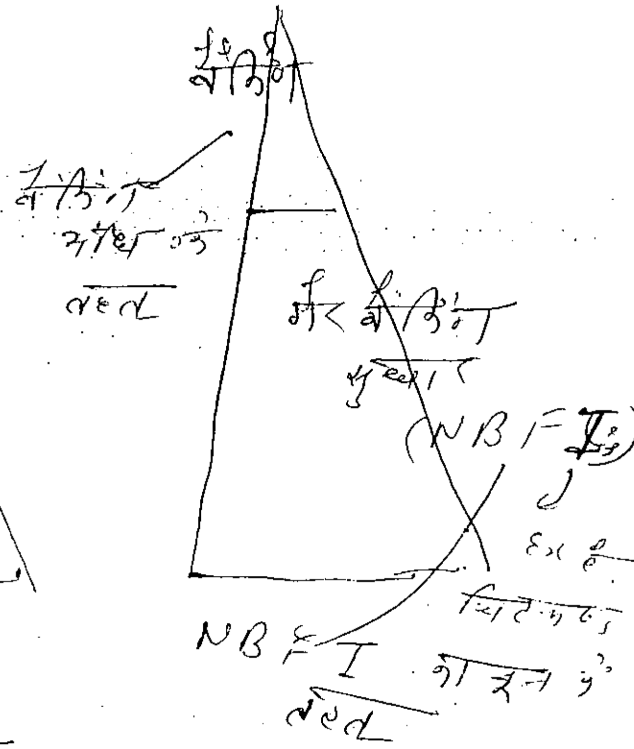

व्यापारिक सुधार

foreign trade — I st → विदेश व्यापार

II nd — घरेलू ⇒ प्रभाव (आंतरिक व्यापारिक का ...)

⇓

M Brand Retail में FDI

Backward linkage पर बल

Ques है भारत सरकार (1991) क्यों अपना रही है। इसको — II nd G (1991)

Ques देश के कुछ वर्गों में विरोध क्यों हो रहा है।

सुधार का विस्तारीकरण :- I G. R. के दौरान जिन क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम नहीं शुरू किये गये थे। उनके लिए भी सुधार कार्य भी शुरू मात्र को सुः का विस्तारी० कहते है।

तीन क्षेत्र

कृषि क्षेत्र (1996)

↓ बुनियादी ढाँचा क्षेत्र का सुधार

→ श्रम बाजार का सुधार

Ques दूसरी पीढी के सुधार के अंत क्या समझते है

Ques ~~पिछले~~ दो दशक के अ० सुधार का विवरण दे?

I G R

(+)

• समय से पूरा।

bcoz PSU, विनिवेश, विदेशी व्यापार, ABGO

• राज्यों की सहभागिता

ASMAT की मान्यता

II^nd G R

(−)

• अभी तक नही

Ques इसमें क्यों सड़चनें आ रही हैं, जबकि पहली पीढी का सुधार एक तबदुद्दा अवस्था में लागू हो पाया था

नही थी। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों में भी आपसी मतभेद नही था। ∴ निर्णय त्वरित रूप से लिये गये व क्रियान्वयन भी जल्दी। 2nd IIGR

है नाव क्षेत्र 81 से FDI

मे ज्यादातर मुद्दे राज्य / समवर्ती सूची के विषय हैं।
राज्य की अनुमति के बगैर कार्यक्रमो को अनुमोदन संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पायेगी। कुछ

क्षेत्रीय विषमता ॥ — राज्यों मे सहमति भी है, वहाँ दूसरी पीढ़ी का सुधार लागू हो रहा है। कई s. विरोध वहाँ P. अवरुद्ध है।

- कुछ s मे राजनीतिक अनिश्चितता है (+) या (-) निर्णय नही

II) - 96-99 के बीच केन्द्र सरकार के गठन मे अस्थिरता थी। इसलिए घोषणा के बावजूद शुरू 2000 से शुरू हो पाये।

III) s. मे निर्णय की गुणवत्ता मे समरूपता नही।

Ques. आर्थिक उदारीकरण 91 मे ही क्यो शुरू हुआ

- शुरू → 81 मे जब सरकार ने वाहन + इलेक्ट्रॉनिक मे लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। FDI
- 83 मे स्वास्थ्य क्षेत्र के लाइसेंस समाप्त निजी अस्पताल स्थापना की अनुमति दी
  83 में अपोलो

- 85 में NRI द्वारा किये गये निवेश का उदारीकरण किया।
- 86 में प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु विदेशी संस्थान के तृ० आधार स्वतःगठजोड़ के मानकों का उदारीकरण किया।
- 86 में शिक्षा क्षे० में निजि नि० को पहले से और अधिक उदार बनाया।
- संचार क्षेत्र में भी नीतिगत उदारीकरण किया
- स्थानीय की सक्रियता नहीं
  (दूरसंचार विभाग का 80 में ...)

परन्तु 91 तक उदा० की प्रक्रिया व्यापक नहीं विशिष्ट क्षेत्रों के लिए थी व इदा० का समन्वय कार्य० नहीं बनाया गया। 91 का उदारीकरण इस अर्थ में नया था कि यह एक समन्वय कार्यक्रम के तहत लागू हुआ। ● लगभग सभी क्षेत्रों के लिए लागू हुआ।

उदारीकरण का प्रभाव
- उत्पादन ↑ वृद्धि दर

- Delicensing
- लाइसेन्स भी व्यवस्था को कम किया गया।
- Dereservation

पूर्व 91 उदा० के परिणाम
(+)
- उत्पादन उत्पादन दर ↑
- उपभोक्ता की संख्या बढ़ी
- टी. वी की मात्रा बढ़ी
- निजि भागी० को फायदा
- उच्च आय वर्ग निजी क्षेत्र को और ला गया
- लीला-नीतशाही से मुक्ति

आपूर्ति S ↑ ⟹ महँगाई ↓ 9 ↓ ⟹ bcoz D < S

16% — 1.2% — 2001 →

85 – 90 ⟹ 7 5 y P ⟹ AGR 5.6%

92 – 97 — 8 5 yr. ⟹ 6.8%

~~अधिकतम~~ P, अस्थिरता — 97 – 2000 — 9 5 yP ⟹ 5.6%

सुधार कार्य धीमे ⟹ GDP ↓

सुधार शुरू — 2000 — 95 y

2002 – 07 — 105 y ⟹ 7.8%

7 – 12 — 115 y — 7.9%

b o Z 2000 से सुधार को गति तेज

वैश्विक मंदी के बावजूद सुधार कार्य के कारण

— गरीब हैं (करोड़)

1973	93	2013
32 (55%)	32.1 (36.7%)	27 (25%)

Shares → बढ़ते उत्पादन का कुछ फायदा गरीबों तक पहुँचता है।

मूल्यांकन का पैमाना ⇒ समावेशी वृद्धि

(+) 91 तक है अध्ययन
↳ पूँजीगत
↳ बुनियाद

नवाचार :
↳ नये विचारों को आचरण में अपनाने की प्रक्रिया

Ques : भारतीय अर्थ. में लोक उपक्रमों की प्रासंगिकता है

2004

1991 लोक उपक्रम सुधार
→ विनिवेश
⇓
(सरकार ने अपनी पूँजी निकालनी शुरू
from लोक उपक्रम निवेश
↳ why सरकारी पैसा फँसाना
+ Depoliticize

2004 → बोर्ड for Restructuring of PSU

⇓
100% → सभी निर्णय of कि. कर्म by सरकार
⇓
सरकार

⇓
80% → 26% विनिवेश
सरकार अब 26 की चुनी जायेगी

Depoliticize
विनिवेश (लोक उप. की
कामगारों को शेयर
⇓
but यह समाप्त नहीं रहा

1991-2004 तक यह प्रक्रिया चली (+)

लोक उपक्रम सुधार (1991)
के मार्गदर्शन हेतु B RPS
कार्य
↳ कमजोर (weak) } PSU's
↳ रुग्ण (sick)

के ~~लिए~~ पुनर्गठन + पुनर्उद्धार के लिए
सरकार को सिफारिश है।

आज भी प्रासंगिक वस्तुएँ बना सके — प्रौ० — पुनर्गठन — वित्तीय, प्रबन्धकीय, ~~प्रबन्धकीय~~

वित्तीय आधार को मजबूत

Ques BRPSU की प्रासंगिकता क्या है। नई भूमिका

↳ विनिवेश की रणनीति

- विनिवेश (Disinvestment). Yes / No ↓ पुनः पूंजीकरण
- पुनः पूंजीकरण (Recapitalization) → यह वहाँ जहाँ प्रबन्धन की गुणवत्ता / सौदेबाजी but वित्त के अभाव या प्रौ० के पुराने हो जाने के कारण वह कमजोर है।

1. यदि कमजोरी का कारण प्रबन्धकीय दोष ✓

कहीं-कहीं दोनों करना पड़ सकता है where as आंशिक कारण

both → आंशिक कुशलता कुछ कम
→ वित्तीय।

विनिवेश → फुल पैसे → पुनः उन्हीं PSU में

Ques आज भी अर्थव्यवस्था - समाज में लोक उपक्रम की क्यों प्रासंगिकता है?

1948

औ० नीति संकल्प
Industrial Policy Resolution

- औद्यो० मदों का वर्गीकरण किया जायेगा
- विकेन्द्रीकृत नीति होगी

(क) तीन उद्योगों पर केन्द्र सरकार का एकाधिकार — रक्षा, परमाणु, रेल, डाक, कुर्जा

निजीकरण के उत्पादन में निजी क्षेत्र का % बढ़ाना

(ख) 6 उद्योग के विकास का दायित्व सरकार (S+C) but जरूरत पड़ने पर नि० क्षेत्र भी शामिल

(ग) शेष उद्योग → आवंटन — निजी संस्थाएँ करेंगी, But कभी सरकार भी उपक्रम लगा सकती

aim

(1) तीव्र गति औद्योगीकरण

2) लघु उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जायेगा b/c रोजगार

(3) औद्यो० क्षे० को गति प्रदान

1956

1 IPR — पुनः वर्गीकरण (3) अनुसूची — (निजि क्षेत्र के बीच) राज्य/सरकार का सामान्य स्वाधिकार

क → 17
ख — 12 → निजि + सार्व. दोनों → (स्वामुचित नियम)
ग — शेष

(2) भविष्य के यदि निजि C. आवश्यकता तो उन्हें संक्रमित किया जाता था

(2) प्रशिक्षित कामगार ↑
- UGC एक्ट 55/56
- IIT ↑

बुनियादी ढाँचा उद्योग
(1) कोयला
(2) लोहा इस्पात
(3) सीमेंट
(4) बिजली उत्पादन
(5) कच्चा पेट्रो० तेल
(6) तेल परिशोधन

- रसायन
- IIT ↑
- IIM ↑

(3) लघु उद्योग
(4) FDI के पुरानी नीति जारी रहेगी

1991 ⇒ (कुछ मामले में पूर्व की)

IPR नीतियों की Continuity

१५% सब्सिडी, वाको? २२

FDI को भी अनुमति दी (विदेशी संस्थाओं को आकर्षित किया)

1977, 77, 88 में 5(?) नीति में संशोधन

70 + 77 में अंकुश लगाया।

81 में क्या उदारीकरण की नकारात्मक

DCO 70 + 77 में कठोर लागू

~~नाप~~ 70 में व्यापक आशंकाएं

70's में FDI नीति को उलट दिया।

Ques भारत के लिए नीति [illegible]

ज्ञान [illegible] नहीं रहे।

सभी दबाव के लिए BRPSU जारी

PSU व्यापार, आउटसोर्सिंग, [illegible] BSNL पर दबाव

निजी कंपनियों, सेवा, कार्यकुशलता

11वीं था 12वीं योजना के उद्देश्य

	11वीं	12वीं
1)	तीव्र आ० संवृद्धि	तीव्रतर आ० संवृद्धि
2)	समावेशी संवृद्धि	अधिक स० संवृद्धि
3)	धारणीय विकास	आ० धारणीय विकास

(उत्पादकतापूर्ण नहीं)

आर्थिक संवृद्धि का मापक है —

-> GDP में वृद्धि
-> रोजगार के सामाजिक आधार को व्यापक बनाना होता है। विशेषकर अब तक वंचित सामाजिक समूह के पक्ष में

(Same वर्ग को नहीं, बल्कि ऐसे को पहले से)

Joy धारणीय विकास
-> सामाजिक धारणीयता
-> राजनीतिक धारणीयता
-> सांस्कृतिक धार०
-> आ० धार०
-> पर्यावरणीय धार०

=> रणनीति ऐसी जिसमें पाँचों का समन्वय हो

आर्थिक लेखांकन
-> सूक्ष्म/व्यष्टि स्तरीय आ० लेखांकन
-> व्यापक/समष्टि " "

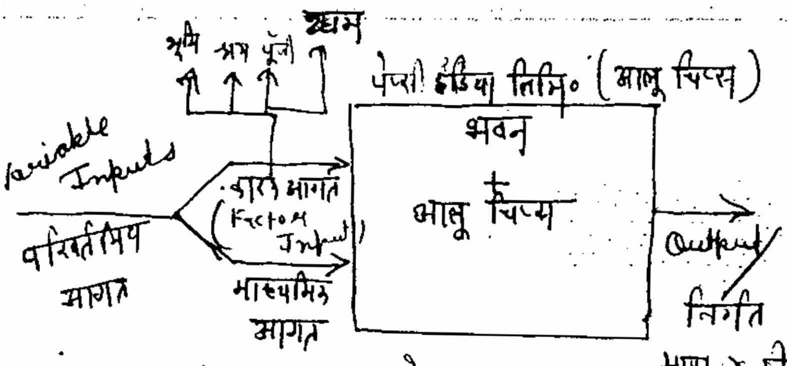

1. आलू, मसाले
2. ईंधन
3. पानी
4. संचार
5. पब्लिसिटी
6. पैकेजिंग
7. विज्ञापन
8. अन्य

मात्रा × कीमत = कुल प्राप्ति / कुल विक्रय / टर्न ओवर / टॉप लाइन

1000 ₹10 = 1000

कुल प्राप्ति का वितरण

(1) $TR - IC = GVA_{MP}$
1000 400 600

(2) $GVA_{MP} - NIT = 480$
600 120 GVA_{FC} 480

(3) $GVA_{FC} - D.A.$ 380
480 100 NVA_{FC}

$GDP_{MP} = \sum GVA_{MP}$

(सभी संस्थाएं)

$GDP_{FC} = \sum GVA_{FC}$

$NDP_{FC} = \sum NVA_{FC}$

सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1) स्थिर आगत (Fixed Inputs) :- किसी उत्पादन इकाई में उपयोग किये जाने वाले ऐसे संसाधन, जिनकी मात्रा एक लेखावर्ष के दौरान स्थिर रहे, चाहे उत्पादन अर्थात निर्गत की मात्रा में कितना भी परिवर्तन हो, स्थिर आगत कहलाते हैं। उदा :- भवन / मशीनें / खेत / किराये

- स्थिर आगतों की वार्षिक लागत को स्थिर लागत कहते हैं।

2) परिवर्तनशील आगत :- किसी उत्पादन इकाई में उपयोग किये जाने वाले ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा एक लेखावर्ष के दौरान उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तनीय हो, परि० आ० कहलाती हैं।

- इन्हें दो वर्गों में बाँटते हैं

(i) कारक आगत - भू०, श्रम, पूँजी एवं उद्यम की सेवायें

(ii) माध्यमिक आगत :- अन्य उत्पादकों से या व्यापारियों से भिन्न उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदकर उत्पादन में पुनः उपयोग किया जाये। तथा जिनकी आयु एक वर्ष से कम हो।

- दोनों प्रकार के परिवर्तन आगतों को परि० लागत कहते हैं → Factor C. (श्रम)
→ Intermediate C. (स्थायी)

- कुल लागत = स्थिर ला० + परिवर्त० ला०

कुल लागत में वृद्धि का एक मात्र कारण परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती है। ✓

- सीमांत लागत है कुल लागत में होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत है। गणना प्रति इकाई में।

Que है कृषक की कुल लागत में परिवर्तन → स्थिर लागत ↑, ट्रैक्टर ↑ ⇓ Shows क्षमता विस्तार

उत्पादकता ⇒ स्थिर लागत, परि. लागत ↑

पारि → - टर्न ओवर → उत्पादन (बिक्री)

उत्पादन की क्रिया (Input) → (Output)

क्रिया

- GVAMP (Gross value addition at market Price) है

समूह वाही

बाजार कीमत पर सकल मूल्य संवर्द्धन है

देश के कुल उत्पादन में कृषि की विशेष उत्पादन इकाई की भूमिका/अंशदान के मौद्रिक मूल्य को GVAMP कहते हैं।

- व्यष्टि स्तर पर उत्पादन मूल्य को मूल्य वर्द्धन कहते हैं। जबकि समष्टि स्तर पर उत्पादन को घरेलू उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर GDP कहते हैं। अर्थात

प्रांत के स्तर पर उत्पादन के समस्त मूल्य को SDP कहते हैं।

[illegible] कहते हैं।

प्रखण्ड → प्रखण्ड घरेलू उत्पाद
वैश्विक → W D P

NIT ⇒ NET Indirect Tax ⇒
(निवल परोक्ष कर) ⇒
~~शुद्ध अप्रत्यक्ष कर~~ ×

NIT = GIT − Producer Subsidy
(सकल परोक्ष कर) (उत्पादक राज सहायता)

GIT = TIT − Adm Cost
(कुल परोक्ष कर) − (प्रशासनिक लागत)

- विभिन्न प्रकार के परोक्ष करों के माध्यम से वसूली गई कुल मुद्रा राशि को TIT कहते हैं ⇒ ₹ 150
- कर वसूली की प्रक्रिया में प्रशासनिक विभागों पर होने वाले व्यय को कर वसूली लागत / Adm. C. कहते हैं = 150 − 10 ⇒ 140
- GIT → संचित निधि में प्राप्त होने वाली राशि
- GIT में से जनकल्याण को राजसहायता के रूप में ⇒ 20
- NIT ⇒ सरकारी आय के लिए

GVAFC ⇒ (Gross value addition at factor cost) :-

कारक लागत / उपादान लागत पर आधारित सकल मूल्य वर्धन

D.A ⇒ (Depreciations)
(मूल्यह्रास भत्ता) / स्थिर पूँजी का उपभोग

उत्पादन कार्य के कारण स्थिर आगतों की क्षमता में होने वाली गिरावट के मौद्रिक मूल्य को D.A. कहते हैं।

- उत्पादन को धारणीय बनाये रखने के लिए स्थिर पूँजी की नियमित मरम्मत करानी होती है। मरम्मत के वार्षिक लागत को तथा ~~किस्त को~~ भविष्य में स्थिर पूँजी के नवीकरण हेतु वांछित राशि के वार्षिक अंश को सम्मिलित रूप से D.A. कहते हैं।

मरम्मत लागत + वार्षिक चंदा = D.A

आर्थिक धारणीयता बनाये रखने के लिए सभी उत्पादकों को मूल्य ह्रास A. का आवंटन करना चाहिए

भविष्य

कृषि क्षेत्र में ↓ ⇒ उत्पादन धारणीयता ↓

(अर्थात् भूमि अपरदन bcoz of उत्पादन गति)

... समझोते

इस हेतु कैंजा के कृषि की धारणीयता होते जायेंगे।

11वी + 12वी में कृषि की धारणीयता पर बल
∴ Soil Cons + परंपरागत जल स्त्रोत पर बल।

Que:- पर्यावरणीय ~~धारणीय~~ ~~लाभ~~

आ० विकास के साथ पर्या० धारणीयता की चिंता व्यवस्थित रूप से 1972 से शुरु हुई। जब ~~~~ UNO ने पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया। स्टॉकहोम सम्मेलन :-
"प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा → 73 से लागू
वन्यजीव संरक्षण अधि ⇒ इसके पश्चात कई wild life Century ⇒ SC ⇒ आदिवासी + जनजाति समाज के अधिकार को कम कर दिया।
72 के बाद → असंतोष ↑ b'coz वे पारंपरिक अधिकारों से वंचित। ⇒ मांग जनअसंतोष ↑
2007 - 2006 में कानून में संशोधन कर लघु वनोपज पर वनवासी जनसंख्या के अधिकारों को पुनः स्थापित किया। → (लकड़ी काटने का अधिकार नहीं + bud रहा का नहीं)
1992 में अर्थ सम्मिट हुआ तथा यह तय हुआ कि (आ० क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का व्यवस्थित मूल्यांकन को शुरू किया जाये, जिसे हरित लेखांकन कहते हैं।

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मौद्रिक मूल्य

92 से हरित लेखांकन का सिलसिला शुरु

GDP_MP — हरित भत्ता — Green GDP
₹ 100 लाख करोड़ ₹ 5 लाख करोड़ 95 लाख करोड़ रुपये

- सकल घरेलू उत्पादन में से पर्यावरणीय रख रखाव लागत अर्थात् हरित भत्ता घटाने के बाद शेष सकल घरेलू P. को हरित सकल घरेलू कहते हैं

$GDP_{MP} - NIT = GDP_{FC}$

राष्ट्रीय आय — पर्यावरण भत्ता ⇒ हरित राष्ट्रीय आय

ग्रीन GDP :- पर्यावरणीय धारणीयता बनाये रखते हुए GDP या राष्ट्रीय आय के मूल्य को हरित GDP या GNI कहते हैं।

हरित लेखांकन ~~के क्षेत्र में~~ भी विश्व में ~~एक~~ रूपता विकसित करने हेतु क्योटो सम्मेलन 1997 हुआ। जहाँ दुनिया के विशेषज्ञों ने मिलजुलकर साफ सुथरी विकास क्रियाविधि (Clean Development Mechanism) विकसित की और विश्व देशों में अनौपचारिक अनुबंध हुआ, कि स्वच्छ क्रियाविधि को प्रोत्साहित करेंगे

1992 में तय हुआ था कि 90 में रवाडी 1990 से पहले विश्व में जितना भी प्रदूषण था, उसकी मात्रा को 2013 तक आधा (50%) करना है क्यो० प्रोटो० उसी लक्ष्य प्राप्ति का वैश्विक प्रयास था। ~~कई देशों~~

कई देशों ने CDM को अपने देश में प्रोत्साहित नहीं किया। भारत ने किया। but कईयो के नहीं करने के कारण प्रदूषण में अपेक्षित कमी नहीं

⇓

2007 में बाली (UNFCCC) में सम्मेलन हुआ। जलवायु के संरक्षण को विशेष रूप से बल

09 - कोपेन, 10 ⇒ कानकुन, 11 ⇒ डरबन

12 ⇒ रियो

72 — 12 = 60

क्लीन डवलपमेन्ट मैकेनिज्म का आ॰ पहलू

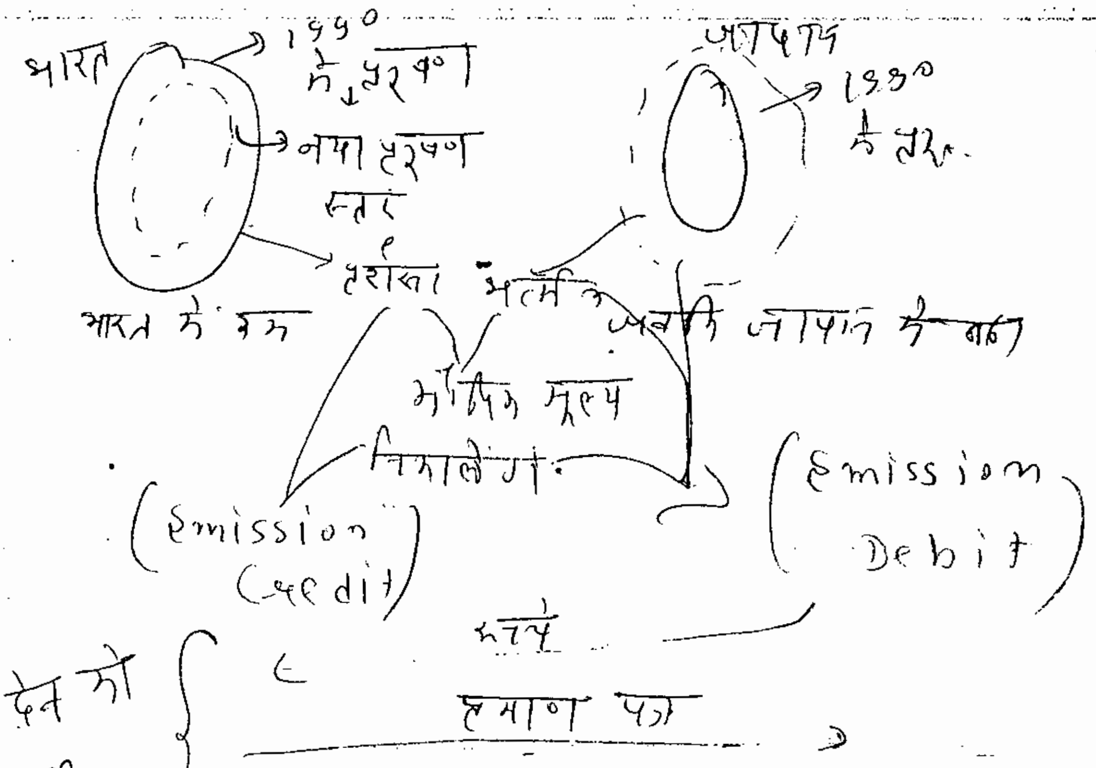

इस लेन देन को Emission ट्रेडिंग कहते हैं

प्रदूषणकारी एवं प्रदूषण निवारक संस्थाओं / देशों के बीच होने वाले प्रमाणपत्रों एवं धन राशि के लेन देन को Emission trading (उत्सर्जन व्यापार) कहते हैं।

⇓ विशिष्ट नाम

कार्बन ट्रेडिंग ⇒

+ क्योटो प्रोटोकाल की महत्वाकांक्षा की अन्य उपलब्धियों में भी ट्रेडिंग है

Pollution ↓ ⇒ Credit ↑ ⇒ TR ↑

हरित भत्ता का मूल उद्देश्य पर्यावरण में होने वाले क्षरण (b/c of आ० क्रिया०) का संस्थागत रूप से सुधार होना है। ⇒ सभी ऐसा करते हैं तो (हरित निधि) का विकास।

ग्रीन जॉब्स ⇓ नवीन निवेश

हरित निधि → use → हरित भवन, Soil Cons. Prog. ; water treatment Prog. (R, U) ; हरित ऊर्जा उत्पादन, low उत्पादन ⇓ सब्सिडी ; हरा उर्वरक

हरित दण्ड शुल्क ⇓ मान्य स्तर से + प्रदूषण

- मान्य स्तर से कम प्रदूषण ⇒
- → हरित जागरूकता ⇒ माँग पक्ष को प्रभावित
- ध्वनि प्रदूषण

हरित निधि → जिला → राज्य → राष्ट्रीय → वैश्विक (World G. F.)

National Green Tribunal है
↳ Nat. Green Policy पर काम कर रहा है

भारत में औसत मजदूरी बढ़ती जा रही है ⇓ मुनाफा ↓ ⇓ निवेश।

NVAFC	मजदूरी	G.O.S.
पहले 380	120	260

(सकल प्रचालन (operating) आधिक्य)

G.O.S. − (लगान + ब्याज) = सकल लाभ / कर पूर्व लाभ

260 − 100 = 160

(b/c अब निगम भी कर लगाया जाता है)

एक फर्म द्वारा अर्जित सकल लाभ पर लगाये गये कर =

GP → CIT ⇒ निवल लाभ / करोपरांत लाभ

160 — 60   100

कंपनी का कोटेच लाभ

- C. विधेयक द्वारा ~~[illegible]~~ CIT से कमी की बात कही गयी है।

(C. को प्रभावित करने वाले कानूनों का सरलीकरण)

<u>श्रम बाजार में सुधार</u> :

उत्पादन इकाई / विनिर्माण इकाई

125 yp ⇒ 10%

need विनिर्माण इकाई ↑ → ∴ निवेश को बढ़ाना होगा

[वितरणीय लाभ राशि पर लगाये गये कर को लाभांश वितरण कर कहते हैं। (Dividend Distribution Tax)]

- निवल लाभ → शेयरधारकों (50%) को वितरित लाभ } → वितरित लाभ
  → C. के भविष्य हेतु

अवितरित निवल लाभ जो

जाता → अतिरिक्त लाभ कहते हैं

⇓

इसे C. को आरक्षित निधि में रखता जाता है

इस राशि को corporate saving / अवितरित लाभ भी कहते हैं।

⇒ निवल लाभ का 2% for **CSR**

Q. CSR → (+)
      → (−)

aim of CSR :- प्रत्यक्ष उद्देश्य :-

समाज के विभिन्न वर्गों की E-S समस्याओं को कम करने का दायित्व सिर्फ सरकार पर ना हो, C. भी उसमें साझीदार बने। (P-P-P दर्शन)

E-S समस्याएं → बेरोजगारी ⇓ कौशल का अभाव

CSR →
- शिक्षण - प्रशिक्षण → कौशल विकास का Prog.
- पर्यावरण संरक्षण भत्ता
- बाग, स्वच्छता
- सामु० महत्व के बुनियादी ढांचा संस्थापन
- हरित तकनीकों के प्रोत्साहन हेतु निवेश

Qus प्रस्तावित विचार :- न्यासी के संदर्भ में गांधी दर्शन के आ० टिप्पणी

गांधी :- धनियों को समाज का न्यासी मानना चाहिए
(स्नातन न्यासी = सन्यासी)

आरक्षित निधि की प्रासंगिकता :-

आकस्मिक रूप से या अनायास रूप से उत्पादन संस्था की स्थिर पूंजी को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति में आ० नि० का उपयोग किया जाता है।

आपदा :- आकस्मिक रूप से विपदा → प्राकृतिक, मानव जनित, उदाहरणार्थ

Qus :- मूल्यह्रास निधि एवं आरक्षित निधि को अलग-अलग क्यों रखा जाता।

- स्थिर पूंजी में होने वाली क्षति को मूल्यह्रास कहते हैं। जिसके लिए क० पू० नि० होता है (निर्धारित + प्रत्याशित क्षति)

जबकि आकस्मिक क्षतिपूर्ति - कदा होती है।
उसकी लागत बड़ी होती है

कारोबार की रणनीतियाँ (Investment Models)

विक्रय महत्तमीकरण (Sales Maximisation)
↓
टॉप लाइन रणनीति
उद्देश्य: अल्पकाल में लाभ बढ़ाने पर बल ना देकर बिक्री बढ़ाने पर बल

लागत न्यूनीकरण (Coast Minimisation)
↓
बॉटम लाईन रणनीति
(अल्पकाल में लाभ हेतु Coast ↓ पर बल)

लाभ = कुल प्राप्ति ↑ − कुल लागत ↓

ग्राहक को भगवान, उत्पाद की गुणवत्ता
सूचना परक विज्ञापन

IC ↓
NIT ↓
DA ↓
मजदूरी ↓
ब्याज ↓
CIT ↓

लागत के निर्धारक को कम करने का प्रयास

निजि लाभ
अन्य के लाभ
(−)
i) इन्स्पेक्टर राज का उल्लंघन
ii) no quality ...
iii) भ्रामक प्रचार

12th 5YP में top line approach के प्रोत्साहन पर बल

- प्रौद्योगिकीय सुधार ↑
- नवाचार
- कौशल में सुधार
- On the Job training (कार्य के साथ ट्रेनिंग)

- उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान

स्तर के संदर्भ में

Indirect & Implicit सब्सिडी है

प्रति हेक्टेयर अनाज

प्रति श्रमिक

प्रति वर्ष

भौतिक तीव्रता

मात्रा × P ↑

उत्पादकता दो प्रकार

भौतिक है — प्रति हेक्टेयर उत्पादन (अनाज)

राजस्व है — बाजार में बेचने पर जो राशि प्राप्त प्रति Sale

MSP ↑ ⇒ राजस्व उत्पादकता ↑ ⇒ भौतिक उत्पादकता

भौतिक उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने वाले उपाय अधिक धारणीय। कीमत बढ़ाने से भी उत्पादकता बढ़ सकती है। but धारणीय नहीं।

12th 5YP की रणनीति :-

1) संसाधन / उपयोग / निवेश की मात्रा — उत्पादकता

⇒ लक्षित G. R. (8%) depend on

- निवेश (सकल घरेलू निवेश) GDI
- निवेश की उत्पादकता ($\frac{1}{ICOR}$)

$$GR \Rightarrow GDI \times \frac{1}{ICOR}$$

Incremental Capital Output Ratio :-

(वर्द्धमान पूँजी उत्पाद अनुपात) :-

उत्पादन की मात्रा में इकाई वृद्धि के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूँजी के आनुपातिक मूल्य को ICOR कहते हैं।

किसी वर्ष विशेष का GDI

$$ICOR = \frac{\Delta C}{\Delta O}$$

Ex उ = 100 करोड़
रु = 20 करोड़

$\frac{5 \text{ करोड़}}{1 \text{ करोड़}} = 5$

$\frac{4 \text{ करोड़}}{1 \text{ करोड़}} = 4$

– ICOR का निम्नतर मूल्य निवेश की उच्चतर उत्पादकता का सूचक होता है।

ICOR उत्पादकता के प्रतिलोम मूल्य का सूचक होता है।

$$G.R = GDI \times \frac{1}{ICOR}$$

✓ बिजली उत्पादन का **ICOR** सबसे ज्यादा है =

∴ निवेश का अभाव bcoz उसका ICOR बहुत ऊँचा है, जिसके कारण लाभदायकता कम है।

✓ **COR :- (Capital Output Ratio)**

उत्पादन की एक दी गई मात्रा या उपलब्ध मात्रा के लिए निवेश न सम्पूर्ण पूँजी के आनुपातिक मूल्य को COR कहते हैं।

$$\frac{C}{O} = \frac{}{12-13 \text{ का GDP}}$$

Capital में इजाफा

GD में इजाफा

से ∆ O

पूँजी निर्माण / संसाधन दोहन {Resource Mobilization}

उत्पादन क्षेत्र :-

कृषि : 4%

उद्योग :- विनिर्माण - 10%

कुल उत्पादन : ₹ 100 लाख करोड़ ₹

- कृषि — 14 लाख करोड़, 14%
- विनिर्माण — 15%
  - खनन एवं उत्खनन
- सेवा → परिवहन

Backward linkage → उत्पादन के पहले के कार्य से संबंधित

Forward linkage → बाद के

इन linkage को बढ़ाने की बात

Ques कृषि क्षेत्र के लक्ष्य को बढ़ाने हेतु क्या रणनीति है

पिछले 60 वर्षों के आयोजन 12 5 yP पर

भारत में मितव्ययिता को बढ़ावा (बचत की आदत) देने के लिए - क्या उपाय?

1) बचत सृजन :→ (राशि बचाना) — आय ↑ (बचत क्षमता), औसत बचत प्रवृत्ति ↑ (बचत की आदत)

2) बचत का दोहन / उगाहन :→ सक्रिय वित्त प्रणाली

- गतिशील क्षमता (भावी क्षमता)
- आंचलिक प्रसार पर बल
- कार्यकुशलता

'जमा ब्याज दर ↑

पा के बाद संसा. दोहन ↑

↑ ⟹ दोहन ↑

3) बचत का निवेश :→ (उत्पादक कार्य में संसाधन उपयोग)

- आम - उत्पादन तात्कालिक

बचत प्रवृति अर्थात् मितव्ययिता को बढ़ाने हेतु दो प्रकार के उपाय :-

I) आदेशात्मक उपाय / बाध्यकारी उपाय :-

1) भविष्य निधि में बाध्यकारी अंशदान के लिए कानून बनाया गया।
2) पेंशन निधि में बाध्यकारी अंशदान " " "
3) स्वास्थ्य निधि " " " " "
4) बीमा निधि " "
5) मनोरंजन निधि " "

II) बचत प्रेरक या प्रोत्साहन उपाय :-

1) भविष्य नि० में अतिरिक्त अंशदान पर कर की छूट
2) पेंशन " " "
3) स्वास्थ्य " "
4) बीमा " " "
5) मनोरंजन " "
6) सरकारी प्रतिभूतियों में (बॉण्ड एवं हुण्डी) निवेश पर कर की छूट " "
7) लघु बचत प्रमाणपत्रों पर निवेश पर (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, हीरा विकास पत्र, डाक घर जमा राशि)

पिछले वर्ष (किसान विकास पत्र) को बंद कर दिया गया,

उपरोक्त बचत प्रमाण पत्रों के विक्रय से उगाही गई राशि को (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) में रखा जाता है। जिसमें से 75% राशि ऋण के रूप में राज्य सरकारों को दी जाती है। एवं 25% राशि ऋण के रूप में केन्द्र सरकारों को दी जाती है।

- सावधि जमा पर निवेश में कर की छूट
- ~~अविक्य निधि में निवेश पर कर की छूट~~
//पारस्परिक
ऐसी वित्त संस्था, जो ईकाई प्रमाण पत्रों के विक्रय द्वारा बचत की छोटी-2 राशियाँ एकत्रित करे एवं प्रतिभूति बाजार में अर्थात बॉण्ड एवं शेयर बाजार में निवेश की विशेषज्ञता रखे, पारस्परिक निधि कहलाती है।

(2005) - शिक्षा में निवेश पर कर की छूट
- बुनियादी ढाँचा बॉण्ड में निवेश पर कर की छूट

(बुनि॰ ढाँ॰ निर्माता Co. द्वारा जारी बॉण्ड अथवा ऐसी Co. के लिए वित्त उगाही करने वाली कंपनी द्वारा जारी बाण्ड) → (2012-13)

- शेयर बाजार में प्रत्यक्ष निवेश (स्वर्ण मि॰) पर कर की छूट (2012)

राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम

Note 91

// बाध्यकारी आय

// प्रेरकारी आय
(First 5, 91 से पहले की हाल के 6 to now तक)

200

निवेश प्रोत्साहन संबंधी

आपूर्ति पक्षीय कारक

- निवेश योग्य नीधि की मात्रा (ज्यादा) बढ़े
- ब्याज पर ऋण की दर ↓ (सस्ता)

माँग - पक्षीय कारक

1. उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग एवं विक्रय ↑
2. कीमत ↑ (निश्चित हद तक कीमत बढ़े)

Qus :- स्था० स्रोहन की विकास प्रक्रिया मे केन्द्रीय भूमिका होती है। लेकिन भारत में कई अवरोध्द अनुभव किये जाते हैं?

Qus :- 11वीं 5YP के दौरान भारतीयों की औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन F.I. द्वारा उगाही गई बचत राशि मे आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पाई है।

बचत के रूप में

- वित्तीय
  - शेयर बाजार
  - म्युचुअल फण्ड
  - बैंक
- भौतिक
  - सोना - चाँदी
  - जमीन, मकान

bcoz अधिकांश F.I.in भौतिक बचत

- (बड़े - बड़े शहर, छोटे शहरों में) → why → फायदा ↑
- → सोना - चाँदी की कीमतें ↑
  - ⇓ (–)
  - उत्पादन गति० में प्रयुक्त नहीं
  - CAD ↑
  - उत्पादक निवेश ↓
- सामाजिक ब्यापक आधार

2002 ———→ 2004

बीज ——— प्रस्तुति

भारतीयों विशेषत: ग्रामीण लोगों की बचत प्रवृत्ति काफी कमजोर है। इसे बढ़ाने के लिए ⇒ उक्त उपाय ग्रामीण क्षेत्रों में + वित्तीय समावेशन + PPF एकाउंट खोलने के लेकर जागरूकता बढ़ायी जा रही है।

- सभी डाकघरों को बैंक में रूपांतरण ✓
- RBI के नए लाइसेंस प्रस्ताव ✓

SHG-बैंक लिंकेज कार्य, 92 के चलाया जा रहा (स्वयं सहायता समूह - बैंक संबद्धता कार्यक्रम) है जिसमें गैर सरकारी संगठन की सहायता भी जा रही है।

- बीमा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- बीमा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन FDI के मानकों का नम्यीकरण ताकि बी० क्षे० की क्षमता ↑ ⇒ ग्रामीणों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराये जाये।

26 से बढ़ाकर 49% किया है।

- वर्ष 2008 में RBI ने वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया। मुख्य बल ग्रामीणों में जागरूकता फैलाना है।

महत्वपूर्ण उपाय - ग्रामीण बचत ⟹ आय ↑

आय है:
- MSP ↑
- (MNREGA)
- बुनियादी ढाँचा सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- भूमिहीन ग्रामीणों की आय ↑ + मजदूरी दर ↑
- "व्यवसायमुक्त खाता" (no frill अकाउंट) है

Qus - भौतिक बचत को हतोत्साहित कर वित्तीय बचत को बढ़ाने हेतु क्या उपाय हैं -

- स्वर्ण में निवेश ↓ ⟹ आयात शुल्क ↑

[illegible] निवेश

नहीं । ⇒ ?

↳ आभूषण विक्रेता को निर्देश : क्रेडिट कार्ड से भुगतान वालों को आभूषण नहीं

↳ माँग ↓ ⇒ कीमत ⇓ ⇒ लाभ ↓ ⇒ निवेश ↓

- ↳ अंतरा० सहयोग पूर्ण तरीके से ~~भण्डार में~~ केंद्रीय बैंक भण्डार का सोना बेच रहा है :- कीमत में भारी गिरावट हुई। कईयों को भारी नुकसान ⇒ सट्टेबाजी प्रवृत्ति ↓

↳ 22 July 2013

जो सोने का आयात 20% निर्यात करना होगा (सट्टेबाजों पर प्रतिकूल असर)

NBFC

आलोचनात्मक → (−) → अवैध तरीके से स्वर्ण आयात की प्रवृत्ति ↑

- Real ~~Estate~~ estate में सट्टे ↓ के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं :-

- 1 करोड़ + मूल्य वाले मकान की खरीद पर 1% सर्विस टैक्स → सर्विस टैक्स की वसूली हेतु ~~लेन~~-देन का लिखित दस्तावेज → दाम बढ़े / निवेश। / निगरानी में इजाफा

- एक निश्चित सीमा से बड़े मकान पर टावर्स पर टैक्स की दर ↑ → सूचना / काले धन पर रोक

- Regulatory Body :-

- छोटे शहरों में आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित सीमा तक आ० ऋणों की ब्याज

दर कम कर दी गयी।

- शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना को तेजी से लागू।
  ↳ लाख मांग ↓

अनुमोदित - SEZ कार्य - पहले से अनुमो० SEZ की पुनरीक्षा की गई। कई अनुमोदन कैंसिल किये गये। 36 developers खुद करा रहे हैं, b(o) मंदी के कारण इनाका ↓ | SEZ की उपयोगी पहले से कम हुई।

निर्यात ↓ ⇒ SEZ ↓ ⇒ जमीन के ग्राहक की मांग

- SEZ कार्य में संशोधन → छोटे SEZ के कर की छूट ↑
  ↳ बड़े SEZ के कर की छूट ↓

- बड़े शहरों के आस-पास SEZ की मांग ↓

जमीन ⇓ अंशत:

सोना - चांदी ① गोल्ड उत्पादक

उत्पादन: भारत में अभी दिख रहे उच्च बचत एवं निम्न निवेश के विरोधाभास की व्याख्या करें।

b(o) of ① उधार ब्याज दर
  ⓑ RBI ↑ ⇒ ... छवि
  ... क्षेत्र में उधार ↑
(सि 2008 से ... ...

अमेरिका वस्तुओं + सेवाओं की माँग गिर गयी है जिससे
निर्यात ↓ ⇒ निर्यातमूलक की बिक्री ↓↓ है, निवेश ↓

(3) भारतीय शहरों के नये हज़ार के कारोबार निर्यात पर आश्रित है ⇒ निर्यात ↓ ⇒ कारोबार ↓

जैसे :- आभूषण, वित्तीय, IT सेक्टर, [illegible]

कामगारों की आमदनी ↓ + अपनी खरीददारी कम हुई है।

घरेलू माँग ↓↓

(4) बिक्री गिर रही है :- वाहन ⇒ इस्पात का कारोबार

बिक्री ↓↓

↓↓

ऑटोमोबाइल

गुड्स सेक्टर के निवेश ↓

Ques विकासशील देशों में अंत० व्यापार करने का इंजन नहीं रह गया है आलोचनात्मक परीक्षण किया।

प्रसंस्करण

खाद्य उद्योग

I) समावेशी पूंजीनिर्माण (निवेश) मॉडल

II) संवृद्धि एवं विकास का तुलनात्मक अर्थ

III) संवृद्धि एवं विकास के माप/आंकलन

समावेशी निवेश मॉडल :- निवेश की ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के सभी क्षेत्रों, देशों के सभी अंचलों एवं समाज के सभी वर्गों की प्रगति को सुनिश्चित किया जाये व विशेषकर पिछड़े (उत्पादन क्षेत्रों/ भौगोलिक अंचलों/ पिछड़े सा० वर्गों) को वरीयता दी जाये समा० नि० मॉ० कहलाता है

₹ 300 लाख करोड़

GDP

GDC — 67%

GDS (सेविंग) — 33% available for निवेश

पिछड़ों

Ques :- समावेशी संवृद्धि के लिए निवेश ढांचे का भी समावेशीकरण करना आवश्यक शर्त है, स्पष्ट करें।

भारत का उत्तर क्षेत्र — पूर्वोत्तर के हरित क्रांति का प्रभाव

- बचत की प्रक्रिया में क्षे० - सा० संतुलन
- वित्त प्रणाली में भी समावेशीकरण
- निवेश

राजनीतिक तौर पर व्यावहारिक निवेश मॉ०

यानि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का पूरी तरह समावेशीकरण।

संवृद्धि :- उत्पादन की मात्रा में सतत् वृद्धि की प्रक्रिया को आ० संवृद्धि कहते है।

- उत्पादन बढ़ने के साथ-2 समाज के विभिन्न वर्गों के उपभोग में होने वाली संतुलित वृद्धि जिससे सामाजिक संतुष्टि का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाये, आ० विकास कहलाता है।
- सभी वर्गों के उपभोग में सुधार के लिए बेरोजगारी एवं गरीबी मे उत्तरोत्तर गिरावट जरूरी है, तथा इसके लिए उत्पादन क्षमता एवं रोजगार के अवसर में उत्तरोत्तर विस्तार जरूरी है।

(विकास)

filtreution theory

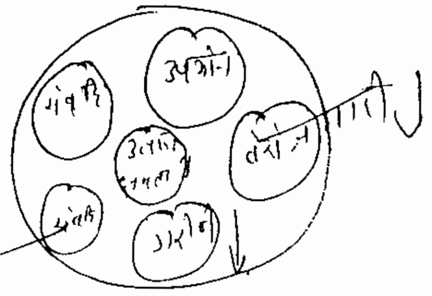

Que आर्थिक संवृद्धि आ० विकास की एक आवश्यक शर्त है।

वाले उत्पादन

Que संवृद्धि का रुझानी मॉडल व विकासपरक

संवृद्धि का मॉडल

उत्पादन ∴ बढ़ाना कि लोगो का जीवन-स्तर

Que 11वी योजना से निरन्तर विकास को नकारा व विकास० संवृद्धि का मॉडल अपनाया

जनहित ३—

Qus ३— विकास मात्र मो० हिया नहीं

आर्थिक विकास ३— का आंकलन ३

G – Gross
D – Domestic
N – Net
N – National

1) आर्थिक संवृद्धि का सूचक (GDP_{mp}) – NIT = GDP_{FC}

2) GNP_{mp} – NIT ⇒ GNP_{FC}

3) NDP_{mp} – NIT = NDP_{mp}

राष्ट्रीय आय की परिभाषा ?

4) NNP_{MP} (निराउवाली) – " = NNP_{FC} (राष्ट्रीय आय)

GDP का संवृद्धि का मौलिक सूचक ३— (कारक लागत पर आधारित निवल राष्ट्रीय उत्पाद)

GDP_{mp} – NIT – DA + NFIA = NNP_{FC}

1000 – 120 – 100 + (–0.6) = 779.4

राष्ट्रीय आय ३— एक वर्ष के दौरान उत्पादन हेतु हुई उपाज हेतु से प्राप्त होने वाली आय।

राष्ट्रीय आय → उपभोग
राष्ट्रीय आय → बचत

If GDP_{mp} ↑ ⟶ NNP_{FC} ↑

आय ↑ → बचत ↑ → निवेश ↑ → GDP ↑

अंबानी की दुनिया भारतीय ⇒ बेरोजगारी की दर

उत्पादन should be समावेशी

आर्थिक विकास के सूचकांक

सामाजिक – आर्थिक सूचक है

1. लॉरेंज वक्र ✓
2. गिनी गुणांक ✓
3. कुजनेट्स वक्र ✓

(1) लॉरेंज वक्र है → संचयी बारम्बारता वक्र जो आय वितरण के मामले में Apply

6-07

आय-वर्ग \ राष्ट्रीय आय में अंश	स्वतंत्र अंश	संचयी अंश
HIG 25%	46.1%	100.0%
MIG: UMIG 25%	15.2%	53.5%
MIG: MMIG 25%	15.0%	37.7%
MIG: LMIG 25%	11.6%	19.7%
LIG	8.1%	8.1%

High Income Group

UMIG ⇒ Upper

आय वितरण के संदर्भ में चार बराबर भागों में बांटा जाता है।

आय में विषमता → बचत में विषमता → निवेश में विषमता

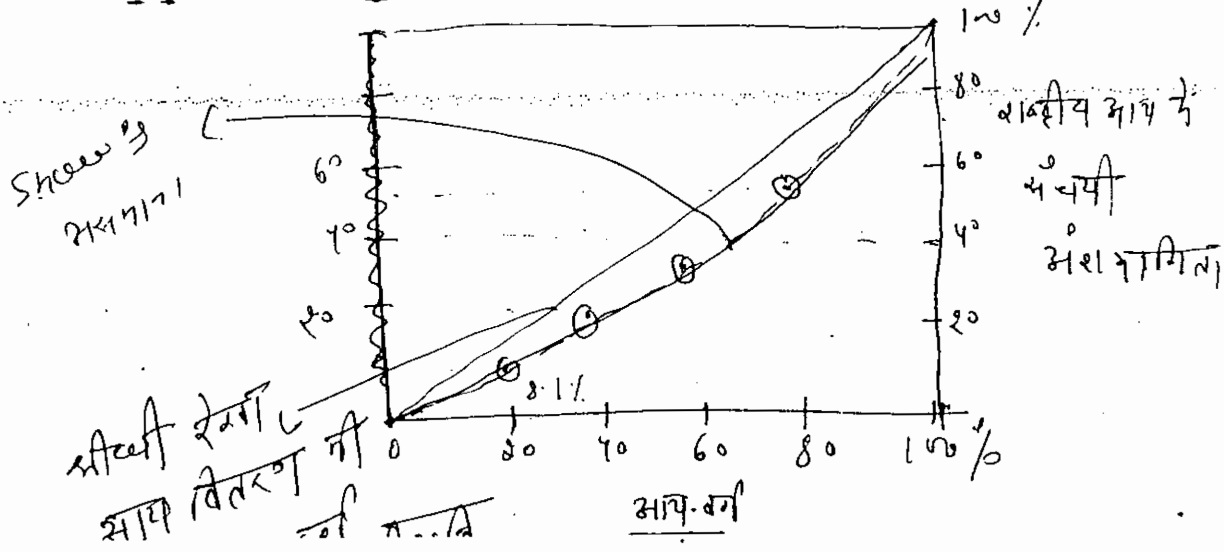

समाज में (+) आय वितरण की यथार्थ स्थिति को व्यक्त करने वाला वक्र लॉरेंज वक्र कहलाता है।

2007 — 12

(1) GDP ↑

use of — "संवृद्धि की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए लॉ० वक्र का उपयोग अर्थात् संवृद्धि की प्रक्रिया समावेशी रही है या गैर समावेशी रह गई है आंकलन के प्रयुक्त। यदि उत्पादन में के साथ-2 लॉरेंज वक्र की ढाल भी ऊँची होती जाये, तो इस प्रक्रिया को समा० संवृद्धि कहते हैं। यदि उत्पादन वृद्धि के साथ-2 लॉ० व० की ढाल गिरती जाये, तो गैर समावेशी संवृद्धि कहते हैं। (विषमता मूलक संवृद्धि)

गरीबी (अनुपात - गरीबी)

04-05 → 2011-12

37 % — 21.9 %

40% — (27 करोड़)

उपयोग मान्य सीमा के नाम

Que :- 11वी योजना में कैसे गोन -2 से कार्यक्रम चलाये गये, जिससे गरीबी का स्तर कम हो गया?

Que :- 11वी योजना में चलाये गये गरीबी निवारण के उपाय

(Growth मापन)

सीमांत एवं लघु कृषक मजदूर 85% — मध्यम एवं बड़े 15%

2004-05 (107 करोड़) → 70% ग्रामीण → 55% कृषि, 15% गैर कृषि

डॉ अर्जुन सेनगुप्त आयोग (85%) → दैनिक आय @ 20 रु.

गरीबी ↓ b(cos) of → आय ↑, व्यय ↓, कमाई ↑

MNREGA → पहले 200, 07 — 330, 2008 → whole India

04-05 में	now
खर्च ↓	35 × 5
6-7 किलो	-

05 में भारत निर्माण

05 - पेयजल / स्वच्छता अभियान / NRHM

→ PDS में सुधार

— विभिन्न योजनाएं :-

NRHM → 2005
(ज्यादा सेन्सला का रहा
(तुलनात्मक अध्ययन पर बल

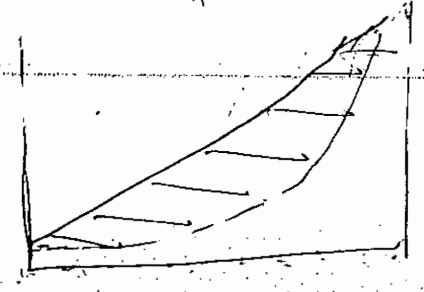

क्षेत्र ↑ = विषमता ↑
क्षेत्र ↓ = विषमता ↓

आदर्श रेखा व लॉरेंज Curve के बीच का क्षेत्र विषमता के परिमाण का सूचक
न्यू काली आय प्रति व्यक्ति को

(काल्पनिक)

लॉरेंज Curve – समकोण
क्षेत्र → त्रिभुज $\frac{100}{100} = 1$

गिनि गुणांक → $\frac{\text{विषमता की वास्तविक मात्रा}}{\text{विषमता की संभावित मात्रा}}$ $\frac{}{100}$

आदर्श रेखा एवं लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल

$\frac{2}{4} = .5$ — आदर्श के अधीन त्रिभुजाकार क्षेत्रफल

$\frac{1}{4} = .2$

विषमता का सूचक → गिनी गुणांक

-- — अनुपात/गुणांक —

गिनी गुणांक का इस्तेमाल

रूस > चीन/USA > भारत > जापान
↓
सबसे कम
(70 विषमता)

नागरिकों की ... तुलना के आधार पर ज्यादातर बाहर आयात/अनुपाती

गुणांक (+) 1) तुलना में बेहतर 2) विषमता का मात्रात्मक मान

विषमता → केरल में ↓ //

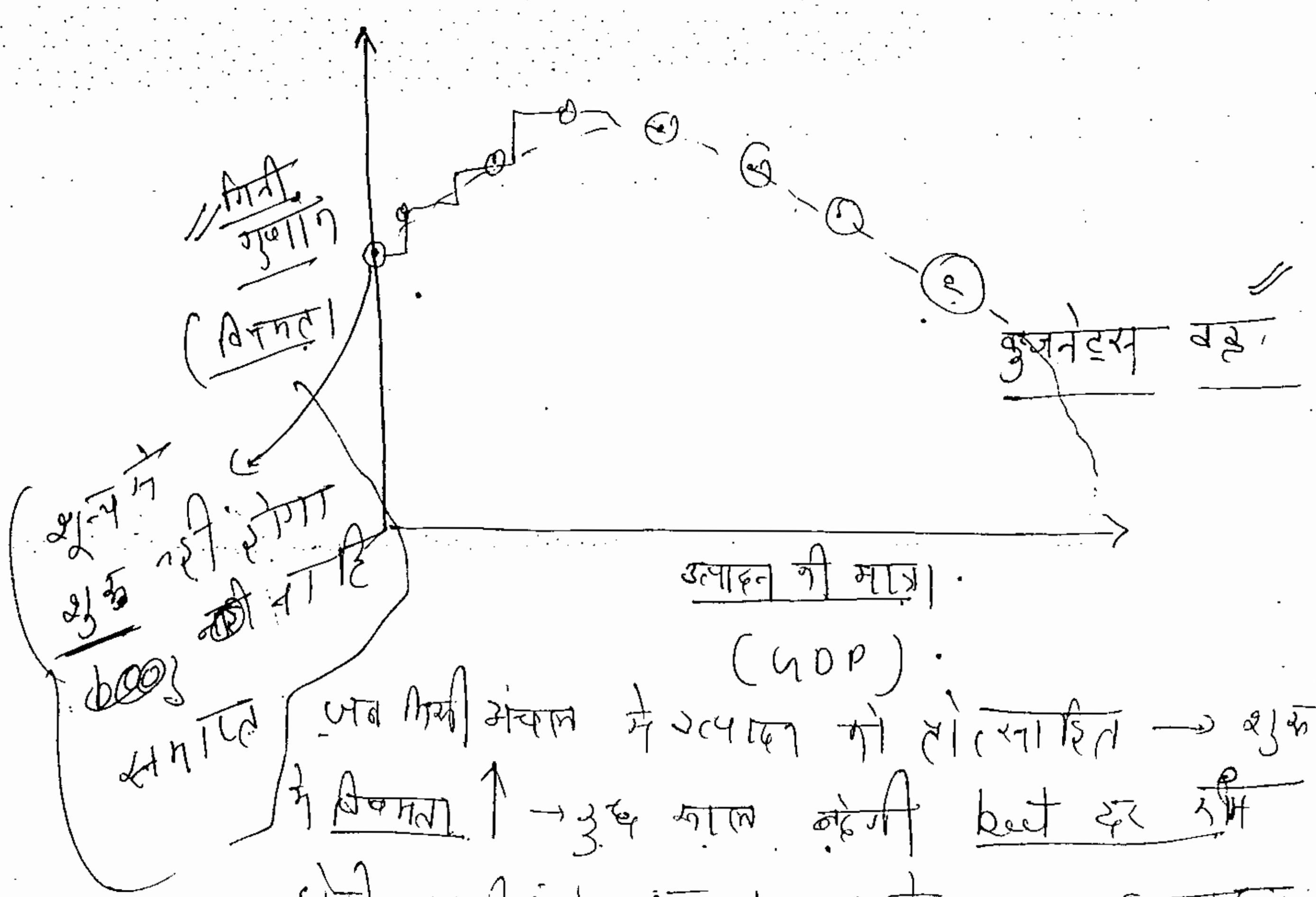

जब किसी अंचल में उत्पादन को प्रोत्साहित → शुरू में विषमता ↑ → कुछ काल बढ़ेगी but दर कम होती जाती है। इस समय के बाद उत्पादन बढ़ने के साथ

⇒ उत्पादन की मात्रा में ↑ के साथ - 2 आय वितरण की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करने वाला वक्र, जिसमें यह व्यक्त होता है कि उत्पादन वृद्धि के आरम्भिक चरण में विषमता बढ़ती है। एवं उत्तरवर्ती चरण में // में गिरावट आती है।

Qus संहति को समावेशी बनाने के मार्ग में क्या बाधायें हैं?

→ पूर्ण मा० समता लाने के लिए ना सिर्फ अवसरों में पूर्ण समता लानी जरूरी है, बल्कि आकांक्षाओं एवं कौशल में भी पूर्ण समता लानी जरूरी होती है। ना कभी अकां ना हि कभी कौशल में पूर्ण समता आ पायेगी। आकांक्षा में समानता संभव नहीं

bcoz सबके आकांक्षा का स्वरूप अलग-2 है।
कौशल में

मान्य सोपानवद्ध विषमता न्यायपूर्ण है

Qus ?

but समान कार्य के लिए विषम भाव अन्यायपूर्ण स्त्री/पुरुष

Which is → संविधान के उल्लिखित विधान अन्यायपूर्ण है।

न्यायपूर्ण असमानता
अन्यायपूर्ण असमानता

1st HSYP ← न्याय विषमता

(4) एंजेल वक्र है → गरीब आदमी जब अमीर होने लगता है, तो खाद्यान्न पर उपभोग व्यय ⇒ धीरे-धीरे घटता

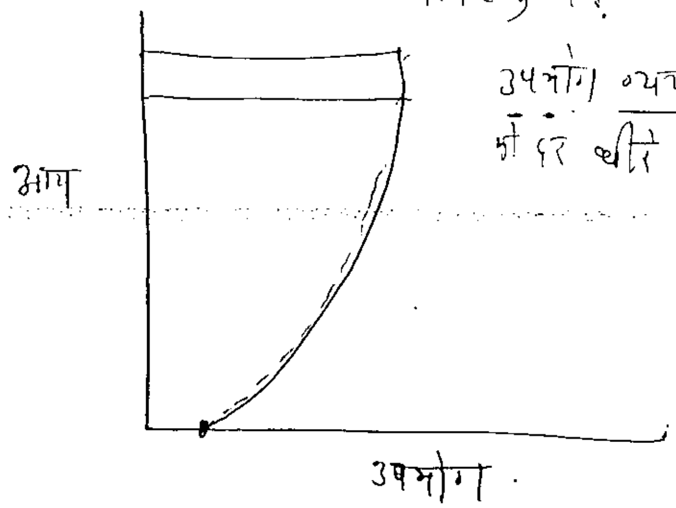

Food Inflation → b'coz गरीबों की मांग।

आय में वृद्धि के साथ-साथ उपभोग में होने वाली वृद्धि विशेषकर खाद्यान्न उपभोग में वृद्धि के गिरते अनुपात को व्यक्त करने का वक्र एंजेल वक्र कहलाता है।

विकास संबंधी UNDP के सूचक

1) HDI
2) GDI → GII → (Gender Inequality Index) (जेण्डर संबंधित विकास सूचकांक)
3) ~~HPI – 1~~ GEM → (" Empowerement Measures)
4) HPI – 1 } → Human Poverty Index
5) HPI – 2 } एवं (" " ")

2010 में बंद HP
→ now MPI (बहुआयामी निर्धनता सूचकांक)
2010 में शुरू

सूचकांक = सूचक + अंक
Index Number

→ (कोई अंक जो किसी प्रवृत्ति का इशारा करे सूचकांक कहलाता है।)

Ex
$$\frac{अ_क + अ_ख + अ_ग + अ_घ}{N} = 14 \ (2013)$$

$$\frac{क + ख + ग + घ}{N} = 15$$

$$\frac{\text{औसत आयु}_{14}}{\text{औसत आयु}_{13}} \times 100 \qquad \sum \frac{P_1 X_1}{P_0 X_0} \times 100$$ → (मूल of Index formula)

=> सूचनाओं के समूह की दिशा।

X => गतिशील
सूचना नहीं

Index Num => Dynamic Value

Shows
औसत मूल्य
में कितना
परिवर्तन

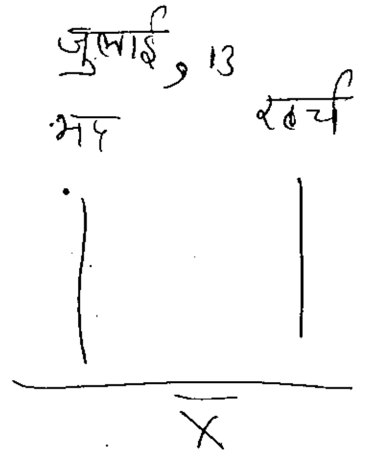

by महबूब-उल-हक

(Human Development Index

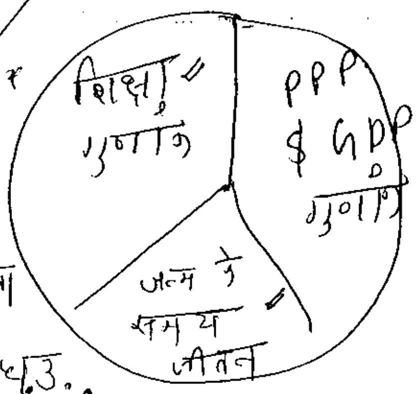

Define - HDI

PPP (क्रय शक्ति समतुल्यता आधारित प्रति व्यक्ति $ स.घ.उ., जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एवं शिक्षा गुणांकों से मिलकर बना एक मिश्रित या सामासिक सूचक है, जो मानव जीवन की गुणवत्ता का आकलन करता है)

Ques विकास प्रक्रिया के विश्लेषण। HDI, GDI एवं GEM के महत्व को स्पष्ट करें।

Ques भारत में वित्तीय सुधार की दृष्टि से क्या प्रयास हुए?

CSO

₹ GDP
₹ 100 लाख करोड़

GDP
₹ 100 लाख करोड़ = 1.67 लाख करोड़ $ 1670b
(परंपरागत तरीका) 60
UNDP ⇒ 365 दिन का औसत

(−)
- मात्रा/कीमत का सही अंदाजा नहीं लगा पाता

मात्रा
- निर्माण मात्रा × 2$
- भारत मात्रा ×

Q × Ps
(Quantity) (मूल्य)
(कीमत बढ़ने पर उत्पादन)

क्रय श
PPP – ₹ 100 GDP
निरूपण हेतु राज्य समतुल्य कीमत से ली जाती है।
(क्रय शक्ति समतुल्यता)

(+) परिवर्तन
1) कीमतें के व्यापक अंतर से उत्पन्न विकृति को

RPP
विभिन्न देशों के उत्पादन का भौतिक मूल्य निकालने के लिए एक समान औसत कीमत का यदि उपयोग किया जाये, तो आंकलित उत्पादन मूल्य को क्र॰ श॰ सम॰ आधारित उत्पादन कहते हैं।

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⇒ बच्चे की औसत आयु
सबकी ⇒ औसत आयु

शिक्षा

बच्चों की कुल संख्या वाले < 15 — व्यस्क > 15

- प्राथमिक (1-5) ✓
- द्वितीयक / माध्यमिक (6-8) ✓
- तृतीयक (9-10)

$$\frac{\text{प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती बच्चों की}}{\text{प्राथ॰ शिक्षा आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या}} = \frac{8}{10} = .8 \Rightarrow \text{(प्राथमिक भर्ती अनुपात / नामांकन)}$$

Same method for IInd & IIIrd

✓ = सकल भर्ती अनुपात — प्र॰ भर्ती + द्वि॰ + तृतीय

✓ = Adult literacy Ratio ⇒ $\frac{\text{साक्षर व्यस्क जनसंख्या}}{\text{कुल व्यस्क जन॰}}$

= दोनों का औसत = सूचकांक — शिक्षा सूचकांक

for प्राथमिक → सार्व शिक्षा

माध्यमिक → प्राथमिक माध्यमिक

Drop out ratio — भर्ती बच्चों में से पढ़ना छोड़ दे

Retention ratio — भर्ती वाले अगले class में भी रहे

Retantion Ratio
आकर्षण बल ↑
ठहराव बल ↓

→ Mid day मील
→ वजिफा (for girl)
→ साइकिल वितरण
→ No Burden

9 | 7/8 → शिक्षा हेतु त्वरित

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

जन्म पूर्व (Pre-Natal)
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना → 2004 में पुनर्गठित
→ जननी सुरक्षा योजना → 12वीं FYP जननी-शिशु सुरक्षा योजना (JSSY)

Post-Natal (जन्मोपरांत)
- जननी शिशु सुरक्षा योजना
- पोलियो
- बाल स्वास्थ्य परीक्षण
- ICDS
पोषाहार में सुधार (1 to 5)

प्रतिव्यक्ति GDP ↑
GDP ↑ − ↑Population
$G_{Product} > G_{pop}$

0 − 1 साल ⇒ शिशु (Infant)
0 − 7 दिन ⇒ नवजात (Newly born Infant)

शिशु मृत्यु दर < नवजात मृत्यु दर

पोषाहार भत्ता (स्वास्थ्य सुरक्षा भत्ता)
⇒ Direct Benefit Transfer
(+) → महत्त्वों की भागीदारी ↓
→ ICOR ↓

1925 में क्या सुधार हो

रचनात्मक संवेदनशील
सुझाव सबके लिए स्वावलंब + नागरिक बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं।

GDI

(+) / (−)

सामान्यीकरण

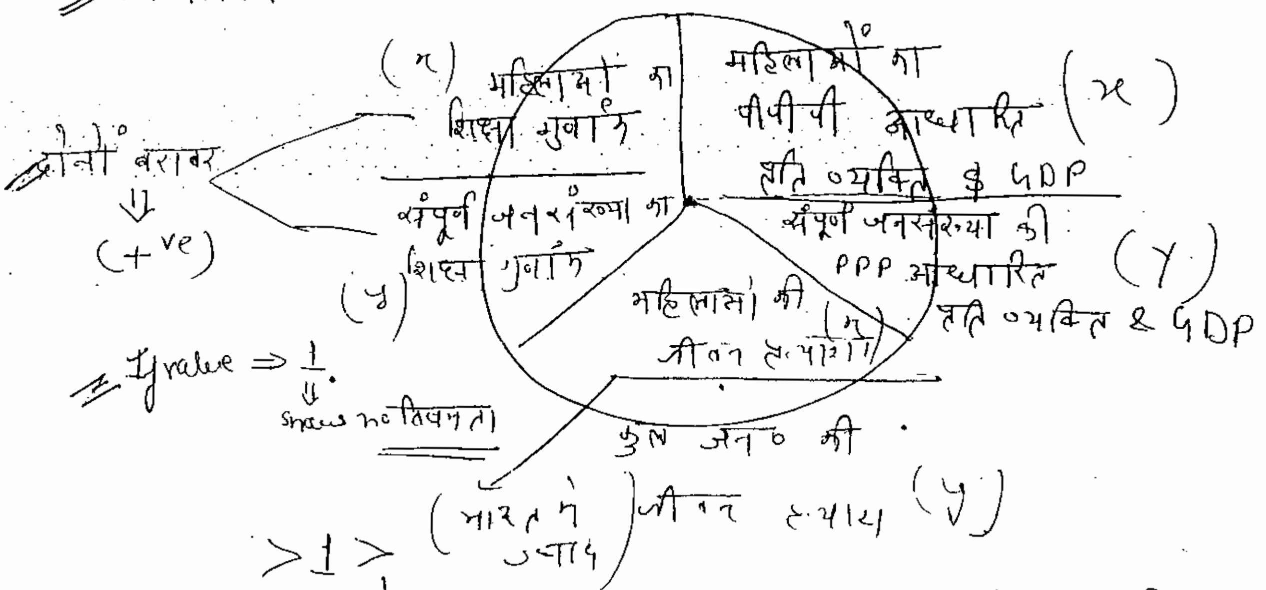

> 1 >

↓ +ve ↓ −ve

यदि गुणांक का value 1 से कम तो (+ve)

यदि " " " 1 " ज्यादा तो (−ve)

भारत में 1 से कम है।

Gender विषमता सूचकांक ⇒

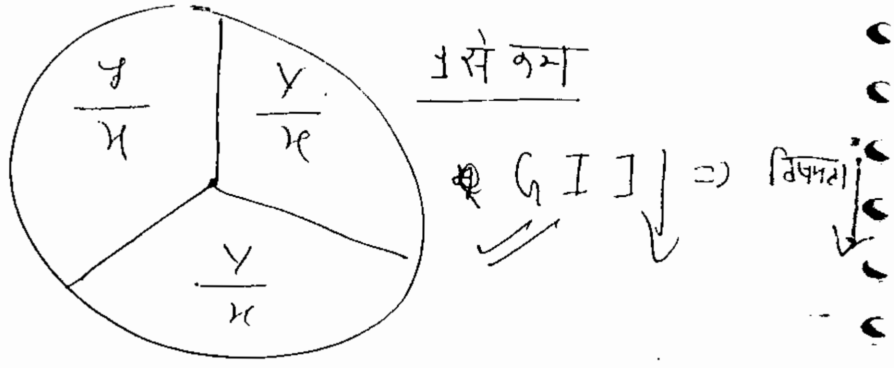

GEM (जेण्डर सशक्तीकरण उपाय) :-

राजनीतिक भागीदारी दर | शि० भा० द० | आ० भागी० दर

रा० आ० एवं सामाजिक निर्णयन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागी० दरों के मिले-जुले औसत सामासिक

आंकलन को GE उपाय कहते है।
(म० " ")

GEMs ↑ = GDI ↑ = GII ↓

GEMs ⇓ (उपलब्धि के कारक) — why lot — परम्परागत भाव

GDI ⇓ (महिलाओं की उपलब्धि)

रा भाग बढ़ाने के उपाय :-

⇓

अर्थ :- किसी देश की राष्ट्रीय विधायिका में महिला सदस्य को % मूल्य को रा० भाग कहते है। (b'coz → संप्रभुता मौलिक कानून)

आर्थिक भाग :-

→ सार्वजनिक संस्थाओं में महिला भाग =
 - राष्ट्रीय विधायिका में
 - स्थानीय निकायों में
 - कार्यकारी पदों पर → (हस्तक्षेप)

→ निजि सं० के म० भाग => (HUF, SHG's

b'coz राष्ट्रीय विधा० द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं ... महत्व के ∴ ... ↑

सामाजिक भाग :- पारिवारिक / गृहस्थ आय में महिला सदस्यों के % अंशदान को सामाजिक भागीदारी दर मान लिया जाता है। b'coz जितना % आय में => उतना ही % व्यय में (उपभोग) => सा० भाग

(−) – रूढ़िवादिता / – no जवाबदेही / – मातृसत्तात्मक पारि० प्रणाली में महिलाओं को आय से ज्यादा व्यय संबंधी निर्णय में हिस्सेदारी अधिक, जबकि पितृसत्तात्मक में विपरीत स्थिति होगी।

- बीजिंग का . मॉडल को भारत सरकार ने अस्वीकार किया हमारे समाज हेतु यथार्थपरक नहीं।

नीतिगत भाग — Case Study है → राजनीति महिला => सत्ता संघर्ष। घरेलू " => " " ।

आरक्षण • उ० नातियों परिवार स्तर पर पहल → त्रिस्तरीय प्रयास किया

आ० भाग → विभिन्न स्तर पर आरक्षण ↑ → परंपरा की नई व्याख्या / महिला अनुकूल व्यवस्था

Informal Education +

GEM

GEM से सम्बन्धित सरकारी उपाय

- महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा

- अन्य देशों से तुलना

श्रीलंका ⇒ PM; बांग्लादेश; पुर्तगाल; पाक० आरक्षण

निर्धनता सूचकांक

HPI-1 है

गैर OECD देशों में गरीबी के आकलन के लिए HPI-1 का उपयोग किया जाता था, जबकि OECD के C० में ग० के आ० हेतु HPI-2 का उपयोग किया जाता था। अब दोनों वर्ग के देशों में गरीबी के आकलन हेतु MPI का उपयोग किया जाता है।

HPI-1 → वास्तविक उपयोग संबंधी अभाव/वंचना → स्वास्थ्य अभाव → जागरूकता अभाव

वा० उप० संबंधी अभाव है

- पेयजल रहित जनसंख्या का % मूल्य
- 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का % मूल्य

दीर्घ स्वा० अभाव है - 40 वर्ष या कम आयु ~~वाले~~ [illegible] वाले लोगों का % मूल्य

जागरूकता अभाव है - व्यस्क निरक्षरता अनुपात

(labour force)

श्रमशक्ति => काम करने की इच्छा + शक्ति रखने वाले लोगों का समुदाय

HPI - 2 = HPI 1 + (स्थायी बेरोजगारी से ग्रस्त लोगों का श्रमशक्ति से % मूल्य)

सामाजिक अभाव

MPI है → वास्तविक उपभोग संबंधी अभाव → (+) उपभोग संबंधी व्यापक आयाम

(—) 1 विलासिता पूर्ण वस्तु add (eg → मोबाइल, टीवी.)

जनता में मुफ्त बांटने की प्रथा → संचित निधि [illegible]

बहुआयामी P I में P आंकलन हेतु तीन आयाम

(1) भोजन एवं पेयजल से अभाव (2) कारक उपभोग संबंधी अभाव (3) आवश्यकता संबंधी अभाव
(2) [illegible] ~~कारक~~ + सेवाओं से उपभोग

MPI में गिरावट संबंधी तथ्य

- खाद्य सुरक्षा — [illegible]
- आवास सुरक्षा — राजनीतिक
- स्वास्थ्य

फिलिप्स वक्र (एक नि[illegible] क्षेत्र ↑)

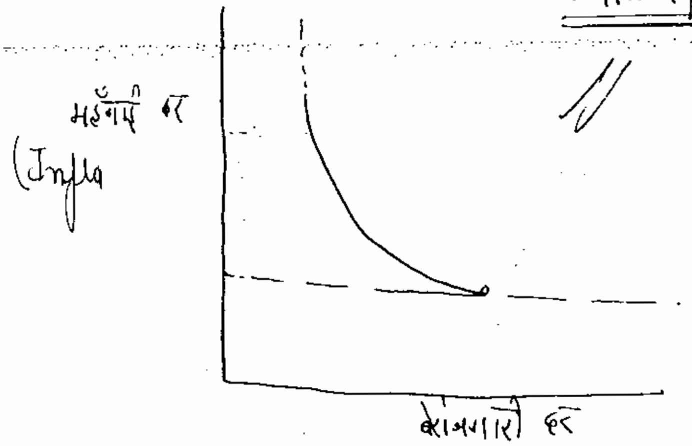

महासमष्टि [illegible]

के प्रतिलोम संबंधों को व्यक्त करने का वक्र फिलिप्स का वक्र कहते हैं।

Ex-plain ⇓ why प्रतिलोम

फि० वक्र० की व्याख्या (1957)

उ प्रारंभिक पूर्व मान्यताये (Assumption)

महँ० द्र => 4%

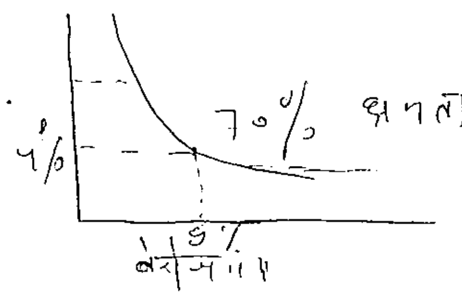

गेहूँ का MSP 2006 — 107
2005 — 100

MSP ↑ ⟹ दोहन दर ↑ => बेरोजगारी दर ↓

Inf ↑

why Inf ↑ => रोजगार => गरीबी ↓ => 3

↳ उत्पादन ↑

फि० वक्र० एक सीमा तक

Inflation ही applicable है।

Inf ↑ ← मांग ← उत्पादन की मात्रा ↑ → खाद्यान्न की आपूर्ति ↑ → निर्यात / घरेलू उपभोग

आयात ↓

घरेलू उपभोग → बाजार तंत्र (निजि व्यापारियों) → HIG एवं UMIG
घरेलू उपभोग → FCI → PDS → LIG, LMIG, WMIG

HIG एवं UMIG, LIG LMIG → खाद्य सुरक्षा।

खाद्य सुरक्षा
⇓
पर्याप्त मात्रा में उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता

2. उत्पादन की मात्रा × कीमत ↑ = आय ↑

आय ↑ → उपभोग ↑ / बचत ↑

उपभोग ↑ → कृषि वस्तु / औद्योगिक वस्तु ↑ / सेवाओं

औद्योगिक वस्तु → साबुन, कपड़ा, जूता etc

सेवाओं → शिक्षा, चिकित्सा

3) बेरोजगारी ↓ ⇒ गरीबी ↓

(-ve) प्रभाव

1) जमाखोरी एवं सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को बल (कालाबाजारी / काली अर्थव्यवस्था ↑) → within country / outside country

2) बेरोजगारी एवं गरीबी की तीव्रता
⇓
उपभोग स्तर ↓

3) तस्करी ↑
⇓
Expression

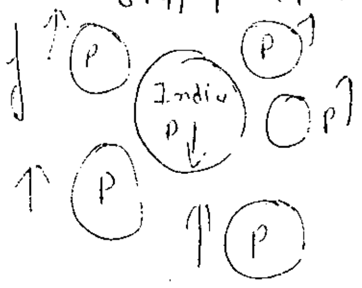

घरेलू कीमतों का अंत० कीमतों के साथ तालमेल बिठाने से अवैध अंत० व्यापार (तस्करी) होने लगता है।

वैध व्यापार ⇒ तिजारत

→ 11वी + 12वी 5yP ⇒ विभिन्न कृषि फसलों के MSP को तेजी से बढ़ाया गया।

⇒ वनाधिकार Act, 2006

⇒ लघु वनोपज मूल्य नीति अपना रही ⇒ आय ↑

उपभोग स्तर ↑ ⇒ गरीबी ↓ ⇒ MSP ↑

(MSP)

कीमत नीति का अर्थव्यवस्था तथा विशेषकर कृषि क्षेत्र में महत्त्व :

(आर्थिक संवृद्धि व समावेशन)

क्षमता < महँगाई

Que :- सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की समृद्धि/ज्ञाति के लिए कृषि समृद्धि के imp. को उजागर करें।

Que गाँधी ने कृषि अर्थ पर क्यों बल दिया, इसमें छिपी आंतरिक अंर्तदृष्टि को उजागर करें?

Que :- मूल अधिकारों की प्राप्ति में कृषि की अर्थ को सर्वश्रेष्ठ ...

→ समता

'b(0) → संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति; → साख्य / प्राप्त for व्यापारिक संरचना

संपूर्ण कृषि → संपूर्ण GDP; 54 करोड़ → 45 करोड़ कृषि में संलग्न → agri. growth ↑; 9 करोड़ उद्योग

अधिकांश लोगों को फायदा।

1965 में कृषि नीति

उद्देश्य :- उत्पादक को लाभकारी कीमत

1965 में सरकार ने स्पष्ट कृषि नीति अपनायी ⇓

नीति पर सिफारिश हेतु कृषि मूल्य आयोग

⇓

1965 ⇒ इसकी सिफारिश पर कीमतें घोषित

(MSP) why न्यूनतम कहते हैं।

⇓

FCI का गठन

⇓

ताकि अनाज खरीद सके।

कार्य → खरीद, भण्डारण, बाजार में विक्रय

कीमत स्थापित

1965 ← नेशक

बफर भण्डार → P & S के संतुलन हेतु

रैस्ता भण्डार → (अलग) खरीद - विक्रय करके कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित किया जाये

इसे में PDS भी शुरू ⇒ खरीदा गया अनाज जनता तक

→ HYV बीज का आयात (65 में)

66 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में

उन्नत बीज कार्यक्रम शुरू किया गया

(उद्देश्य :- विभिन्न भारतीय फसलों के संकर ब्रिड बीज विकसित करना)

66 => किसान तक पहुँचाने हेतु => बीज वितरण अभियान (Lab to Land)

(65) 65 में ही पूसा को दिल्ली लाया गया

ICAR का पुनर्गठन किया

R & D पर बल दिया गया

~~लैबोरेटरी to लैंड मूवमेंट~~

1971 :- दाण्डेकर एवं रथ महोदय ने गरीबी का पहली बार आकलन किया।

आधार :- R 2100 कैलोरी · U 2100 कैलोरी

आधार ⇒ भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के हिसाब के आधार पर

→ why this - उस समय के अनुसार अनुकूल परिभाषा

संभवतः उद्देश्य : उक्त कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन

1973-74 => ~~गरीबी का~~

(55%) योजना आयोग ने गरीबी का व्यवस्थित आकलन शुरू किया

(93 के लकड़वाला समिति स्थापित)

(37%) 93 →

आय उपलब्धि के आधार पर गरीबी को पहचानते

↓

व्यय/उपभोग विधि द्वारा आकलन

↓

93 से " यह शुरू

↓

इसमें कमी

↓

09 सुरेश तेंदुलकर समिति

↓

2010 में उसके आधार पर उपभोग संबंधी नया मानक स्वीकार किया गया

(+)

- मानक पहले से बड़े
- उपभोग basket बढ़ा

आंकड़ों को संग्रहण

↓

NSSO डेटा

near poverty पर क्यों सर्वे होगा पर आधारित हैं

समस्या → people [illegible] [illegible] गरीब शामिल नहीं

पुरानी विधि 2004-05 → 27

नयी विधि → 37

MSP को 11वीं योजना में प्रभावी तरीके से लागू
(07-12) ⇓

MSP↑ ⟹ उनकी की आय ↑

↳ FCI की खरीद ↑

↳ अनाज भण्डारण

(−)

but भण्डारण क्षमता नहीं बढ़ा

~2007 → गाँव का कोई व्यक्ति गोदाम → FCI रहे पर for 5 year ⟹ किराया देगी

⇓

but नाकामयाब ↓

MSP ⟹ किसानों की आर्थिक कीमत कृषि क्षेत्र करना

भण्डारण ↓

• केन्द्र-राज्य स्तर पर जागरूकता ↓

~ Private के भण्डारण क्षमता की बढ़ायी जाय

खाद्यान्न

खर्च > औसत कीमत (Food Subsidy)

लागत > प्राप्ति of

of सरकार — सरकार

- मुफ्त
- (1997 में श्वेत पत्र पर चर्चा)

⇓

- गुणकारी ↑ (Merit Subsidy) ⟵ (सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति)
  - प्रत्यक्ष रूप से
  - अप्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से
- नुकसानदेह/गैर-गुणकारी (Non-Merit)
  - प्रत्यक्ष
  - अप्रत्यक्ष/परोक्ष

Decide

सर्वाधिक वरीयता गुणकारी राज सहायता को उसके पश्चात को वरीयता ... वहाँ पर आके दोनों को कम करने की बात के लिए

राशन कार्ड

⇒ नये सिरे से राशन कार्ड

⇓

Targeted PDS (लागू) 1997

पूर्व PDS में सुधार हेतु

(i) लक्षित वर गरीबों को (लाल रंग के) राशन कार्ड

(अजुर्री मंत्रालय / हीरो सम्बन्धित है) PDS में क्या खामियाँ / समस्या

निवारण।

गरीबों की पहचान हो ← 1) लक्षित गरीब समुदाय के ऊपर संशय है

(2) => राशन कार्ड देने का दायित्व प्रशासन पर नहीं डाला गया।

सरकार संसदीय पद्म में परिवर्तन

पहल समय से

कार्ड प्रदान

(3) राशन कार्ड का अधिकार भी नहीं है।

एवं खाद्य आपूर्ति विधेयक को मंजूरी

(4) राशन कार्ड मिलने पर भी निर्धारित मात्रा के अनाज नहीं (Fair Price Shop)

कार्य को Compition Act के दायरे में लाया जाये

जनहित याचिका दायर कर सकते हैं

PDS के भ्रष्टाचार

उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो =>

BDO + पंचायत प्रधान के लिए दण्ड का प्रावधान है।

PDS को कारगर बनाने के लिए प्रशासन के मजबूत इरादे लागू।

Prize + Punishment

जहाँ जरूरत वहाँ

पुरस्कृत

आधार कार्ड

- Direct Cash transfer
  ↳ (Kurt जा सकता)

Food Subsidy के मामले में अभी भी DCT नहीं

b coz कीमत स्थिर नहीं
↳ कोटा से कम खरीद की संभावना

भण्डारण
- मात्रात्मक अनाज
- गुणात्मक अनाज → व्यापक बाजार का फायदा
  ↳ FDI मल्टी ब्रांड रिटेल → money, टेक्नोलॉजी ... ध्यान देना चाहिए

कृषि विकास नीति
↳ आपूर्ति की नई नीति
↳ कृषि भण्डारण
↳ कृषि व्यापार
↳

FCI
॥
खरीद + भण्डारण
⇓
राज्य सरकार की निगरानी में F shop से वितरण

कृषि
- अपना विकास
- कृषि की मदद से सामाजिक हित का विकास → ...

केन्द्र सरकार → राज्य सरकार को नियत कीमत पर अनाज जारी ⇒ Issue Price (निर्गत दर)

MSP
⇓
FCI किसानों से अनाज खरीद

आम तौर पर निम्नतम मूल्य < MSP

डीलर ⇒ निजि दुकान ⇒ उपभोक्ता [illegible]

([illegible])

बाकी अर्थ के भिन्न आ० हिसाब कर्म के लिए कोई तैयारी नहीं

गरीबी का निवारण
⇓
रोजगार विस्तार द्वारा

स्थायी → उत्पादन + [illegible] (उन्मूलन)

अस्थायी → निवारण → जन वितरण प्रणाली

[illegible]

मुख्य उद्देश्य = उन्मूलन

but जब तक उन्मूलन नहीं

तब तक निवारण

कृषि विकास की रणनीतियाँ

1965-66 से 1995 तक

① **तरीका** (नवीन उत्पादन तकनीक) (NAT)
- उन्नत बीज ⇒ (समय के साथ प्रतिरोधी फसलें)
- रासायनिक उर्वरक
- सिंचाई व्यवस्था (पर्याप्त एवं समय पर) ← भारी बहुद्देशीय परियोजना / हानि पर्यावरण

② **उद्देश्य** है खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

80's में प्राप्त की

80 के दशक में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग के फलस्वरूप ⇓ काफी सस्ता उपलब्ध ⇓ उपयोग बढ़ा ⇓ उत्पादकता ↓

- अनाज में रसायन अवशेष
- गुणात्मक अनाज के दानों का पोषक तत्व ↓

③ क्षेत्रीय विषमता
(30-40 में ज्यादा work)

पश्चिम ← तेजी से — पूर्व

65 के बाद पलायन

1996 — अब तक

नई कृषि विकास रणनीति

① NAT – 2
- a) Genetically Modi. बीज
- b) कीटनाशकों का संतुलित उपयोग
  (+) ↳ मात्रा में वृद्धि हुई
- c) 1992; Earth Summit ⇓ पर्यावरण संतुलन जरूरी ⇓ पर्या० संतुलन
  - सिंचाई परियोजना
  - जैव उर्वरक
- d) क्षेत्रीय संतुलन पर बल
  - पूर्वी भारत में हरित क्रांति

नई खनीति → III गत

(4) अनाज < गेहूँ, चावल

फसल संरचना का विविधीकरण विशेषतः फल व सब्जियों को वरियता
नई किस्म ↑ → दलहन, तिलहन

(5) सिर्फ कृषि ↑

(6) कृषि संबंध क्षेत्र (पशु०, मीटपालक, कुक्कुट) → वरीयता

(6) आत्मनिर्भरता के बाद भी अनाज ↑ तो क्या ⟹ यहाँ कल्पना पर बल

जरूरत < उपलब्धता
⟹ निर्यात ↑
(निर्यातोन्मुखता)
⇓
प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात ↑
⇓
⟹ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर बल
(गुणवत्ता संबंधी मानक)
⇓
FDA (फूड & ड्रग अथॉरिटी) का दायरा ↑

(7) 65 में गुणवत्ता ↓

(8) no authority

what new before 65's
पूँजी स्थान ⟹ उत्पादकता ↑
श्रम स्थान ⟹ उत्पादकता ↓

मशीनीकरण in both

बाजार का रूपान्तरण

क्रान्तिवादी ← विपरीत
प्रगतिशील ⟹ परिवर्तन को स्वीकार

1947 → 1988 → 1993

व्यापारिक
उदारीकरण
वार्ता

उरुग्वे दौर की
वार्ता

94 में मराकेश संधि
समझौते के क्रिया० की निगरानी हेतु ⇒ WTO

IInd G.R. ⇒ भूमण्डलीकरण के दौर से तात्पर्य
(96)
Q.19 वैश्वीकरण के दौर में कृषि विकास की रणनीति क्या है?

↳ निर्यातोन्मुख रणनीति (विदेशी विनिमय की कमी 44%)

World Market Survey

प्रोसेस्ड फूड के निर्यात को बढ़ावा

(—)

- सकल सीमांत ↑ b(o)
कृषि मांग

हेत-उत्पाद eggs

95 में कृषि सर्वेक्षण

Ist GR से वंचित ← 87% किसान सीमांत एवं लघु

NES ⇒ कृषि व्यवसाय को सभी वर्गों के लिए imp

समाज का नजरिया ⇒ केन्द्रीकृत
⇒ क्षेत्रीय संतुलन
अन्य — पूर्वी भारत

(−)
↳ क्रियान्वयन सभी स्तरों पर समान नहीं
↳ पूर्वी भारत में ज्यादा काम नहीं
SRI (सिस्टमाइज राइस इन्टेंसीफिकेशन)

और गुणों सब्सिडी (व्यापक समाज को फायदा नहीं) ↓

गुणकारी सब्सिडी (जैव उर्वरक) ↑

2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति अपनायी
↓
उक्त same बातें सम्मिलित

25% ↓ सूखा प्रभावित क्षेत्र
50% ⇓ सूखा ग्रस्त क्षेत्र

→ नैसर्गिक हानियाँ (फसल बीमा)

नई रणनीति के तहत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
↓
(−) क्षेत्रीय विषमता का दोषारोपण (उदा. — गुजरात के मामले)

↳ फसल बीमा योजना को लागू करने हेतु अलग से कंपनी — Agri. Corp. of India Limited
Ins. (2000)

अगस्त 2000 में बीमा में FDI एवं
निजि निवेश की अनुमति

FIIS ⇒ (Farm Income Ins. Scheme)

(...) प्रावधान
अनाज मात्रा की क्षति की
ही पूर्ति होगी कीमत की नहीं
• – मात्रा

मात्रा + कीमत
दोनों क्षति
की पूर्ति

2004 में बंद → b(c) विरोध
⇓
MSP को बढ़ाने पर बल दिया

MSP + NAIS / FIIS
⇓
इस
↳ कृषि का बाजारीकरण
⇓
∴ रोक,

कृषि व्यापार
↓
21 करोड़ कृषक (विक्रेता)
3 करोड़ व्यापारी (क्रेता)

विक्रेता > क्रेता
⇓
माग में गिरावट आयेगी
⇓
माग↓
∴ MSP ↑ जरूरी

सरकार ने माना कि
पहले व्यापारियों की संख्या
बढ़ाये +
निवेशकों को भी आकर्षित
करेंगे। ताकि
↳ विक्रेता < क्रेता
↳ निवेशकों का आकर्षण
↳ भण्डारण क्षमता का
विस्तार करेगी
↳ बिजनेस कल्चर को बढ़ावा

- अग्रिम राशि → महाजनों पर निर्भरता ↓ ⇒
- ~~लाइसेन्स का~~ ~~बिचौलिया~~ ↓

~~MSP~~ खरीद कीमत + विक्रय कीमत में अंतराल

- स्वास्थ्य ~~प्रसंस्करण~~ कीमतों को सुनिश्चित कीमत

(पदार्थ के विपणन संबंधी कार्यों को संचालित करना) ⇐ विपणन संबंधित लॉजिस्टिक

खरीद → भण्डारण → पैकेजिंग → डिलीवरी ⇒

Trader — Merchant
- मण्डी
- कई व्यापारी
⇓ पूँजी अभाव

(Farmer उत्पादक) → (Merchant)
⇓ पूँजी अभाव ↓

⟹ (मल्टी ब्राण्ड ~~व्यापारिक~~ सौदागर के आने से) ⇓ व्यापारियों को Contract पर रखेंगे।

(मल्टीब्राण्ड स्टोर)

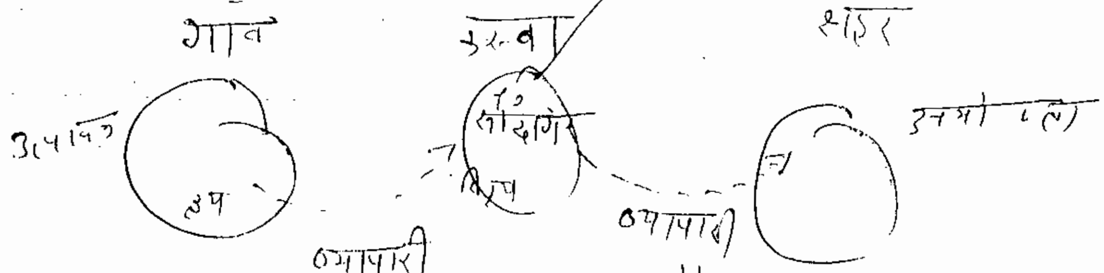

व्यापारी
⇓
Backward linkage
(मूल आपूर्ति को जोड़ेगा)

व्यापारी
⇓
Forward linkage (जो बाजार से जोड़े)

⇒ If FDI ↑ ⇒ सौदागर की संख्या ↑

उपरमाउंट
Chemist of Shop

FDI — (4)

- Receipt मालिका कम होगी
- संविधान पेशा की स्वतंत्रता को परिसीमित
- निर्यात ↑
- तकनीकि क्षेत्र में सुधार

Ques IInd G.K.
फायदा किसानों को कैसे प्राप्त होगा

Ques कृषि विकास रणनीति एवं इसकी नीति का व्यापारिक सुधार के संदर्भ में व्याख्या करें।

(National Agric Federation) नेफेड

राज्य विपणन संस्था (हरियाणा) व्यापार

for कृषि पदार्थ के

जिला बाजार समिति → कृषि के संविदत् कीमतों का निर्धारण

झारखण्ड " "

FCI → NAFED
अनाज खरीद

निवेश — आन्तिक मार्केटिंग

सहकारी संस्थाओं को सुधार

∴ संशोधन = सहकारिता कानून में स्थापना

पशुपालन का अर्थशास्त्र

नवमी एवं 11वी योजनाओं में कृषि नीति

1996– 2000 ⟶ 2001

AEZ scheme =>

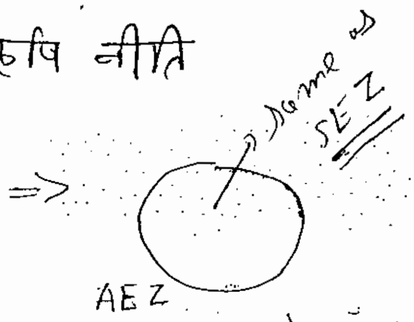

- सबसे ज्यादा आम हेतु — पुणे - अंगूर, मुरादाबाद → बासमती चावल
- 7 तरी बिहार — लीची

{ आलू खरीद — पैकिंग, प्रोसेस करने की इकाई — निर्यात }

Process ↑ ⇓ घरेलू बाजार में S ↓ ⇓ कीमत ↑

कीमत ⟹ किसान लाभान्वित

जमीन महंगी ⟹ भूमिहीन कृषकों की परिस्थिति ↓

AEZ

(+)

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ↑
- रोजगार → अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल
- विदेशी मुद्रा प्राप्ति ↑
- कृषक वर्ग की आय ↑
- R - U विषमता ↓
- कुशल उपयोग की प्रवृत्ति ↑ (wastage ↓)
- कृषि पर pop. की निर्भरता ↓

(–)

- भूमिहीन व भूमिहीन कृषक के विषमता ↑
- खाद्यान्न महंगाई ↑ (MSP, मांग ↑, ↓ उत्पादन)

कृषि व्यापार बढ़ने से फसल उत्पादन की उपज पर निर्भरता कम हो रही है। ⟹ पेशागत संरचना में और कृषि पेशे के पक्ष में रूपांतरण हो रहा है।

Q. अफ्रीका के भूखमरी दूर करने में भारत की क्या भूमिका? — Diplomatic Benefit

(2007, मई) है — नई कृषि नीति

राष्ट्रीय कृषक विकास नीति है

2000 की नीति का ही अनुसरण (thoroug changing)

- देश में खाद्यान्न फसलों को प्रोत्साहन
- बेहतर ग्रामोन्मुख नीति ...

डीजल मल्य — (S) → मानक बीज खरीदकर
उर्वरक
रसायन फसलों को बचाना
→ परंपरागत सिंचाई के संसाधनों की सफाई
कृषि उपस्कर
की राज्य सहायता
में use.

2006 में नरेगा ⇒ मजदूर महंगे ⇒ मशीनरी को बढ़ावा

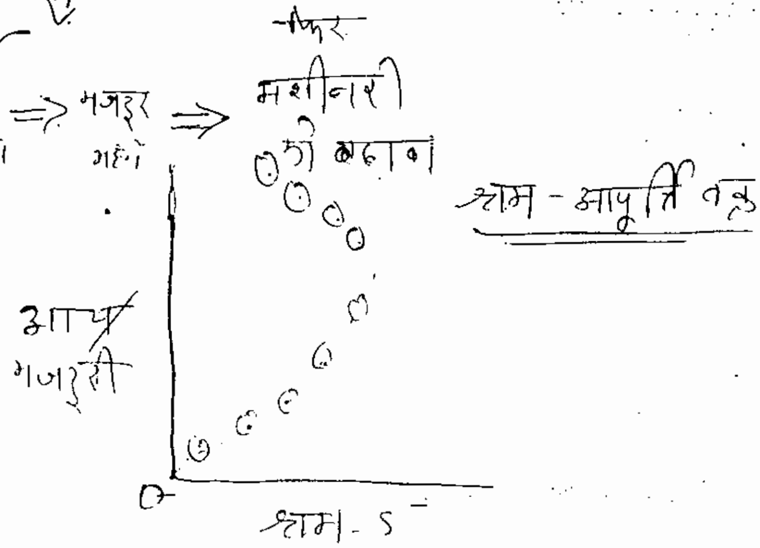

श्रम की उपयोगिता
आराम की उपयोगिता

(+) सुनियोजित एवं नियंत्रित मशीनीकरण
श्रम S. एवं मशीन S में तालमेल बिठाते हुए मशीनीकरण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया।
reverse migration

श्रम आपूर्ति में संतुलन ॰

ICOR ↓
उद्योगों का फायदा ↑
कृषि पर आधारित उत्पादन ↑
⇓
GDP ↑

ग्रामीणों की समझ का स्तर
आधुनिकीकृत

- कौशल विकास की प्रेरणा प्राप्त
- अनाज की बर्बादी की मात्रा
अंशतः कम

(−)
- पशुओं के लिए चारे में कमी
- Some times अनियंत्रित (bcoz of सामाजिक–सांस्कृतिक ...)
- कुछ मात्रा में बेरोजगारी
- मजदूरों की मोल-भाव ताकत कम
- मुख्तारों की ताकत ↑

वित्त ↓ ३ए आरक्षण

• राज्य स्तर पर क्रियान्वयनों में विषमता ⟹ लाभ में विषमता ⟹ विषमता ↑ (अन्य प्रकार का)

✓ कृषि संबंधी पूंजी निर्माण / निवेश।

वित्त प्रणाली या वित्त बाजार — आधुनिक

Formal या recognised — औपचारिक या संगठित क्षेत्र:

मुद्रा बाजार (MM)	पूंजी बाजार (CM)
(1) वाणिज्यिक बैंक	(1) विकास वित्त संस्थाएं
(2) RRB	(2) प्रतिभूति बाजार
(3) सहकारी बैंक	(3) निवेश संस्थाएं
(4) कॉल मुद्रा बाजार	(4) NBFC's
(5) रेपो बाजार	(5) उद्यम पूंजी निधियां (venture Capital fund)
(6) मुद्रा बाजार की पारस्परिक निधि (money market mutual fund)	

Informal or unrecognised — परंपरागत:

श्रॉफ, सेट्टी, चेट्टी, सेठ, महाजन, साहूकार, जोद्दार

1991 में आर्थिक सुधार → वित्त सुधार

वित्त :→ मुद्रा उपयोग के अधिकार को कहते हैं।

वित्तीय लेन-देन :- उधार के रूप में निश्चित समय हेतु लेन-देन। (Financial transaction)

परिपक्वता अवधि (वापस लौटाना)

- एक साल से कम → अल्पकालिक मु. वि. → मुद्रा बाजार का विनिमय कहते हैं।
- एक साल से ज्यादा हो → दीर्घ. वित्तीय वि. → पूंजी बाजार का विनिमय कहते हैं।

मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालिक विनिय विधि
पूंजी ,, ,, दीर्घ ,, ,, ,,

⇒ मुद्रा बाजार उत्पादन क्षेत्र में अल्पकालिक निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे उपलब्ध उत्पादन क्षमता के बेहतर दोहन में मदद मिलती है, लेकिन क्षमता में विस्तार सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

यद्यपि आर्थिक संवृद्धि रहती यह गैर-धारणीय

⇒ पूंजी बाजार उत्पादन क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिसके उपलब्ध उत्पादन क्षमता का विस्तार + विविधीकरण सुनिश्चित होता है, जिससे तत्काल आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित नहीं होती है, लेकिन भविष्य में संवृद्धि की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं।

धारणीय वृद्धि हेतु दोनों बाजार जरूरी हैं।

अल्पविकसित देश में जहाँ उत्पादन की क्षमता बहुत कम होती है, वहाँ आरंभिक चरण में C.M. अधिक प्रासंगिक है। कालांतर में जब क्षमता को पर्याप्त विस्तार हो जाता है, तो M.M. की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

1951 में जब आयोजन शुरू तो प्रारंभ में पूंजी बा. अधिक प्रासंगिक '91 में M.M. की प्रासंगिकता बढ़ गयी। 80

M० नरसिम्हम (RBI के 39 गवर्नर) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया व वित्त बाजार के संरचनात्मक सु० की सिफारिशें मांगी गयी। नरसिम्हम कमेटी on financial sector Reform (FSR)

⇓

91 के उतरार्द्ध में रिपोर्ट

⇓

92 में SEBI ACT ⇒ 93 में गठन → related with प्रतिभूति M०

- 93 में RBI ने नए बैंक को स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित

- 1919 की के ईन्तिरी (1930) → Bank for International Settlement (BIS)

निवारार्थ हेतु

↳ UN के बाद कार्य ने कार्यालय

⇓ दुनिया के कुछ देशों के केन्द्रीय बैंकों का संगठन / स्थापित स्थान

⇓ BASEL

⇓

सम्मेलन

⇓

1986 - 88 ⇒ विभिन्न देशों के बैंकों के लिए कुछ मानक विकसित किये ⇒ सभी देशों को अपनाने को कहा ताकि बैंक एकरूपता, पारदर्शिता

⇓

बेसल मानक

नरसिम्हम कमेटी ने इन्हें समाहित किया

⇓

1995 के WTO, SE

⇓

96-97 → S.E के साथ

⇒ इस संदर्भ में बैंक

(ताकि Beeबराबरी ना) 1998 के दुबारा मानक ⇒ बेसल-II

⇒ 1997 में नरसिंह II समिति

98 में सिफारिश (सिफारिश acc. to बेसल-II)

2008 में वित्तीय संकट

2008-10 ⇒ बेसल-III मानक

2011 में लोकसभा ⇒ संसद ने बैंक संबंधी कानून में संशोधन

Green Bank स्थापना का लाइसेंस

वाणिज्यिक बैंक

- अनुसूचित वा० बैंक (SCB's)
  - 18 (सार्वजनिक)
    - SBI's 8 — राष्ट्रीयकृत
    - 19 बैंक — राष्ट्रीयकृत
  - 22 निजी
    - 15 पुराने
    - 7 नए (छात्र में नहीं)
  - विदेशी (41) (N?)
- गैर-अनुसूचित

RBI Act, 1934

Banking Regulation Act, 1949 (बैंकिंग विनियमन अधिनियम)

Company Act, 1956

SCB's ⇒ BRA, 1949 के प्रा० के अनुसार जिस संस्था को वाणि० बैं० के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे वाणिज्यिक बैंक कहते है,

एक ऐसी वित्त संस्था, जो मुख्यतः चेक द्वारा निकासीय जमा राशि के दोहन के लिए अधिकृत हो, तथा जो साख-सृजन की मदद से तरलता आपूर्ति की विशिष्टता रखते वा० बैंक कहलाते हैं।

SCB's :→ RBI Act की दूसरी अनुसूची में शामिल वा० बैंकों को, जो RBI के मानकों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, SCB's कहते हैं।

गैर-अनु० बैंक → दूसरी अनुसूची में नहीं
RBI के मानकों के अनुसार
काम करना compulsory नहीं

गैर बैंक
C. Act, 1956
के तहत

NBFC
प्रतिनिधि bank
वाणिज्यिक बैंक का
कार्य करती [illegible]
C. Act, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

देशी वा० बैंक :- जिन वाणिज्यिक बैंक के स्वामित्व एवं प्रबंधन क्षेत्र में आधे से अधिक शेयर देश के निवासियों के हाथ में हो, उन्हें देशी बैंक कहते हैं।

विदेशी बैंक :- (NRI + विदेशियों के पास 51% शेयर)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक :- स्वामित्व + प्रबंध अधिकार का अधिकांश (50%) राष्ट्रपति के पास हो

निजी क्षेत्र के बैंक :- जिन के स्वामित्व + प्रबंधन का अधिकांश निजी हैसियत से भारत के निवासियों के पास हो।

नए निजि बैंक :- नरसिंहम् समिति द्वारा सुझाये गये नए बैंकिंग मानकों के अनुसार 1994 से स्थापित निजि बैंकों को नए नि० बैं० के वर्ग में रखा जाता।

पुराने निजि बैंक :- 91 से पहले पुराने बैंकिंग मानकों के अनुसार स्थापित।

निजि बैंक के रूप में पंजीकृत ऐसे बैंक, जिनके स्वामित्व एवं प्र० नियंत्रण को सरकार ने बलपूर्वक अधिग्रहण कर लिए → अधि० के बाद राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में वर्गीकरण किये गये।

(1969 → 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत; 1980 → 6)

20 → 14 + 6

New Bank of India → 1993 में PNB में विलय → now राष्ट्रीयकृत 19

2001 में → बैंक ...

गैर रा० → सरकारी क्षेत्र के ऐसे बैंक जिनकी सरकारी संस्था के रूप में ही स्थापना हुई थी, अर्थात बाजार आधारित मोलभाव द्वारा अन्य किसी विधि से बिना बल प्रयोग किये अधिग्रहण किया गया।

SBI, IDBI

गैर राष्ट्रीयकृत
- SBI समूह (1+5)
- अन्य IDBI

Before ←—— ग्रे ——→ After

सार्वजनिक की हिस्सेदारी ज्यादा

o— विदेशी + नए निजि

o— PSB का कारोबार हर

विदेशी + नए निजी बैंक

SBI ब्रांच

5000 ——→ 22,000

~~Ques~~ ~~[illegible]~~

तुलन-पत्र (Balance - Sheet)

किसी भी सं॰ या Co. का ऐसा वित्तिय व्यक्तव्य, जिसमें उसकी परिसम्पत्तियों का मूल्य, उसकी दैयता अर्थात् देनदारी का मूल्य तथा इन दोनों के बीच अंतर व्यक्त करने वाला मूल्य दर्ज हो, संस्था का तुलन-पत्र कहते हैं।

दैयता के तीन स्रोत
1) स्वामित्व पूँजी
2) ऋण ,,
3) जमा ,,

देना ऋ

धन − दैयता = निवल परिसम्पत्ति
12000 − 10,000

+ve नेटवर्थ

स्वामित्व पूँजी में ज्यादा

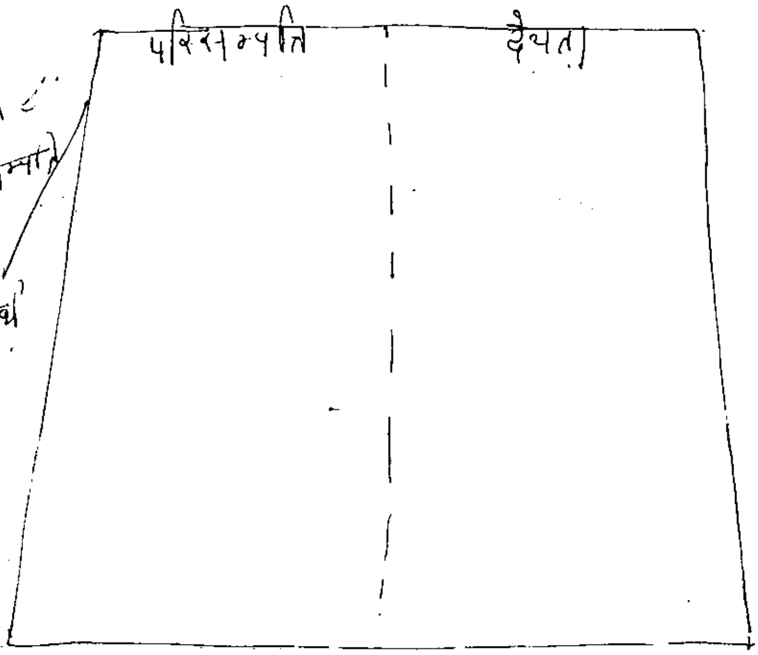

i) निवल (+) है, तो गुलाबी तुलन पत्र (Pink B.S.)
ii) निवल (−) है, तो ~~+ve~~ −ve नेटवर्थ => लाल B.S.
iii) निव (0) है, तो उदासीन B.S. => 0 B.S.

Black B.S

अगर किसी संस्था का B.S लगातार
(तीन वर्ष Red => दिवालिया B.S.
ऐसी C. को => ,, C. कहते हैं।
=> जिसका पुर्नस्थापना संभव है संभव => Revivable week Inst. कहते हैं
,, ,, ,, नहीं + बाहरी मदद की जरूरत => रुग्ण संस्था

(बड़ी, मध्यम, लघु) ← 1960 के दशक से 80 के शुरुआत तक रुग्ण हो जा रही थी। इसे Indust. sickness कहा गया

⇓

संसद ने (1985) में कानून बना।

⇓

(SICA) Sick Industrial Companies Act, 1985

⇓

↳ संस्था की स्थापना ⇒ 87 में कार्य प्रारंभ ⇒

⇒ BIFR (Board for Industrial & financial Reconstruction)

87 में ही लोक उपक्रम में सुधार हेतु सिफारिश आमंत्रित करने की मंशा से अर्जुन सेन गुप्ता समिति का गठन किया गया। ⇒ 1988 में सिफारिश प्राप्त

⇓

सारांश → लोक उपक्रमों को रा० एवं प्रशासनिक दखलंदाजी से मुक्ति दिलाने हेतु प्रबंधन संबंधी स्वायत्तता दी जाये। स्वायत्तता देने के लिए संबंधित विभाग के मंत्री + लोक उपक्रम के निदेशक मण्डल के बीच समझौता हो।

(MOU) ⇒ 88 में शुरू ⇒ 91 में व्यापक बनाया

(1985) में बैंकों में सुधार हेतु RBI ने एक समिति गठित की ⇒

87 ⇒

राष्ट्रीय असंगठित उद्यम आयोग (अर्जुन सेन.)

बैंक के देयता के तीन घटक

1) स्वामित्व पूँजी :- बैंक के मालिकों द्वारा निवेशित पूँजी (टीयर-1)

स्वामित्व शेयर प्रमाण पत्र or शेयर बेचकर उगाही गयी पूँजी को स्वामित्व पूँजी कहते हैं।

बेचे गये शेयर का जितना हिस्सा देश के निवासी खरीदते हैं, उसके मूल्य को घरेलू निवेश कहते हैं। जिसके दो घटक होते हैं।

- जितना हिस्सा निवासी व्यक्ति खरीदते हैं, उसे स्वामित्व डोमेस्टिक निवेश (GDI) कहते हैं।
- घरेलू निवेश का शेष हिस्सा ⇒ जिसे देश की निवासी संस्थाएँ खरीदती हैं ⇒ उसके मूल्य Dom. Invest Institu.

बेचे गये शेयरों का जितना % हिस्सा विदेशी निवासी ⇒ खरीदते हैं, उसके मूल्य को विदेशी निवेश (Foreign)

- FDI: विदेशी निवेशक ने यदि भारतीय Co के 10% या उससे अधिक शेयर खरीदा है व प्रबंधन संबंधी निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिला है, तो वह निवेश
- यदि वि० निवेशकों ने भा० Co में 10% से कम शेयर खरीदा है, तो उस निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो नि० कहते हैं।
  - QFI
  - FII

यदि विदेशी लोगों ने भा० C. में 10% से कम शेयर खरीदे

QFI कहते हैं। ⇒ 1 Jan, 12 से अनुमति

FII :- यदि विदे० संस्थाओं ने भा० C में 10% से कम शे० खरीदे हैं।

91 से पहले भारतीय बैंकों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी, तो भारतीय बैंक पूँजी उगाही हेतु पूर्णतः D निवेशकों पर आश्रित थे। ∴ कम पूँजी जुटा पाते थे।

→ C. के व्यवसाय का शाखा प्रसार करना हो (क्षमता प्रसार)

(कम पूँजी, नहीं देती, को स्थापना)

चूँकि वि नि↓ ⇒ क्षमता प्रसार

नरसिम्हम समिति ⇒ बैंकिंग उद्योग की सतत प्रगति हेतु वि० नि० के उदारीकरण की सिफारिश।

प्रभाव :- वित्तीय समावेशन ↑

⇒ 49% FDI (सरकारी)

74% की सीमा निजि देशी बैंकों

100% ⇒ विदेशी बैंकों में

बेसल I ⇒ टियर - I Capital को मज़बूत

बेसल - II

विदेशी निवेश को सीमा बढ़ायें

बेसल III ⇒ और बढ़ाने की बात

⇒ FDI को भी दो वर्ग

ग्रीन फील्ड FDI (हरित क्षेत्र)

ऐसा FDI, जिससे ना सिर्फ शेयर का स्वामित्व परिवर्तन हो बल्कि उत्पादन क्षमता का (विस्तार) + (उन्नयन) भी हो → (GDP की संवृद्धि की आधारभूत शक्ति)

ब्राउन फी. FDI (धूसर क्षेत्र) ऐसा FDI जिससे शेयरों के स्वामित्व में परिवर्तन हो, लेकिन क्षमता विस्तार या क्षमता उन्नयन ना हो।

भारत की FDI नीति के तहत ग्रीन फील्ड की परिभाषा + ब्राउन फी. पर संदेश

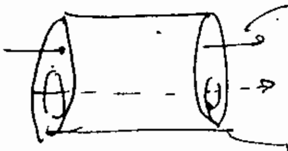

(सिर्फ RBI का अनुमोदन / स्वचालित मार्ग)

सरकारी अनुमोदन मार्ग

(RBI अधिसूचित) FIPB — ₹1200 करोड़ तक

कैबिनेट का भी अनु. — 1200 करोड़ से अधिक

ब्राउनफील्ड FDI (–) / (+) मौजूदा के बेरोजगार पुर्नवास

टियर पूँजी — Tier I + II

(पूर्णकालिक व्यापार)

ऋण पूँजी / टियर-II निश्चित ब्याज की शर्त पर उधारस्वरूप में ली गई पूँजी को ऋण पूँ. कहते हैं)

वित्तीय व्यवस्था → नया ऋण → source

ऐसी ऋ. जिसकी (ऋण पत्र) बाण्ड

परिपक्वता अवधि ~~1 वर्ष से अधिक~~ +

शुद्ध इसी पूँजी लगाई जायें, ऋणी को बेचने वाली संस्था की स्वामित्व में हिस्सा नहीं, बल्कि शेयर में हिस्सा मिलता है।

(ऋण पत्र की परिपक्वता अवधि एक साल से कम)

डेब्ट + बाण्ड को कारोबारी कम्पनी ने बेचा

↓

कारोबारी ऋणपत्र

कारो. बा / कारो. ऋ

ऋणपत्र को बेचा by सरकार ने (S/C) तो सरकारी ऋण

ऋ. बां. / ऋ. ऋ.

सरकारी हुण्डी को ट्रेजरी बिल कहते हैं।

सरकारी ऋणपत्र / सरकारी प्रतिभूति / Govt. Securiti / [illegible]

Domestic Comercial Borrowing ⇒ घरेलू वाणिज्य पूँजी → घरेलू बैंकों से उगाही

ExCB ⇒ विदेशी ऋण " ⇒ विदेशों से उगाही गई पूँजी

Before 91 → ECB की अनुमति नहीं थी ⇒

नरसिम्हम ने बैंकों ECB उगाने की अनुमति ?

सरकार ने माना

92 में SBI ⇒ ECB ($400 करोड़) ⇒ (FDBS विकास Demat + Bond Scheme)

उद्देश्य → ग्रामीण क्षेत्र में शाखा प्रसार

ECB के तत्काल का अनुमोदन ↓ use विदेशों में कारोबार प्रसार

शाखा की → BOB

Corect ⇒ SBI Country

SBI → 1998 → जागो भारत (Resurgent India Bond)

ECB की सीमा है लेटवर्ष का 200% – 500 मिलियन $ maxim.

2000 ⇒ India मिलेनियम डिपोजिट स्कीम (IMDS) ⇒ $500 c.

SBI विदेश में ⇒ RBI

टियर – I

I और बाध्यकारी देयता

II बाध्यकारी देयता

बाह्य निवेश को प्रसार

लाभांश ⇒ आवश्यकारी + गैर-आवश्यकारी देयता नहीं

टियर-III पूँजी है – [illegible] होल्डर्स certificate (HC)

(जिसमें शेयर एवं ऋणपत्र के लक्षण वर्ष-2 विद्यमान हैं)

N.C. के बेचने से जो पूँजी ⇒ T-3 पूँजी

प्रतिभूति संविदा अधि० 1956

विशेषज्ञ समिति

जमा पूँजी

- (10%) ← चालू खाता → चालू जमा
- अदेशित (time Deposite) 4% ← बचत खाता → बचत "
- } इन दोनों को मिलाकर CASA जमा कहते हैं। ⇓ (Current अकाउंट & Saving account)
- 7.5% ← आवर्ती " → आवर्ती "
- ← सावधि " 7.5 – 8.0 → सावधि "
- आवधि जमा — अवधि के समाप्त होने पर ही निकासी
- ← FCNR खाता
- ← NRER "
- ← NRO " → Non resident ordinary account
- } ⇒ अनिवासी जमा

फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेन्ट बैंक अकाउन्ट ⇓ 1 to 3 years हेतु जमा ⇓ आवधि

नान रेजीडेन्ट एक्सटरनल Rupee account ⇓ as a बचत जमा ⇓ कमी पैसे

FCNR + NRER को मिला।

CASA जमा / माँग जमा ← bcoz खाताधारी जब माँगे, तब निकासी होती है।

टिप्पणी :- 1985 से पहले अनिवासी जमा को आकर्षित करने के लिए किये गये प्रयास कमजोर थे।

85 से ही बैंकों ने तेजी से इसे आकर्षित किया, जिससे अनिवासी जमा राशि बढ़ने लगी। 91 से और भी प्रयास किया जिससे increase। वर्ष 2000 में (फेमा - 99)

लागू हुआ। इसके पश्चात बैंकों ने और व्यापक रूप से अनि० जमा को आकर्षित किया। अब उनकी जमा पूंजी में अनि० जमा का उल्लेखनीय अंश है।

सकारात्मक प्रभाव है →

$↑ ⇒ आयातक C को नुक्स।

(1) आयातकों हेतु विदेशी मुद्रा की सुलभता बढ़ती जा रही है।

(2) → NOW → निर्धारित जमा ⇓ $ उपलब्धता ↑ ⇓ बाजार में S↑ ⇒ D↓ र↑

बैंकों से पहले विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति नहीं ? → 91-92 ⇓ आंशिक

(3) विदेशी मुद्रा बाजार में बैंकों की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जिससे विनिमय दर में स्थायित्व लाने में थोड़ी मदद मिल रही है।

25 7 CRR 100 SLR 20 ← 68 75 32 25

(3) भारतीय कामगार द्वारा आमदनी की बार बार कम की जमा (रेमिटेन्स) ⇒ विदेशों में कार्यरत नागरिकों द्वारा अपने देश में भेजी गयी राशि।

(4) अनिवासियों द्वारा भारत में निवेश को बढ़ाता मिलता है।

निवेश → वास्तविक सम्पदा; शेयर बाजार

हर जमा राशि में निश्चित ब्याज दर

अनिवासी जमा का ब्याज दर परिवर्तनशील

परिस्थिति

	gain of acc.	जमा देयता	निकासी
0%	चालू खाता	आरम्भ में अनन्त	आरम्भ अनन्त
4%*	बचत *	अनन्त	सीमित
7.5%	आवर्ती	सीमित	1
5 – 9.0%	सावधि (main aim Interest Rate)	1	1
6%	FCNR		
	NRER		
	NRO		

for कारोबारियों / गृहस्थों के पर –

for all ① साधारण ब्याज दर ② ब्याज पर ब्याज अर्जित

बैंक निः बुकि.

* => 1) ब्याज की गणना 31 मार्च, 2009 तक बचत खाते पर न्यूनतम मासिक शेष राशि पर की जाती थी। 1 अप्रैल को RBI ने दिशा-निर्देश जारी ब्याज की गणना न्यूनतम दैनिक राशि पर करनी चाहिए।

⇓

न्यूनतम दै० शेष राशि मानक अपनाने और ब्याज माप बढ़ गई। इससे बचत खाता पहले से ज्यादा आकर्षक

* 2) 25 Oct 2011, तक बचत जमा I.R. RBI द्वारा प्रशासित थी, और यह 4% थी। 25 Oct, 2011 को ही RBI ने नए दिशा-निर्देश जारी किये। इस ब्याज की ऊपरी सीमा समाप्त कर दी।

=> RBI ने बचत खाते पर बैंकों को ज्यादा स्वायत्तता दी है :-

aim → ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता !, ताकि जो स्टेकधारी मे पैसे जमा उन्हें बैंको से आकर्षित ~~ब्याज~~ मिल सके।

२) औपचारिक प्रसार !!

सम्पूर्ण जमा राशि => ~~प्राथमिक जमा राशि~~ (PDL)

(~~Gross deposit~~ देनदारी)

(GDL)

GDL => SDL + PDL

- ~~सकल~~ जमा राशि को जमा संबंधी प्राथमिक देयता कहते हैं

Primary Deposite liability / मूलधन

- जमा राशि पर देय ब्याज राशि को जमा संबंधी द्वितीयक देयता कहते हैं।

(SDL)

- GDL or GDTL

(G Demand & time/term liability)

सकल माँग एवं आवधिक देयता

NDTL → GDTL – IBL

(इण्टर बैंक लायबिलिटी)

IBL :- अपने खाताधारियों के निर्देश पर खातों के माध्यम से धनराशि के अंतरण को सुचारु बनाने के लिए बैंक एक-दूसरे के यहाँ खाते खोलते हैं, जो प्रायः चालू खाते होते हैं। इन्हें IBL

NDTL = GDTL − IBL
100 = 105 − 5

(नेट Demand & time liability) नम माँग एवं मवधि देयता ⇒ RBI बैंको के विनियमन के संदर्भ में मानकों का निर्धारण NDTL के अनुपात मे करता है। we

विनियामक मानकों का आधार NDTL होता है।

RBI के बैंकिंग संबंधी मानक :-

1) लेखांकन मानक (accounting Norm) :- RBI का निर्देश है, कि सभी अनुसूचित बैंक अपने NDTL को नकद परिसम्पत्ति के रूप में रखाते के तरवाये

It mean's cash Asset ⇒ 100

(why) CRR (Cash Reserve Ratio) :⇒

प्राथमिक उद्देश्य RBI की मदद से RBI के नियंत्रण में वेशाल निधि संचित की जाये, आवश्यक रूप नकदी की समस्या पर बैंको की मदद कर सके।

आरक्षित नकद अनुपात है। (4% of NDTL)

NDTL का वह % अंश, जिसे RBI के नियंत्रण में रखना जरूरी हो CRR कहलाता है।

अनुसूचित बैंको को RBI मे खाता।

⇒ ~~पिछले सप्ताह तक~~ सात्रहांत में उपलब्ध NDTL के ~~4% खाते में~~ RBI के नियंत्रण में चला जाना चाहिए
4%

→ दैनिक रूप से भी वांछित CRR का 70% RBI के लिए आरक्षित करना पड़ता है।

पिछले सप्ताह RBI ने CRR प्रबंधन मानक में परिवर्तन करके 99% कर दिया।

⇓

इससे बैंकों के पास उपलब्ध नकद राशि में कमी आयी

⇓

Liquidity ↓

प्रभाव ⇒ $ की माँग ↓ ⇒ $ की बढ़ती हुई कीमत की प्रवृत्ति पर अंकुश ⇒ ₹ के exchange rate ↓

ऋण क्षमता ↓ ⇒ निवेश ↓ ⇒ G.R ↓

बैंक ग्राहकों को प्रेरित करने का प्रयास ⇒ FD को जमा करने की होड़ ⇒ I.R. ↑

main aim :- इस नीतिगत संशोधन द्वारा RBI ने G. के सापेक्ष ₹ के स्थायित्व को वरीयता दी।

Que :- वित्त मंत्री - RBI गवर्नर में तालमेल की कमी

चिटफण्ड के विनियमन → बैंकों की I R ↑ ; Real estate + गोल्ड में निवेश ↓

चिटफण्ड — विनियमन — प्रतिबंध के बजाए अंकुश (हेतु)

SLR (Statutory Liquidity Ratio) :-

सांविधिक तरलता अनुपात :- NDTL का वह % अंश, जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना जरूरी है, (जिन्हें पूर्णतः तरल माना जाता है) अर्थात् RBI की पूर्व अनुमति के बाद संभवतः अन्य प्रतिभूतियों में अथवा स्वर्ण धातु या स्वर्ण प्रतिभूति में निवेश करने की अनुमति हो। SLR कहलाता है।

सांविधिक :- विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि / Act

Note : हाल में बैंकों द्वारा स्वर्ण धातु में स्व. स्वर्ण प्रतिभूति में निवेश के विकल्प को बंद कर दिया गया है। यह विकल्प 2008 में दिया गया था। ⇒ G Deman ↑

now close ⟶ G Demand ↓

सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं को स्वर्ण खरीद हेतु प्रोत्साहित (बैंक + डाकघरों)

⇓

D. ↑ ⇒ ∴ केवल वृद्धि गहनों के कारण नहीं

(margin: community trade ⇓ स्वर्ण धातु / प्रत्यक्ष संबंधी खरीद बिक्री)

⇒ SLR का प्रा० उद्देश्य है जमा राशि का निश्चित अंश स्वचालित रूप से सरकारी कोष में पहुँचती रहे, ताकि आयोजन संबंधी कार्यक्रमों या कल्याणकारी कार्य० का सुचारु रूप से वित्त पोषण हो।

NDTL → 100
CRR — 5
— 95
SLL — 25
शेष ⇒ 70
ऋण योग्य निधि

→ CRR एवं SLR मानकों के लिए लॉकिंग के बाद शेष NDTL, जिसे ऋण आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है, ऋण योग्य निधि कहलाती है।

- CRR / SLR के साथ ऋण योग्य निधि का व्युत्क्रम संबंध

CRR/SLR ↑ ⇒ तरलता (नकद राशि) ↓
⇓
मुद्रा की आपूर्ति ↓
⇓
निवेश ↓
⇓
G.R. ↓

लेकिन महँगाई पर दबाव भी कम हो जाता है।

→ Anti Inflationary Measures के रूप में SLR + CRR ↑

→ संवृद्धि + निवेश प्रोत्साहन हेतु ⇒ CRR ↓, SLR ↓

Pro-Growth Measures

Ques अभी RBI की वरीयता क्या हो — Inf. / Growth

पिछले 1-1½ साल से CRR ↓ + SLR ↓

CRR + SLR ⇒ आरक्षित अनुपात

भारत - 2013
→ वित्त
→ Priority sector Lending

Qus 12वीं योजना में समावेशी संवृद्धि की रणनीति के अनुसार/मार्ग में वित्तीय समावेशन की क्या प्रासंगिकता है? इस दिशा में कौन-2 से उपाय किये जा रहे हैं।

Measures :-

PSL (प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान) :-

संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की मंशा से वर्ष 1968 में सरकार ने सा० बैंकिंग की अवधारणा अपनायी।

(Banking with social responsibility) सा० दायित्वपूर्ण बैंकिंग / सा० बैंकिंग :- विभिन्न प्रकार के बैंकों का इस प्रकार प्रबंधन, कि मौद्रिक लाभ महत्तमीकरण के उनके कारोबारी उद्देश्य तथा व्यापक सा० लाभ के राष्ट्रीय उद्देश्य में तालमेल स्थापित हो, सा० बैं० कहलाता है।

⇒ CSR मानकों के अनुसार बैंकिंग

इसी अवधारणा के अनु० :-> 1969 में 14 बड़े वि० बैं० को राष्ट्री० कर लिया गया, ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी इलाकों में उनके शाखा प्रसार का वृहद व्यापक अभियान चलाया गया।

— 1970 में जिला स्तरीय बैंकिंग आयोजन को व्यवस्थित करने हेतु अगुवा बैंक कार्यक्रम शुरू किया गया।

⇓

जिले में कार्यरत सभी बैंक के कार्य का समन्वय

⇓ for this

RBI ⇒ एक बैंक को नाम

— 1972 में इन बैंकों को निर्देश दिया गया, कि ऋण योग्य निधि का एक निर्धारित अंश, एक निर्धारित ब्याज दर पर ऐसे ऋण आवेदकों को दें, जिन्हें सरकार ने PS

PS
ऋण वितरण, वे जिन्हें प्राथमिकता दी है, इसका समूह PS गट

का दर्जा दे दिया है।

⇒ PS का दर्जा निम्नलिखित को दिया जा चुका है:-

1) कृषि क्षेत्र :-

2) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र (कुटीर + ग्रामीण)

3) एक निश्चित सीमा तक आवास ऋण
(प्रति व्यक्ति ⇒ 25 लाख रु)

4) शिक्षा ऋण

5) निर्यात कारोबार हेतु ऋण

6) समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य → SC, ST, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य, निर्धन परिवार के सदस्य, अन्य ⇒ (विभिन्न राज्य सरकारों के दिशा-निर्देश पर)

राष्ट्रीयकरण (अ) → अनुसूचित, सामान्य अनुसूचित

देशी बैंक की ऋण योग्य निधि का 40% ⇒ I.R. ⇒ 11% या कम

विदेशी बैंक हेतु सीमा ⇒ 32% ⇒ IR II% या कम

Ques PSL के कारण क्या आवश्यकता ...

← CRR 100
← SLR
PSL 28 (40%) ⇒ सामाजिक आवश्यक
मुक्त ऋण योग्य निधि ⇒ कारोबारी फायदा

नरसिम्हम स. I ने बैंकों के माध्यम से लागू होने वाले कल्याणकारी कार्य का भी मूल्यांकन किया, और पाया कि ये उतने असरदार नहीं सिद्ध हुए, जितनी अपेक्षा थी।

∴ इनमें सुधार की कुछ सिफा. भी।

Ques 90 के वित्तीय समावेशन

91 के पहले

91 के बाद
⇒ पूर्व दृष्टि को असरदार

कितगत नाम की अवधारणा

⇒ DRIS ⇒ (विभेदकारी ब्याज दर कार्यक्रम)
↳ PSL का उप कार्यक्रम
↳ बैंकों का निर्देश दिया गया था, कि जो ऋण अग्रिम BPL ऋण पत्र साख में दे। उसे 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये व गरीब व्यक्तियों को दिये गये ऋण कार्यशा प्राथमिकता। कोष ऋण में 1% या उससे अधिक का होना चाहिए।

असफल नी.दि. आ.

नर० समि० ने यह पाया, कि DRIS लगभग पूर्णतः विफल हो गया, क्योंकि 1% के लक्ष्य के मुकाबले गरीब नागरिको का मात्र 0.01% दिया गया।

ऋण सेवा आपूर्ति की शैली ग्राहकोन्मुखी नहीं थी, ∴ यह कार्यक्रम विफल हो गया। नर० ने सिफारिश की
↳ KYC मानक अपनाये
↳ जरूरतों को समझे
↳ उनकी आवश्यकताओं + सीमाओं को समझते हुए सेवा

⇒ DRIS को बंद करने को कहा, व उसके स्थान पर एक नवीन कार्य० चलाए। (वितरण शैली गलत)

गरीबी ↓ सफलता मी० समानता अधिक

92 में इसे बंद किये बगैर SHG - Bank Linkage कार्य० चलाया
(गरीब व्यक्तियों का समूह बनाये)

जैसे आय० बढ़े-बढ़े सामाजिक योजना का दायरे बढ़ाने

Diff.

DRIS	SHG - Bank
	फिर स्थानीय पंचायत से मान्यता
	BDO द्वारा मान्यता
	बैंक मैनेजर से ऋण हेतु [illegible]

बैंकों पर हावी हैं
गरीबों की उदासीनता

Before 1 year
70 लाख => SHG
प्रति SHG में औसत
संख्या 17

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP - 2008)

- सूक्ष्म उद्यम स्थापना हेतु BPL व APL दोनों को मदद
- शर्त :- प्रमाण पत्र कि संगठित रोजगार में नहीं
- बैंक से ऋण
- if 100 to वापसी 2/3
  बाकि 1/3 => सरकार को लेने की सहा

Que विविध

SHG → क्रियान्वयन हेतु
- पंचायत / ग्राम मुखिया
- NGO => work w पंचायत की पूरक

PSL में लगाये करने हेतु

ऋण आपूर्ति को बढ़ाने हेतु R.V. Gupta समिति => 1996
समिति की सिफारिश => 1997
NABARD ने 1998

इसके तहत बैंकों को ← KCC कार्य० बनाया।
निर्देश कि कृषि क्षेत्र में ऋण आपूर्ति हेतु किसानों को क्रेडिट कार्ड दे।
- (ऋण की सीमा निश्चित => क्रेडिट सीमा)

(+) ऋण अनुमोदन के त्रुटियागत स्तर से मुक्ति
- KCC में निश्चित समय में ऋण जमा, तो no ब्याज
- ← उस सीमा के बाद ब्याज
- कृषि में निवेश की मात्रा ↑
- कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण की गति तेज हुई
- उनकी फसलों के उत्पादन पर अच्छा असर पड़ा

Qus कृषि विकास के बैंकों की भूमिका

↳ किसान को पूंजी प्राप्त by KCC

↳ खाद्य सुरक्षा की दिशा में imp. भूमिका

जुलाई, 2004 में नया कृषि ऋण कार्यक्रम की घोषणा की (New Agri. Credit Scheme – NACS)

↳ इसके तहत बैंकों को निर्देश दिया गया कि रु. 5 से 7 तक कृषि ऋण की मात्रा को दो गुना करे।

2005 में KCC वितरण की दर ↑ + ऋण सीमा ↑

कृषि क्षेत्र में निवेश ↑

2005 में भारत सरकार ने National Food Security Mission ↳ गेहूँ, चावल व दलहन

National हार्टीकल्चर मिशन (रा. बागवानी अभियान)

लक्ष्य से ज्यादा आपूर्ति (2½ गुना)

प्रारंभ में G.R ↓ 2003 ↳ प्राप्त

10th 5YP के आखिर में ऋण S ↑ के कारण कृषि G.R. में सुधार

– मौसम पर गरीब किसानों की निर्भरता।

2007 में KCC complete ⇒ (+) / (–) ↳ NPA ↑

जयदी समिति चोज (↳ कृषक आत्महत्या के कारणों की जाँच हेतु) ⇒ समाधान

आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण ऋण नकल व्यवस्था।

> सूखाग्रस्त इलाकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा

> सिंचाई का कमी

> सरकारी बैंकों का किसानों के प्रति अमित्रवत् आचरण ⇒ महाजनों पर निर्भरता ↑

> फसल बर्बाद होने पर भी महाजन ऋण देगा। ⇒ सीमित ऋण भार ⇒ ऋणजाल

समिति के अतिरिक्त अन्य कारण

↙ सांस्कृतिक रिवाज

↳ दहेज में आत्महत्या

२००५ पर किसान आत्महत्या का मुद्दा ⇒ KCC को ↑ (कृषि मित्र कार्ड)

(बकाया ऋण / ↳ सस्ते ऋण)

⇒ २००८ तक कई नहीं लौटा पाये
⇓
कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम बनाया गया।

(+ ve aim: KCC के प्रति जागरूक करना)

↳ लघु किसानों के बकाया ऋण को पूर्णतः माफ
⇓
(२ हेक्टेयर पर से कम)

↳ गैर-लघु कि. का 1/4 पूर्णतः माफ but जब वे 3/4 को लौटायेंगे।

(+) ऋणजाल से निकल - हित में

नकारात्मक - KCC की माँग काफी बढ़ गई।
⇓
जनाधार पहले से घटाई 08-09 वितरण की गति ↑

⇒ PSL को अधिक प्रभावी बनायी ⇒

(रोजगार सृजन / वैल्यू आउट; 05, 05, 12)

२००३ में लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड शुरू किया → मितव्ययता ↑, निर्गत ↑, गरीबी ↓

निम्न कौशल, आय वाले स्वरोजगारियों के लिए २००३ में (10 लाख 5 yr) स्वरोजगारक्रेडिट कार्ड शुरू किया गया।

Qus ⇒ भारत में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

Qus ⇒ क्या आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास सहगामी है? समीक्षा कीजिए।

Qus ⇒ विकास और समावेशी विकास में क्या अंतर है,

लघु उद्यमी CC के माध्यम से

2nd G. Reform के चरण में " उद्योग का विकास है।

⇒ 1951 से ही लघु उद्यम के महत्व एवं भूमिका

- प्रारंभिक काल = परंपरागत imp. वाला उद्यम ⇒ परंपरागत उद्यमी

ii) SI ↑ ⟶ परंपरागत उद्यमी की आजीविका ↑ ∴ गाँधी जी ने

RBI गवर्नर (new) ⟹ S. I. के विकास पर बल

गरीबी ↓ बेरोजगारी ↓

(1) रोजगार की मात्रा संख्या एवं गुणवत्ता

(2) कुल उत्पादन में भागीदारी / अंशदान उल्लेखनीय है।

↳ उत्पादन संरचना विविधीकृत

कागज I., रसायन I., Gems & Jewe..., स्वास्थ्य प्रसंस्करण में भागीदारी, चमड़े की वस्तुएं निर्मित

(3) सेवा ⟶ होटल रेस्तरां, BPO, पर्यटन, शिक्षा, कुरियर C., परिवहन क्षेत्र में (सड़क), असंगठित वित्तीय बाजार, IT Sector, स्वास्थ्य सेवा, लघु चिकित्सा

electric goods, वस्तु I. (फर्नीचर), इंजीनियरिंग गुड्स, हथ करघा I., वस्तु I. की कताईयां (उदा. ⇒ तिरुपुर)

(4) निर्यात संभावना ↑ ⟶ JLJ हैंडीक्राफ्ट

↳ उत्पाद का 40% विदेश में ⇒ अंत० प्रतियोगिता

=> कमाई का imp. माध्यम

4) क्षेत्रिय विषमता दूर करने मे उल्लेखनीय भूमिका

1951 मे ही सरकार ने इसके imp. को समझा =>

(State finance corp.) SFC Act 1951

↳ राज्य वित्त इकाईयाँ स्थापित → का

कार्य ↳ सस्ता, कम ब्याज पर ऋण

SIDBI =>

↳ सभी SFC के कार्यों का समन्वय करे।

↳ SFC हेतु नीति निर्माण, कार्यक्रम बनाये

↳ SFC को वित्तिय सेवा उपलब्ध कराये

SIDBI
⇓ वित्त
SFC
⇓ वित्त
बैंक को
⇓
लघु उद्यमियों

1995 — WTO

1995 => (आबिद हुसैन समिति)

↳ कार्य वैश्वी. के कारण S. I. पर पड़ने वाले दबाव का विश्लेषण।

↳ वैश्वी. के अवसरों के दोहन हेतु उन्हें और समर्थ बनाने का उपाय बताना।

↳ वैश्विक प्रतियोगिता से अपने बचाव हेतु इनमें कौनसे सामर्थ्य विकसित किये गये है, इसके भी उपाय.

⇓

1996 में अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई।

जुलाई, 96 में वित्त मंत्री ने कुछ सिफारिशों की घोषणा

⇓

S. I. नीति, 1996

⇒ 98 में समिति ने सिफारिश

⇒ 2000 में P.M. ने लघु उद्योग की घोषणा ⇒ PMSSI योजना (SSyP)

इसी के तहत SSI क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई

→ वित्तीय क्षेत्र समस्या के समाधान हेतु टास्क

~~2000 में~~ पुर

⇒ 2000 में प्रशासनिक निर्देश जारी हुए

→ अनावश्यक " इन्स्पेक्टरों को रोका गया।

लघु उद्योगों का संगठन → को विशेष तौर पर प्रोत्साहित ⇒

लघु उद्योगों के उत्पादन → 138 उत्पादों की सूची बना कर दी।

⇒ Industrial Development & Regulation Act, 1951

→ सभी औद्योगिक इकाइयों का विनियमन

now यह वृहत उद्योगों

समिति ने S.I. के लिए अलग Act की बात की।

↓

सरकार ने विधेयक पेश किया

↓

2006 में पारित

MSME विकास अधिनियम, 2006

micro small Medium

↓

this is v MSME

2001 से सीमा में उत्तरोत्तर वृद्धि

इसके तहत लघु उद्यो. ~~की सीमा~~

75 लाख — 5 करोड़ — बाहर 10 करोड़ (अधिकतम) → मध्यम

↓ सूक्ष्म — ↓ लघु

- कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार इसी

में

Ques उदारीकरण के दौर के औद्योगिक सुधार

PSU — MSME — वृहद् उद्योग sections में रोजगार g.R. → 1%

लघु " " " " 40% p / 4.3

वृहद् I.
⇓
पूँजी गहन

SI → ⟶ शीर्ष स्तरीय निर्यातक (10) वस्तुओं में से अधिकांश का ... SSI है।
लघु
श्रम गहन
⇓
भारत के संदर्भ में अधिक imp

मल्टीब्राण्ड रिटेल
Export obligation

⇓
MB रिटेल से 30%

आपूर्ति ↑

घरेलू निवेश — विदेशी निवेश

(−)
- तकनीकी नवीकरण की प्रक्रिया अभी भी धीमी है। जबकि चीन ↑
- कौशल विकास का संस्थागत ढाँचा कमजोर है।
  - प्रशिक्षण संस्था पर निगरानी कमजोर
- राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान शुरू किया गया
- Innovation ↓ ⇒ कौशल में गतिशीलता ↓
- बुनियादी ढाँचा ↓ → बिजली
- परिवहन
- कच्चे माल की मात्रात्मक, कीमत संबंधी समस्या
- लागत संरचना में उच्चावच ⇒ मुनाफे में सुरक्षा
- सरकारों से पूरी राहत नहीं
- नीतिगत समस्या
- गाँव में SSI के विकास हेतु कोई प्रयास नहीं

PURA — ग्रा० औद्योगिकरण ⟹ लागत ↓ ⇒ SSI की प्रतियोगि क्षमता ↑

⇒ जनसंख्या के अनावश्यक पालन

1991 से Look East policy ⇒ पूर्व ... से निर्यात

एशियन कॉपरेशन डायलॉग (एशियाई देशों का गर्त, मंच)
↳ 2003 से तय ⇒ SST के ...

⇓

⇒ 2007 → भारत – चीन संधि,
" – इंडोनेशिया / जापान "
" – आसियान "
} → उक्त समझौते के तहत

(+)

- पूर्वी अंचल के उद्यमी के अवसर बढ़ रहे।
- विपणन को बढ़ावा

– लागत
– प्रबंधन ↓
– Fashion Range
– प्रतियोगी दबाव

उद्यमी की संख्या ⇒ 3 करोड़ है।

National Spost Exchange Limited
(NSEL)

विनिमय
- हाजिर – Spot Exch – माल भाव के साथ लेन-देन (वस्तु-मुद्रा) भी साथ ही ⇓ for उपरान्त। ⇓
- वायदा – forward – जबकि मोलभाव आज but लेन-देन भविष्य में ⇓ for व्यापारी
  (कीमत निश्चित व वास्तविक लेन-देन के बीच time gap)
  ⇓
  (+)
  - कीमत विचलन के उतार-चढ़ाव से बचते हैं
  - सुनिश्चित कीमत पर आपूर्ति

NSEL ⇒ वायदा कारोबारी ~~इसके तहत~~ नियम के इसके तहत समन्वय
⇓
NSEL में कारोबार में शामिल
⇓

=> बाद में MCX बनी

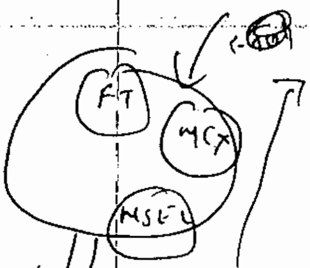

FMC => वायदा कारोबार की निगरानी का काम

शेयरों में भारी गिरावट
b/c of स्वर्ण कीमत ↓

FMC इसकी जाँच कर रही है

both (+ve) (−ve)

Ques :- भारत में दी जाने वाली कृषि सब्सिडी की ~~उपयोगिता~~ प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

समीक्षा → मूल्यांकन + विभिन्न विशेषज्ञों की राय देती है।

(+)	(−)
- गरीबों के सहयोग हेतु	- Misuse (दुरुपयोग)
- समावेशी विकास	- मुख्यतः बड़े किसानों द्वारा लाभ
- खाद्यान्न सुरक्षा	- वितरण पूर्ण नहीं
- नई तकनीकी का use	- पर्यावरणीय समस्या (कुप्रभाव) → ecosystem
- प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ↑	- गाँव में विषमता ↑
- क्षेत्रीय विषमता ↓	
- द्वितीयक + तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि	
- बेरोजगारी ↓	

(बजट पर बोझ)

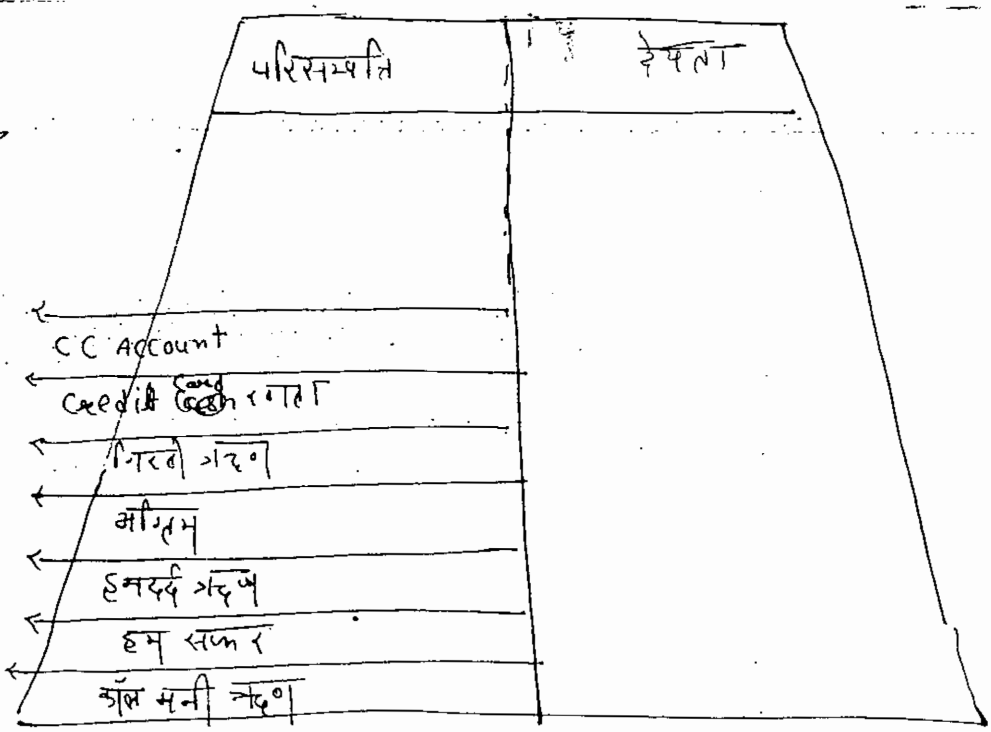

कीमत

कैश क्रेडिट अकाउंट है एक प्रकार का आवृति ऋ॰ खा॰ है, अर्थात् खाताधारी ऋ॰ का उपयोग करता है, धनराशि प्राप्त होने पर ऋ॰ का भुगतान पुन: आवश्यकता होने पर भुगतान ऋ॰। | जैसे → KCC

भुगतान

Only 4 कारोबारी व्यक्तियों / संस्था

Use → only for उत्पादन
not 4 उपभोग

सामान्यतः कच्चे माल की खरीददारी के use, कार्यशील पूंजी के लिए होता है, स्थिर पू॰ हेतु नहीं।

(क्षमता विस्तार) (क्षमता दोहन)

यह ऋ॰ तो " " के अनुसार

CCA ↑ ⇒ I(OR) ↓

Credit C A भी एक प्रकार का ऋ॰

खाता → उत्पादक + उपभोक्ता both,

प्रक्रिया → आवृति होता है।

(ii) माँग की वृद्धि अंशतः अविवेकशील (उपभोक्तावाद ?)

But यह है बैंकों को छूट समाज के विभिन्न व्यक्तियों को हेतु नहीं है। (Survey shows → भारतीय समाज में CC के use की बारम्बारता काफी कम है।)

न्यूनतम के स्तर पर CC हैं ज्यादा पारितोषिक

Ques जिस तरह से श्वेत वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि हो रही है। (जिनका उपयोग व्यक्ति दिखावे हेतु करे) क्या इससे सहमत की समाज के उपभोग में बाढ़ बढ़ रहा है ?

विज्ञापन, जीवन शैली ↓ श्वेत वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति ↓ SC

AC → 91 से पहले श्वेत वस्तु — रेफ्रिजरेटर; 91 के बाद → अत्यधिक महँगी

RBI ने CC पर कुछ अंकुश लगाया है → SC के निर्देश के बाद RBI ने विज्ञापन को सीमित किया।

निष्कर्ष → केवल CC के कारण उपभोक्तावाद नहीं

गिरवी ऋण है किसी सम्पत्ति (वर्तमान व सम्पत्ति) के कब्जा अधिकार (खरीदार) के बदले दिये गये ऋण को कहते हैं।

Ex → Home loan → गहने के बदले

झुकाव है CC का सही use ✓ अनुशासित तौर उपभोगवादी → अभाव की धारणीयता ↓ → सम्पत्ता में पतन ↓ Ex → अमेरिका → 2008

लाभ के संकेत ⇒ bcoz of gold में उछाल

कीमत वृद्धि का cycle

कीमत गिरावट का cycle

Secular वृद्धि Secular decline

Mega trend downward

तरलता को हानि ⟹ शेयरों में गिरावट ⟹ स्थिरता (C)

प्रक्रिया चलती रहे तो 2008 - USA जैसा crisis आ सकता है

अग्रिम ऋण :- भविष्य में मिलने वाली आय/धनराशि के साक्ष्यों के आधार पर दिया गया ऋण।

(i) उदा :- • लोन against बाजारी प्रतिभूति ✓

• व्यापारी के पास भुगतान से सम्बन्धित कागजी प्रमाण पत्र

• किसान की फसल गोदाम के रसीद → ऋ. के आधार ऋण

• निर्यात प्रमाणपत्र के आधार पर पायी गयी प्रमाणपत्र

⇓

ऐसा ऋण पोस्ट शिपमेन्ट लोन कहते हैं।

• निर्यात करने के ऑर्डर के आधार

⇓

प्री शिपमेन्ट लोन

सरकार Aug. ⇒ रिज़र्व बैंक भी सरकार को अग्रिम ऋण (C's)

⇓

इसे अर्थोपाय अग्रिम कहते (Ways & means advance)

by RBI ← WMA

To C and S

संघ ऋण (Consortium Loan) :→

दो या अधिक बैंकों द्वारा आपस में अल्पकालिक समझौता के माध्यम से / के आधार पर दिये गये बड़े ऋ० को C. L. कहते हैं।

सम्मेलन ऋण (Syndicate Loan) :→

दो या अधिक बैं० द्वारा आपस में स्थायी समझौते के आधार पर दिये गये बड़े ऋण को S.L. कहते हैं। ऐसे समझौते में शामिल बैं० के समूह को सिंडिकेट of B. कहते हैं।

C.L. + S.L. से बैं० तंत्र की कार्यकुशलता ↑
वित्तीय आपूर्ति की मात्रा + गुणवत्ता ↑

91 से पहले

C. L + S. L. की जरूरत नहीं
⇓
b'coz D. of बड़ा ऋण ↓
b'coz → निजि C. को एक हद से ज्यादा क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं।
⇓

MRTP (P) Act, 1969
(Monopolistic & Restrictive Trade Practices (Prohibition) Act)
⇓
आयोग गठित → MRTP आयोग

91 के बाद
↳ MRTP का बार-बार संशोधन ⇒ नरम
⇓
ताकि उपयोगों को अवसर

माँग ↓
Industry ↓
⇓
बैं० ऋण की माँग ↓
⇓
सरकार की आमदनी ↓

सिंडिकेट की
terrorism

अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उदारीकरण

आगे चलकर निरसित ⇒ Compitition Act, 2002
(2003 से लागू)

इसी के तहत CCI का गठन
2006 में कार्य प्रारंभ

⇒ इस समय C ने क्षमता में वृद्धि ⇒ ऋण जरूरत ↑

⇒ PSU ↑ ⇒ जैसे :- ONGC, BSNL की स्थापना

ONGC → क्षमता सीमित ← → विस्तार → C.L+S.L. की जरूरत ↑

⇒ 2000 में फेमा लागू हुआ ⇒ विदेशों में कारोबार बढ़ाने का उदार अवसर मिला (Ex :- टेल्को now working in लंदन, चीन, रूस also)

कॉल मनी है → एक दिवसीय ऋण को कॉ. म. कहते हैं, अगले ही दिन वापसी की शर्त पर दिये गये ऋणों। ⇓ ऐसे ऋणों पर तय ब्याज की दर को कॉल रेट कहते हैं जिसे ग्रहण लेने - देने वाले मोलभाव द्वारा तय। RBI/सरकारी हस्तक्षेप नहीं।

why ⇐ Transaction

ऐसे ऋ० की आपूर्ति अक्सर वे बैंक करते हैं, जिनके पास दिन प्रतिदिन के कारोबार के अंत के नकद अधिशेष रह जाता है। ऐसे ऋण की माँग भी अक्सर बैंक ही करते हैं। जिनके पास दिन प्रतिदिन के कारोबार में नकद अभाव की समस्या।

जमा > निकासी

जमा < निकासी

कॉल म० के विनिमय को अंतर बैंक C.M./बाज़ार भी कहते हैं।

आम तौर पर C. दर सभी अन्य ब्याज I.R. से कम होती है, but कभी-2 बहुत ऊँची भी

ex. 1996 (Nov.) 6% ⟶ 138%

bcoz of S. E० में संकट

क्योंकि वित्त पलायन के कारण ⇒ वित्त की कमी ∴ ↑ किया गया।

सामान्यतः C. R. तब बढ़ता है, जब बैंकों के समुदाय में नकद राशि या तरलता का अभाव रहता है। ∴ अन्य ब्याज दर भी ↑

RBI की C. R. की लगातार निगरानी

if C. R. ↑ लगातार ⇒ तो RBI Liquidity देने के उपाय करता है।

if C. R. ↓ ⇒ तरलता ↓ ⇒ सरलता Liquidity घटती tightening

दुनिया C. M. विनिमय का सबसे बड़ा अड्डा (हब/केन्द्र) लंदन बाजार है। लंदन के अंतर्गत बैंक आपस में स्टर्लिंग ऋण का लेन-देन। जिस ब्याज दर पर एक B. दूसरे B. को C.M. देने को राजी होता है, लंदन अंतरबैंक प्रस्ताव दर (London Inter-bank offer Rate (LIBOR)) कहते हैं।

मुम्बई के अंतर्गत बैंक जिस I पर मुद्रा की आपूर्ति ⟶ MIBOR कहते हैं। → SBI, IDBI, → ICICI, ...

(Ques: वित्त मंत्रालय का बयान (मार्केट) ⇒ इसकी ओर C. R. ↑)

उक्त पाँच G-5 बैंक कहते हैं। इनके मध्य की ब्याज दर MIBOR के आधार पर लेन-देन।

FC ← (HSBC) ECB दर ⇒ LIBOR से ज्यादा

ECB की ब्याज दर LIBOR से जुड़ी रहती है, यह ब्याज फ्लोटिंग होता है (अर्थात परिवर्तन होता रहता है।)

यदि LIBOR ↑ ⇒ IR ↑ ⇒ Home Loan ↑ (फ्लोटिंग H.L)

Ans — BOR क्या? रत में क्या महत्व होगा

LIBOR घोटाले की जाँच by ब्रिटेन की संसदीय समिति → UBS बैंक

HSBC का नाम आ चुका है, बार्कलेज, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड

प्रतिभूति

- अंकित मूल्य / Face value → जो शेयर पर अंकित
- बाजार वैल्यू → जिस मूल्य पर विनिमय

पहले F.V. = M.V same ⇒ फायदा खरीददार तक सीमित
⇓
Production में वृद्धि नहीं।

now ⇒ Book building option
⇓
प्रतिभूति इ.स. हेतु बाजार नि. विधि
⇓
G की Growth ↑

AC : 100 करोड़

(निर्गत) IC : 100 रु. (1 × 100 करोड़ प्रमाण पत्र)

(आवेदित) SC : 100 "

(Paid up Capital = चुकता पूंजी) — PC : 75,000 करोड़ (M.V. 750 × 100)

bcoz of BBM ⇒ P C may be high then A C (Book building benefit)

PC − AC ⇒ खाता लाभ

75,000 − 100 ⇒ 74,900

प्रतिष्ठा ठीक नहीं ⇓ CSR करने से प्रतिष्ठा ↑

CSR → B. bu benefit → इस्तेमाल

Ques:- CSR व BBP में relation

Market Capitalisation / M. Cap / M.Cap. ⇒ बाजार में उपलब्ध सभी शेयरों का मौद्रिक मूल्य।

- हुण्डी का बाजार में विक्रय अंकित मूल्य से कम मूल्य पर होता है।
- अंकित से कम मू० पर हुण्डी का विक्रय → हु० का बट्टाकरण कहलाता है। SLR मानक के अनुसार बैंकों के लिए आवश्यकारी होता है, कि वह सरकारी बॉण्ड या हुण्डी खरीदें। अभी आवश्यकारी सीमा 23% है। 23% की आवश्यकारी सीमा के अलावा स्वेच्छा से भी बैं० सर० प्रति० में निवेश करते हैं।

स्वैच्छिक नि० / अधिक निवेश depend on Liquidity (नकद अधिशेष)

न० अ० ∝ स्वै० अधि०

जैसे बाजार में ऋण की D ↓ ⇒ नकद अधि० ↑ ⇒ स्वै० निवेश ↑

निवेश की इच्छा कमजोर ⇒ ऋण की माँग ↓

bcoz of

घरेलू / विदेशी / निर्यात ↓ — बिक्री कम ⇒ निवेश की D ↓ ⇒ नक अधि० ↑ ⇒ SLR ↑

बट्टा की दर जितनी अधिक होगी ⇒ सरकार को ज्यादा नुकसान

सरकार चाहेगी कम से कम बट्टा पर बेचें

खरीददार ज्यादा बट्टा चाहता है।

Qus why recently सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश ↑

RBI के कार्यों का विवरण

UPSC Ques

RBI के कार्य

1) केन्द्रीय बैंक के परम्परागत कार्य

2) विकास परक कार्य

जिन कार्यों का संपादन सभी देश के के० बैंक करते हैं, उन्हें के० बैं० के पर० कार्य कहते हैं —

इसमें छः कार्य सम्मिलित हैं —

1) मुद्रा निगमन एवं मुद्रा भण्डार का प्रबंधन

2) सरकारों को (C व राज्य Govt. दोनों) बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति — (बैं० S.)

3) बैंकों तथा अन्य प्रकार की वित्तिय संस्थाओं को बैंकिंग सेवाओं की S. → ∴ RBI को बैंकों का बैंक कहते हैं या Banker of last resort भी कहते हैं। (अंतिम सहारा बैंक)

4) वित्तिय बाजार का विनियमन

5) विदेशी विनि० बाजार का विनियमन

6) मौद्रिक एवं वित्तिय तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण एवं प्रकाशन।

India
भारत का के० बैंक — RBI

बांग्ला० C. B. — बांग्ला बैंक (Bangladesh Bank)

चीन का C. बैंक — People's Bank of China

USA ⇒ फेडरल रिजर्व of USA

State Bank of Pakistan

विकास परक कार्य हैं

↳ वित्तिय संस्थाओं की संरचना का विस्तार, विकेन्द्रीकरण एवं आधु०

↳ वित्तिय नवाचार

↳ देश के पिछड़े अंचलों, उत्पादन के पिछड़े क्षेत्रों एवं समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम या लक्षित कार्य० बनवाना एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

Ques. क्या RBI को नीति०, विकास परक कार्य ... ताकि ... कार्य पर ... ध्यान दे सके।

→ Yes
- already बहुत सारी संस्थाएँ
- Duplication की prob.
- सारे कल्याणकारी कार्य हेतु एक संस्था खोली जा सकती है।

→ NO
- RBI का कार्य का दायरा संकीर्ण
- शंकित

यु राजन — "सेविंग कैपिटलिज्म from कैपिटलिस्ट" (पूँजीवादियों से पूँजीवाद का बचाव)

वि० सं० का विस्तार हो वर्तमान वि० सं० को शाखा विस्तार हेतु प्रोत्साहित करे।

— नये वित्तिय संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करे।

(1) ⇒ दोनों मे FDI की भूमिका →

ARC → (एसेट रिकंस्ट्रक्शन C.) ⇒ ऐसी Co. जो

कर्जों की वसूली का कारोबार करती है।
बकाया कर्ज की वसूली का अधिकार बैंक से खरीद लेती है।
तत्पश्चात वकीलों की मदद से वास्तविक वसूली करती है।
इसमें FDI की सीमा अब 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गयी है

ज्यादा वकील की नियुक्ति → क्षमता ↑
तमाम तरीके से काम

② सरकारी बैंकों का पुनः पूंजीकरण
↳ सरकार द्वारा बैंकों को और पूंजी देने की प्रक्रिया।
12,000 करोड़ की योजना।

(FDI ↑)

नयी शाखा → रोजगार
⇓
वित्तिय समावेशन
पर्वतीय क्षेत्र, ग्रामीण, Urban (preferential order)

वित्तिय सेवा

किसानों की कर्ज हेतु

③ लाइसेंसिंग की प्रक्रिया ⟹ शाखा प्रसार

⟹ संस्थाओं का विविधीकरण :
- NBFC
- बीमा C.
- सहकारी वित्त
- ARC
- RRB

→ सबका विस्तार

⟹ (आधुनिकीकरण) :- अद्यतन कार्यशैली, उपकरण, नीति का प्रस्ताव है।

ICOR
↓

RBI

मुद्रा की साख को Fiduciary value कहते हैं।

(भरोसा मू०)

निष्कर्ष

- मुद्रा स्फीति — प्रत्यक्ष आनुपाती संबंध
- कालाधन
- नकली मुद्रा का प्रसार
- विनिमय दर — रु 1 = $ 1/65

RBI → Inf. control का प्रयास b(o)z (मुद्रा की साख को बचाना)

मुद्रा की साख ↓ क्रयशक्ति ↓ का प्रसार ↑

नकली मुद्रा का प्रसार — मँहगाई ↑ → उत्पाद

(देशी मुद्रा के बदले दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त हो) ↑

औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC)

नकली मुद्रा वाला → औसत बचत प्रवृत्ति ↓

वैश्विक C. → जिस C. की साख पूरे विश्व में

स्थानीय C " " एक देश

मौद्रिक / प्रतिरूप C. →

नैसर्गिक / कृत्रिम

रुपये का विनिमय दर ↓

Inflation

निर्यात ↓ → आयात ↑ → 4) व्यापार घाटा ↑ 5) चालू घाटा ↑

सरकारों के बैंकर के कार्य
- → खाता प्रबंधन
- → ऋण दोहन का प्रबंधन
- → सलाहकारी सेवा

खाते

- घरेलू
  - संवैधानिक
    - संचित निधि (खाता)
    - आकस्मिक
    - लोकलेखा
  - संविधानेतर (विधान सम्मत / Statutory fund)
    - प्रधानमंत्री राहत कोष
    - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष/निधि
- विदेशी

Note – अगर किसी वित्त अंत॰ संस्था का सदस्य Indian Govt. है, तो उसका खाता भी होगा

विदेशी खाते

- IMF में खाता स्थापन by RBI
- विश्व बैंक में खाता
- ADB में A.
- अंत॰ कृषि विकास Fund में A.

ऋण दोहन का प्रबंधन

(मोलभाव आधारित विनिमय) है → (S. प्रतिभूति की पूर्ण no आरक्षित कीमत मोलभाव b/w RBI & क्रेता)

- Govt. S. की निलामी
- रेपो विनिमय
- खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market operation) (सरकारी प्र. की)

सरकारी S. का उत्पादन → F.M.

विक्रय → by RBI

⇓

नीलामी

- बैंकों (58% का) खरीददारी
- other C. → अधिशेष उपलब्ध

विक्रय - क्रेता - विक्रेता के बीच मोलभाव

नीलामी - नाना प्रकार के क्रेता के मोल भाव द्वारा कीमत

→ विक्रेता निर्धारित

द्वारा न्यूनतम कीमत → आरक्षित कीमत

• प्रतिभूति विक्रय से मुद्रा का संकुचन होता है।

⇓

D ↓

⇓

Inf कम होती है, या अधोगामी दबाव बढ़ता है

⇓

मुद्रा की साख ↑

⇓

₹ मजबूत

⇓

आयात लागत ↓ ⇒ लागत जन्य Inf ↓ ⇒ ~~CAD~~ TD को बढ़ते पर अंकुश

→ CAD पर अंकुश ⇒ आरोपीयों का उत्साह ↑ ⇒ निवेश

⇓

ब्याज का Ex rate ↓ ⇒

OMO में RBI बेचती ही नहीं खरीदती भी है ⇒ तीव्र गति से खरीद लेती तो Inf ↓

OMO का प्राथमिक उद्देश्य ↳ कीमत में स्थायित्व लाना

गौण उद्देश्य ↳ Ex. R. में स्थायित्व लाना

- Yield → (प्रतिदान)
- G-Sec – Yield है

₹ = 10,000

CR = 8%

MP = 5 वर्ष

FD : 9.5%↓

: 5.0

5.0

Now Scenario → FDR ↑ ⇒ सरकारी बॉण्ड की D ↓

बॉण्ड का अंकित मूल्य — घोषित ब्याज → वास्तविक ब्याज 750 (Yield) (बॉण्ड बाजार के अंकित मूल्य से आधार होता है)

जैसे बाजार मूल्य of Bond ↑ उसका वास्तविक प्रतिदान दर घटता जाता है।

FD↑ ⇒ M.V. of Bond ↓ ⇒ Yield ↑

B of M.V जैसे-2 गिरेगा Yield बढ़ता जायेगा

S. of Govt B. ↑ ⇒ बाजारमूल्य ↓ ⇒ Yield ↑

लेहमैन-ब्रदर्स (2008-09) → गिरावट

अमेरिकी सरकार S. B. बेची ⇒ पैसा Inst. को दिया (बेल आउट पैकेज) ⇒ कार्यक्रम बेल-आउट

M.P↓ ⇒ Y↑ ⇒ अमेरिकी सरकार पर ब्याज बोझ ↑

कुल खर्च की राशि ↑ ⇒ राजस्व + राजकोषीय घाटा ↑

⇒ कर प्राप्ति ↓

⇒ ग्रीस → कल्याणकारी P. में खर्च ↓ ⇒ असंतोष → सामाजिक विचलन / सरकार के प्रति रोष

व्यापक सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक संकट PIIGS संकट

⇒ यूरो जोन में अब G.R. ↑

bailout कार्यक्रम को वापस लेगे ⇒ Yield ↓ ⇒ अब कम

सरकारी बॉण्ड खरीदेंगे ⇒

USA ⇒ क्वांटिटेटिव ईजिंग ⇒ ऐसा कार्यक्रम जिससे देश में मुद्रा की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ाया जाये।

टेपरिंग → मुद्रा प्रसार की दर को कम करने की प्रक्रिया

प्रभाव दाम ↓

अनुमान → आने वाले दिनों में Yield बढ़ेगा

∴ USA के निवेशक वापस जा रहे हैं।

USA — India

बॉण्ड की खरीद-बिक्री का relation

$

=> Fed Reserve => पेपरिंग की घोषणा। => अनिवासशील (USA)

⇓

विनिमय दर स्थापित

Q. विश्व अर्थव्यवस्था के वर्तमान संकट का संबंध PIIGS से ना होकर अमेरिका के नीतिगत समायोजन का आधिक प्रभाव

1994 में कार्यक्रम शुरू किया गया by RBI

LAF
(Liquidity Adjustment facility) → वाघुल समिति

2011 – Margin Standing facility

ऐसी अतिरिक्त सुविधा, जो RBI बैंकों को हमेशा देता है।

stand by
⇓
सहयोग देने के लिए तत्पर

RBI ——→ SBI
<- - - - - -

सरकारी s RBI को cash surplus जमा है
⇓
थोड़े समय हेतु नकद राशि

→ Cash surplus

RBI ने SBI को रेपो लोन दिया।

रु० प्रतिदान

BB

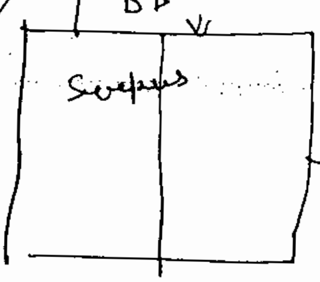

Reverse Repo

Direct SBI को दे

कॉल मनी

रेपो विनिमय।

- सरकारी S. उ धरोहर के आधार पर RBI द्वारा बैंकों को इस शर्त पर दिया गया ऋण, कि कुछ दिनों (0 से 12 दिन) के अंदर ऋण राशि वापस लेने का अधिकार RBI सुरक्षित रखेगा। रेपो ऋण कहलाता है।

- जब भी RBI बोल तो ऋणी को पैसा लौटाना होगा

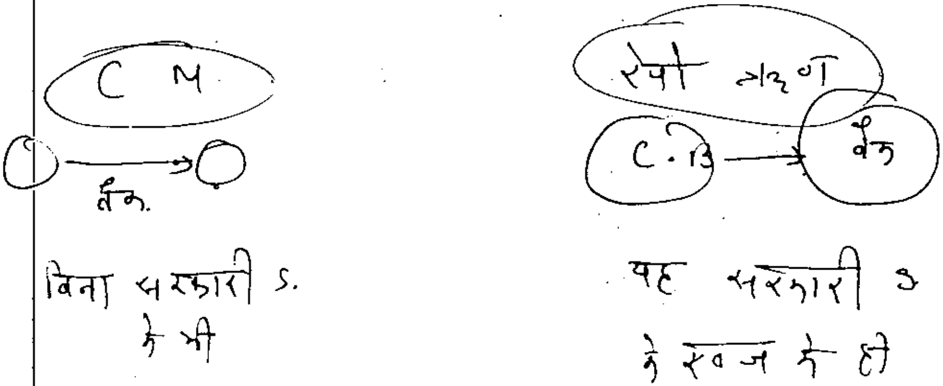

7.25

कितनी प्रतिभूति बेची जायेगी decided by parliament

- Gsec - S. के आधार पर RBI द्वारा बैंकों से इस शर्त पर स्वीकार किया गया ऋण, कि निर्धारित दिनों के अंदर ऋण राशि को लौटाने का अधिकार RBI के पास सुरक्षित रहेगा रि. रेपो ऋण कहलाता है।

(+) → RBI

6.25

1% का फासला ⇓ ज्यादा लागत की उगाही हेतु

लाभ :- (1) +ve नेटवर्थ ↑ of B
(2) तरलता समायोजन सुविधा

G-Sec में खरीददारी 1994 रेपो ऋण सुविधा के चलते सरकारी S. की उपयोगिता बढ़ गयी है, इससे बैंकों के समुदाय में इन S. की स्वैच्छिक माँग बढ़ती जा रही है,

- सरकार बाजार से ऋण उगाही की क्षमता ↑ व सरकारी ऋण का औसत ब्याज कम होता जा रहा है।

(RBI का annual report)

- कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करने की स० क्षमता ↑
- RBI अपने S. नीलामी के कार्य को अधिक कुशलपूर्वक कर पाती है।
- SLR मानक में गिरावट
  (कॉर्पोरेट निवेश ↑ → SLR ↓) → इससे अर्थ० में सरकारी हस्तक्षेप की मात्रा कम होती गयी अर्थात् वित्तीय उदारीकरण को बल मिला।

Que रेपो दर कम करने के प्रभाव :—

→ Demand ↑
→ ऋण अनुमोदन को बल
→ ऋण की Supply ↑
→ I. R. ↓ संभावना → व्यापार निवेश
→ Liquidity ↑ —
→ ऋण खपत ↑
→ वस्तुओं की खपत ↑ ⇒ निवेश ↑
→ उच्च स्तरीय संतुलन
→ Inf R. ↑

Que पिछले दो वर्षों से रेपो rate को कम करने का उपरोक्त उद्देश्य कारण ही है

Que :— क्या आप मानते हैं कि रेपो रेट को कम करना चाहिए ?

Ans :— अगर G. R. बढ़ेगी, तो विदेशी नि० आकर्षित होंगे & को उपलब्धता ↑ — ₹ मजबूत होगा।

रिवर्स रेपो R = ↑

↳ बाजार में मुद्रा आपूर्ति ↑

रेपो R + रिवर्स रेपो से ↑ ⇒ ताकि महंगाई ↓

" + " ↓ ⇒ Growth ↑

(I) कृषि

अल्पकाल में S - D में संतुलन

- फसल संरचना
- कृषि राज सहायता — प्रत्यक्ष — परोक्ष
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल खरीद, भण्डारण एवं बाजार में विक्रय (विपणन प्रणाली में सुधार)
  - जन-वितरण प्रणाली
- खाद्य - प्रसंस्करण उद्योग } कृषि एवं उद्योग के
- पशुपालन का अर्थशास्त्र } अंतः संबंध की उन्नति
- संस्थागत सुधार ← भू-सुधार, सिंचाई प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग

II) बुनियादी ढाँचा है।

III) निवेश ढाँचा / है / मॉडल

कृषि कीमत नीति का अर्थ एवं इसके प्रमुख उद्देश्य

(i) कृषि क्षेत्र में उत्पादित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बाजार के विकास हेतु सरकार द्वारा नियत कीमत को सामान्यतः कृषि कीमत कहते हैं।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा कीमतों की घोषणाएँ की जाती हैं। आयोग किसानों की लागत एवं बाजार में प्रचलित कीमत के बीच तालमेल रखने के उद्देश्य से कीमतों की सिफारिश करता है। इन कीमतों के निर्धारण की उपरान्त समग्र व्यवस्था

को कृ॰ की॰ नीति कहते हैं / कृषि क्षेत्र की खामियाँ

कृ॰ की॰ नी॰ के उद्देश्य

(कीमत नीति व्यापक नीतिगत व्यवस्था)

1) परिवर्तनशील लागतों के संदर्भ में किसानों को उनके कार्य को उत्साहवर्द्धक मुआवजा सुनिश्चित कराना।

(2) फसल की आंचलिक संरचना एवं मौसमी संरचना में सुधार हेतु कृषकों को प्रेरित करना। (वांछित फसल संरचना)

(3) कृषि क्षेत्र हेतु विकसित होती जा रही नव्य उत्पादन तकनीकों को अपनाने हेतु कृषकों को समर्थ बनाना एवं उत्साहित करना।

(4) देश के सभी उपभोक्ताओं के लिए समुचित मात्रा में अन्न एवं अन्य फसलों (गैर-अन्न) का भण्डार विकसित करना एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

5) कृषि आधारित उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने की मनसा से प्रतियोगी कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कृषि वस्तुओं का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करना।

(6) देश के आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय कारणों से कृषि वस्तुओं की कीमत में होने वाले उच्चावच पर अंकुश लगाना।

(7) इन नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जरूरतमंद देशों के लिए निर्यात योग्य कृषि अधिशेष विकसित करना।

Ques कृषि की॰ नी॰ को अपनाने की जरूरत क्यों थी?

Ques why पूर्णतः बाजार पर नहीं

CACP
↳ का पुराना रूप → APC → 1965
(Agri pricing Comission)
⇓
new

(CACP → 1987)
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
→ लागत की जानकारी लेते है,
(सर्वेक्षण)

अन्य फसलों के मुनाफे का औसत को ध्यान में रखा जाता है।

कृषि संगणना (2010 – 11)
↳ आकड़े की रखा
• भूजोतकों की संख्या ⇒ लगभग 14 करोड़

(खेतों के भाग पर जमीन फैला हुआ)

• कृषकों की संख्या ⇒ लगभग 24 करोड़

लोकसभा → 85% भूजोत ऐसे हैं, जिनका भूजोत के पास 16 करोड़ हेक्टेयर
↳ जमीन का 1/2 करोड़ करोड़ पास
दो हेक्टेयर से कम है
⇓
लघु व सीमांत किसान

14 1/2 भूजोत → 2 – 10 hect. (लघु एवं लघु मध्यम किसान)
शेष भूजोत → 10 hects +

CACP – यहाँ भी देखता है कि उपरोक्त क्या रहती है → बाजार कीमत /

जिस मूल्य पर सरकार खरीदवाती है

- MSP
- Procurement Price (खरीद मूल्य)
- निर्गत मूल्य I.P.

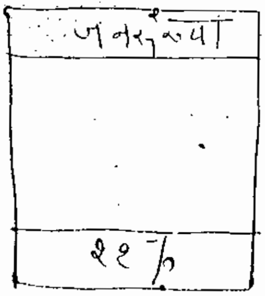

गरीबी रेखा

खरीदने पर → MSP

गरीब उपभोक्ता हेतु

मूल्य ⇒ I.P

खरीद (MSP) जिस मूल्य पर केन्द्र सरकार अनाज देती है, I.P कहते हैं
↓
बेचा (I.P)

MSP → केन्द्र → निर्गत

केन्द्र सरकार कम दाम पर राज्य सरकार को
→ राज्य सरकार को अनुमति इससे कम पर उपलब्ध कराये, but इससे ज्यादा नहीं

I.P. का aim → ज्यादातर गरीब उपभोक्ताओं को इससे ज्यादा नहीं देना

⇒ कृषि राज सहायता को सामान्यतः दो वर्गों में बांटते

- उत्पादक राज सहायता
- उपभोक्ता " "

(राज सहायता सारे किसान को नहीं but लाभ किसान को होते)

उर्वरक कारखाना → लागत 600 बोरा
⇓
मूल्य - 250 बोरा ⇒ for marginal class

घटाई by सरकार

(उत्पादक राज सहायता)

⇒ उत्पादक राजसहायता → परोक्ष (उर्वरक सब्सिडी) (मध्यस्थ की आवश्यकता)

Direct Subsidy :-

मुफ्त सिंचाई

// जो धन सहायता का लाभ directly हस्तांतरित करे

(महत्वपूर्ण) → Direct Cash ⇒ is a Direct Subsidy

Ex :- बीज मूल्य ⇒ 800/-

कृषक ⇒ 200 + बैंक में 600 ⇒ 800

(−) (+)
disuse · महत्वपूर्ण
संभव

Qus D & Id में कौनसा बेहतर है ?

परीक्षा

(−) (+)

- महत्वपूर्ण को काफी समस्या।
- बड़े किसान ही ज्यादा लाभ

// FM → कुछ सब्सिडी में Direct Cash transfer नहीं

// Qus I / D. Subsidy का कृषि पर क्या प्रभाव

↳ वितरण में कुशलता ↑
उत्पादकता ↑

राजसहायता

↓ प्रकट (Explicit) → Direct सब्सिडी

↓ अप्रकट (Implicit) → Generally Indirect सब्सिडी अप्रकट

Input सीमेंट
खदान ⇐ चूना, पत्थर
⇓
by Co
प्रोसेस द्वारा
खनन का
अधिकार

पैसा — no पैसा
↳ सीमेंट उत्पादन ⇒ पुल बनाने ⇒ कृषक
लागत ↓ की लागत ↓

जिन संसाधनों का लाभ अंततः कृषकों को मिले, लेकिन उसके उत्पादन की बुनियादी लागत को राजसहायता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से कम रखा जाये, तो उसमें व्यय होने वाली राजसहायता को कृषि क्षेत्र हेतु अप्रकट राजसहायता कहते हैं।

उदा० –
– अप्रकट ⇒ आपातकाल रूप में

Govt ⇒ अप्रकट राज सहायता को प्रकट बनाया जाये ⇒
सरकार का aim
aim ⇒ जागरूकता बढ़े
⇓
बहस की सही दिशा, मा-नी

अप्रकट का कमाल
समाज में दुरुपयोग ↑

⇒ राज सहायता की गुणवत्ता में सुधार हेतु अप्रकट को प्रकट S. में रूपांतरित किया जाये। इससे समाज में संचालित उपयोग

⇒ उत्पादन में कमी होगी

- 2nd G.R. की बुनियादी रणनीति में राज सहायता का स्वस्थ उपयोग करना imp. आयाम है।

S. का विकेन्द्रीकरण by सरकार
(राजसहायता संरचना का विकेन्द्रीकरण) है —

ACP संरचना कभी → यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं

राज का विकेन्द्रीकरण जरूरी → तात्कालिक उत्पादन
→ S - E हित

↓

but किसानों गरीबों पर दबाव नहीं है IP↓ -

राजसहायता के विकेन्द्रीकरण की संरचना ऐसी हो कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हित के तनाव का निवारित हो अर्थात् MSP को बढ़ाये but IP नहीं बढ़ाएं।

(राज सहायता) → राज्य द्वारा दी गयी सहायता

Que वर्तमान राजसहायता में त्रुटियों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए

MSP

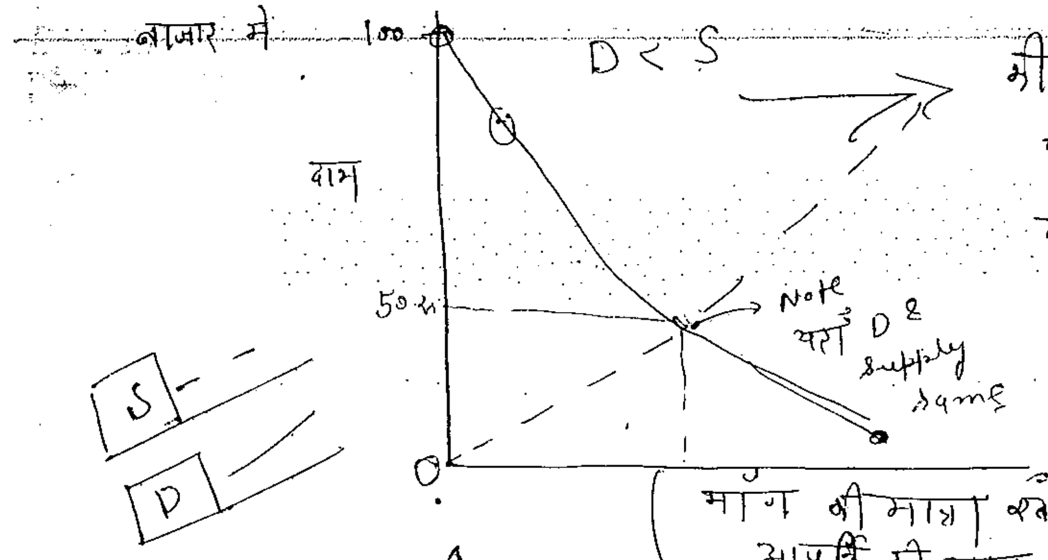

→ कीमत में गिरावट के कारण माँग की मात्रा मे वृद्धि ~~होगी~~ को दर्शाने वाली रेखा।

↓

माँग रेखा।

कीमत ↑ माँग की मात्रा ↓

shown by रेखा

⇒ माँग रेखा।

⇒ कीमत मे उच्चावच (base) के कारण माँग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने वाली रेखा ⇒ माँग रेखा

S बाजार विक्रेता कहते हैं।

⇒ जैसे-2 कीमत ↑ S की मात्रा ↑

⇒ आपूर्ति आधिक्य ⇒ D < S

↳ माँग की ~~आपूर्ति~~ की तुलना में आपूर्ति अधिक

⇓

विक्रेता पर दबाव ⇒ कम कीमत पर बेचेगा ⇒ प्रतिस्पर्धी बोली ⇒ कीमत की अधोगामी प्रवृत्ति ⇒ माँग ↑

↳ इस कुछ विक्रेता नहीं बेचेंगे

⇒

⇒ माँग आधिक्य ⇒ D > S ⇒ माल में कालाबाज़ारी →

तब तक कालाबाज़ारी जब तक D = S ना हो जाये।

किसान — व्यापारी

14 करोड़ — 11 करोड़

किसानों को व्यापारियों से बचाने हेतु

↳ सरकार स्वयं entry → FCI → खरीद का MSP

↳ जितना बेच सकते हैं, उतनी खरीद

D↑ ⇒ दाम ↑

→ MSP :- वह खरीद पर सरकार FCI के माध्यम से कृषकों से इतनी मात्रा में फसल खरीदने को राजी हो, जितनी मात्रा कृषक बेचना चाहे उसे MSP कहते हैं।

⇒ खरीद मूल्य :- जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब उपभोक्ता हेतु जिस कीमत पर निर्धारित मात्रा में अनाज खरीदने हेतु सरकार प्रतिबद्ध हो उसे खरीद मूल्य कहते हैं।

जमाखोरी एवं कालाबाज़ारी → D ↑ जब market में आये

⇒ व्यापारी रोक रखे हों, तो FCI बेचना शुरू कर दे (उपभोक्ताओं को राहत)

⇒ बाज़ार में कीमत स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम अनाज का जितना भण्डार बनाये रखता है → उसे बफर स्टॉक कहते हैं।

⇒ बफर स्टॉक हेतु खरीद भी PP के आधार

बफर भण्डार मे अनाज कोन्सर्स हेतु की खरीद मूल्य का उपयोग करता है।

जरूरी मात्रा => अतिरिक्त मात्रा

PP MSP

=> PP, MSP की तुलना मे थोड़ा ऊँचा होता है।

=> MSP + बोनस => PP

FCI ग्रेडिंग
- सामान्य
- fine => (Generally बोनस कीमत इसी के लिए)
- Super fine

(हाशिये पर: इन्ही को प्राप्त जो पहले बेचते है)

=> उत्पादन ज्यादा बढ़ने पर => FCI पर दबाव =>

बफर स्टॉक के अनाज की मात्रा ↑ (पिछले 3-4 साल का Scenario)

कृषि कीमत नीति ↑ MSP — अप्रत्याशित आपूर्ति ↓

मानक — अनाज — उच्च — इसके मनोवेग — जड़ना

=> free release जैसे आपदा राहत कोष => राजकोषीय सहायता ↑

कृषि कीमत नीति → (+) — उपज ↑

Que ⇒ हाल मे कृषि उत्पादन मे वृद्धि हेतु कौन-2 से प्रमुख कारक जवाबदेह है।

- कृषि कीमत P_0 मे कृषकों का मनोबल तेजी से बढ़ाया है।
- FCI के खरीद कार्यक्रम का भौगोलिक प्रसार
- कृषि सम्बन्धी बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु भारत निर्माण परियोजना सहयोगी रही है। (इस से सड़क की → सिंचाई ...

- आगतों का निवेश ↑ (बीज, उर्वरक, उपस्कर)
- पिछले कुछ वर्षों में ऋण उपलब्धता में भारी वृद्धि हुई है। ⟹ Input Investment ↑
- पिछले कुछ वर्षों में कुछ इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या तेजी से बढ़ी रही → नए खरीददार ⟹ उपज का विपणन सरल होता जा रहा है।
- कुछ वर्षों से कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि ⟹ इससे कृषकों की लाभदायकता बढ़ी है। (फल - सब्जी) (भारत - फूल निर्यात)
- देश के सभी ग्रामीण जिलों (चम्बल - नाशपति से फूल निर्यात) में आधुनिक बीज बैंक स्थापित हो चुके हैं ⟹ उन्नत प्रकार के बीज की आपूर्ति ↑ ⟹ विशेष रूप से पिछड़े इलाको में बढ़ी है।
- मानसून की प्रकृति व (आधुनिक) सम्बन्धता
- कृषकों में जागरूकता का स्तर ↑

भारत ⟹ 5½ लाख करोड़ (वार्षिक) ⟹ (production) → लगातार ज्यादा

Priority sector

भू-सुधार

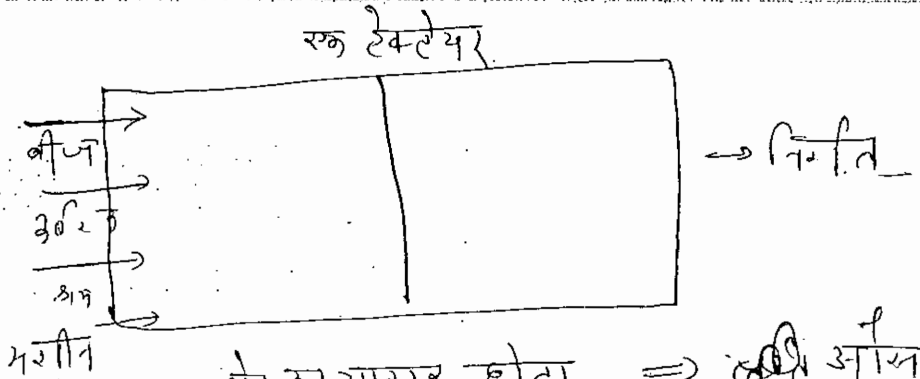

खेत का आकार छोटा ⇒ औसत लागत ↑

पर्यवेक्षण 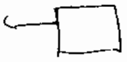
गुणवत्ता ↓
श्रमिक ↑

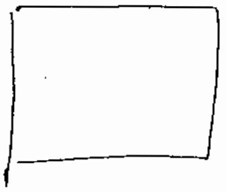

⇒ खेत का आकार एक अनुपात से कम लागत ↑
" " " ज्यादा पर्यवेक्षण लागत ↓

अनुकूल दशा ⇒ उत्पादन इकाई का इष्टतम आकार
ताकि पैसा लाभकारी

⇒ भूमि सुधार करने के कृषि की दीर्घकालिक औसत लागत ↓ ⇒ दीर्घकालिक लाभदायकता ↑

⇒ कृषि समुदाय के जीवन की गुणवत्ता ↑ (गरीबी ↓ प्रच्छन्न बेरोजगारी ↓) ⇒ कृषि आधारित उद्योग ↑

किसान
- भूमि
- भूमिहीन

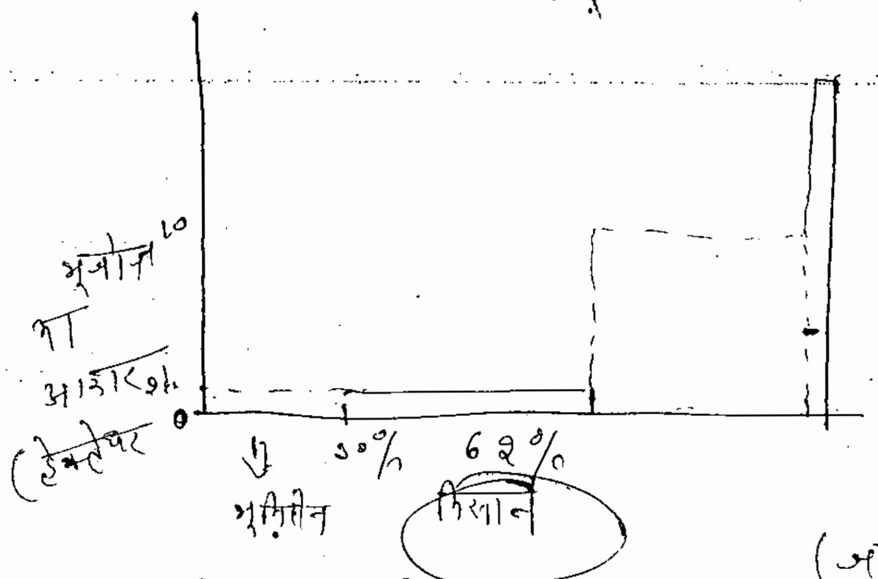

⇒ अतिरिक्त भूमि की पहचान → अधिग्रहण (जबरन) → भूमि वितरण। 70 भूमिहीन ⇒ हिंसक तरीका

(25 April 2013) राष्ट्रीय भू सुधार नीति है
- (पूँजीवादी तरीके से भूसुधार का कारण)
- भूमाफिया का खात्मा

Ques भू सुधार का पुराना व न्यूनतम मार्क्सवादी मॉडल में अंतर स्पष्ट करें कि क्या टिप्पणी करें असफल रह जायेगा।

भू सुधार → मार्क्सवादी मॉडल / पूँजीवादी मॉडल

(MSP के नकारात्मक प्रभाव) → 1) वृद्धि के बजाय Feeding ↑

2) लगातार MSP बढ़ाने से व्यापारियों में जमाखोरी — कालाबाजारी ↑

3) मुख्य लाभ भूस्वामी वर्ग को ना कि भूमिहीन वर्ग को। ग्रामीण समाज में विषमता ↑

केन्द्र द्वारा C — राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण अभियान

आयोजित अभियान — रा॰ खा॰ प्रसं॰ उद्योग को बढ़ावा देने हेतु चलाये जाने वाले सभी कार्यक्रमों को एकीकृत कर 1 अप्रैल, 2012 को यह अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में निम्न॰ कार्यक्रम शामिल हैं :→

खर्चे का बंटवारा C : S

(1) खा॰ प्रसं॰ उद्योग क्षेत्र हेतु प्रौद्यो॰ उन्नयन / स्थापना / आधुनिकीकरण कार्यक्रम

↓ 75 : 25 ↓

but विशेष दर्जा C : S 90 : 10

(2) कोल्ड् चेन (शीतलक संजाल), मूल्य वर्द्धन एवं संरक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास कार्यक्रम

(3) पशुवध शाला (Abattoir) स्थापना / आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम | → [illegible] → तो बिमार]↓

UT (केंद्रशासित) 100% by C

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु HD (मानव) विकास कार्यक्रम

(5) उत्साहवर्धन क्रियाकलाप कार्यक्रम

(6) ग्रामीण अंचल में प्राथमिक प्रसंस्करण एवं संग्रहण केन्द्र कार्यक्रम — Pasteurization

(7) मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

(8) शीतलक वाहन कार्यक्रम

(9) पुराना खाद्यान्न - उद्यान कार्यक्रम

उपयोगिता वृद्धि ⇒ मूल्य वृद्धि (value addition)

खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम :— ऐसा Recog. जिससे कृषि उत्पाद की मूल्य वृद्धि हो।

हम :→

खाद्य प्रसंस्करण

फायदे — उन्नत तकनीकी — वस्तु एवं रूपांतरण

(+)
- wastage ↓
- उत्पादकता ↑

सुझाव
- तकनीकी ↑
- use हेतु सब्सिडी

Central Processing Unit
(केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई)

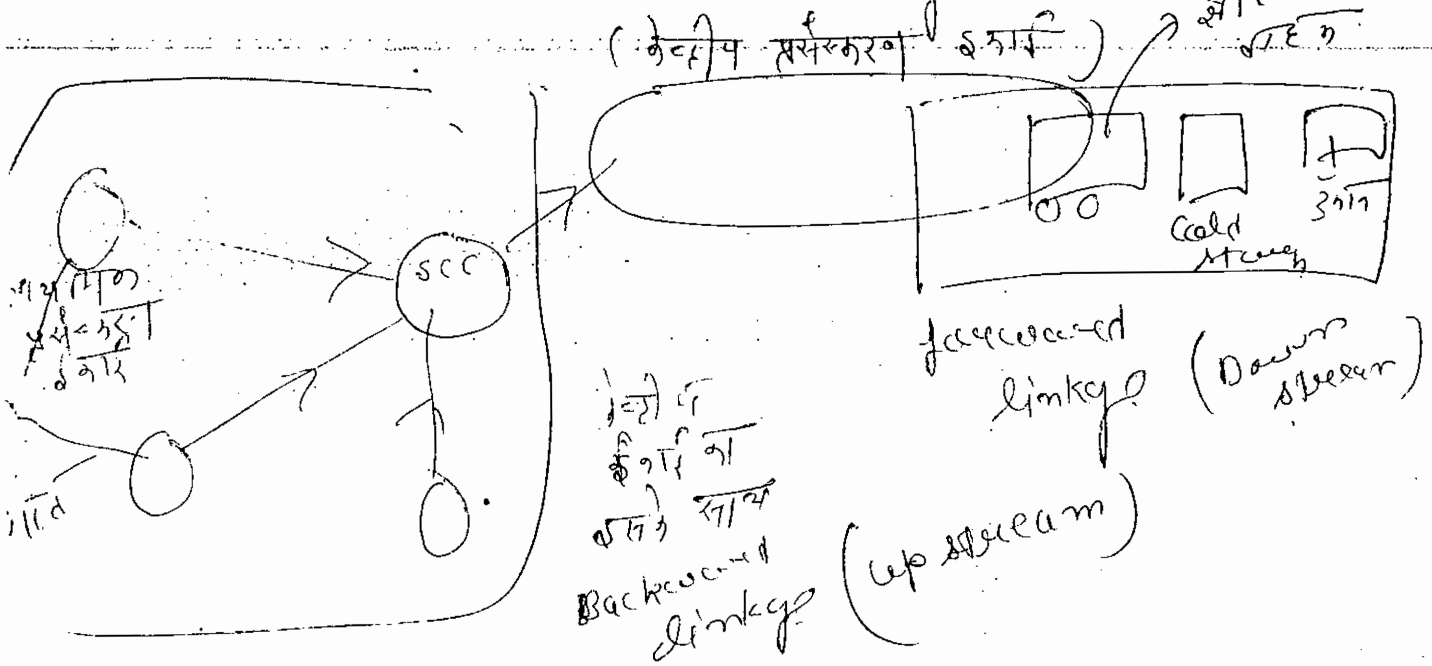

=) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

खाद्य प्रसंस्करण के लिए forward linkage व (अग्रगामी संबंध) पश्चगामी संबंध

नया स्तर 2007 — Mega food park

1956 — छोटा आकार, नये ... नहीं

- उद्योग को बढ़ावा देने के कार्य-2 के उद्देश्य हैं — आदि / जरूरत
- F.P. इकाइयों की स्थापना सहित फसल उतार के उपरांत होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय पारि. के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलापों को समायोजित करने के उद्देश्य से क्रियान्वयन की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करना।
- पूंजी आपूर्ति प्रौद्योगिकीय अंतरण कौशल विकास एवं रख रखाव में सहयोग द्वारा F.P. क्षेत्र की क्षमता में लगातार सुनिश्चित करना।

- जो स्वयं सहायता समूह (SHG's) में सक्रिय हैं, उन्हें लघु एवं मध्यम उद्यम का कानूनी दर्जा प्राप्त करने में सहयोग देना।
- संस्थागत प्रशिक्षण व्यवस्था द्वारा भारतीय रोजगार के अवसर विकसित करना तथा खाद्य P. उद्योग में प्रशिक्षित कामगारों की माँग एवं आपूर्ति के अंतराल को कम करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में सुरक्षा एवं स्वच्छता के गुण विकसित करना
- F. P. इकाईयों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करना।
- खेत से प्लेट तक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को सुचारु एवं त्वरित करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा, आपूर्ति जाल, लॉजिस्टिक, भण्डारण एवं प्रसंस्करण क्षमता विकसित करना (आपूर्ति जाल के प्रत्येक बिंदु के आपसी तालमेल को ...)

(Supply Constraint (आपूर्ति अवरोध))

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संगठित उत्पादन ईकाईयों को विशेष प्रोत्साहन देना।

मनरेगा को ... 6 — ग्रामीण बाजार के प्रसंस्कृत उद्योग

(गरीब लोग, अमीर लोग, Reduce, MSP)

यूरिया सब्सिडी

(1) यूरिया सब्सिडी कम करने से यूरिया की कीमत ... इससे किसानों पर न सहने योग्य बोझ बढ़ रहा है। चूँकि उन्हीं की उत्पादकता ज्यादा है, उनपर बोझ बढ़ने से सम्पूर्ण देश की 80% औसत उत्पादकता ... कर ली है

(2) राजकोषीय घाटा है इसको खाद्य राज्य ...

खाद्य में भी उर्वरक राज सहायता का हिस्सा सबसे बड़ा है। खाद्य सुरक्षा अधि० पारित होने के कारण उपभोक्ता को मिलने वाली राज सहायता में वृद्धि की आवश्यकता है।

- यदि उर्वरक राज सहायता कम की भी गई, तो सकल खाद्य राज सहायता व्यय और बढ़ जायेगा।

- उपाय

- यूरिया राज सहायता को पिछले 3-4 वर्षों में निरंतर कम किया गया है। लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभाव से लघु एवं लघु मध्यम किसानों के बचाव हेतु पहले से भी सस्ता [illegible] उपलब्ध कराया जा रहा है।

- उर्वरक को पिछले वर्ष बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिया गया (2011) जिससे उर्वरक बनाने वाली Co को कई फायदे होते हैं। ब्याज की दरों पर कम हो जाती है। बाजार में बांड्स बेचने पर कर रियायत। आयात की गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क ↓ ~~उनके~~ उनकी परियोजनाओं का सरकार द्वारा तीव्र गति से अनुमोदन → औसत लागत कम → जिससे सब्सिडी की आवश्यकता कम हो जाती है → यूरिया के दाम बढ़ाने का दबाव कम हो जाता है।

Influence

- उर्वरक बनाने वाली Co को गैस कम दाम पर दे

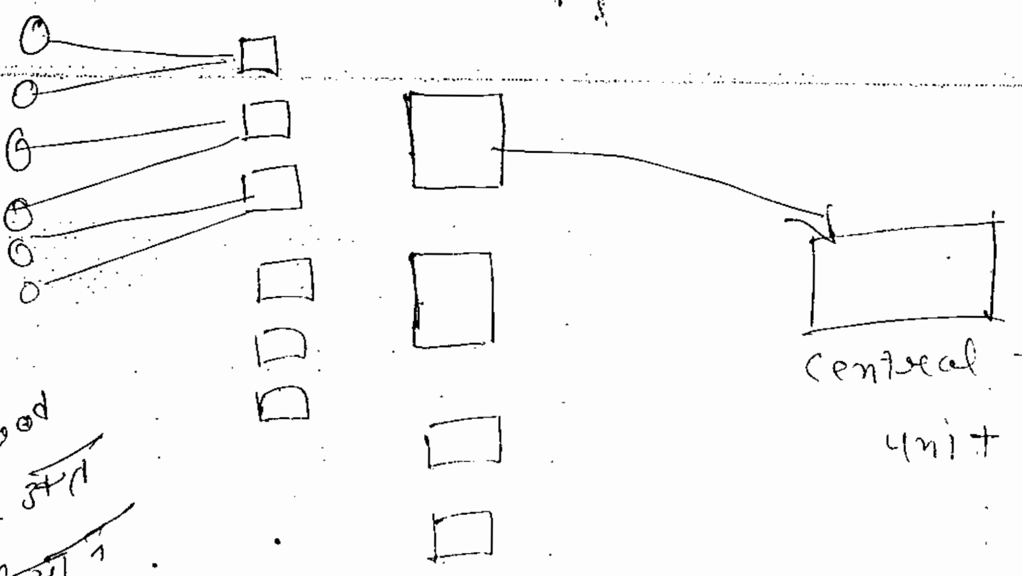

central प्रोसेसिंग यूनिट

mega food park क्षेत्र अभियान के स्वतंत्र है

रघुराम राजन समिति ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता हेतु नया फॉर्मूला सुझाया ⇒ officially माना नहीं है

PM निर्देश → सभी मंत्रालय बारीकी से अध्ययन + अपनी राय दें।

राज्यों का तीन वर्गों में विभाजन — पिछड़ा, कम विकसित, विकसित

पोषण युक्त राज सहायता हेतु विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर दी जाने वाली S. को ऐसी संस्थाओं को उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रेरित कर फसलों के पोषक तत्वों का संरक्षण सुनिश्चित करे।

⇓

यूरिया के बढ़ोतरी 80% उपयोग use

but फॉस्फेट, पोटाश के मूल्य ↓ ⇒ use ↑

Economics of Animal Keeping

- देश की Economy / GDP पर प्रभाव
- रोजगार पर प्रभाव
- गरीबी निवारण पर प्रभाव
- पशुपालन एवं सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव
- पशु० & निर्यात संवर्धन पर प्रभाव
- पशु & बजट पर प्रभाव ↑

पशुपालन ↑
- कुल उत्पादन ↑
- उत्पादन ढांचा विविधीकृत

पशुपालन
(पशुधन में विस्तार / संख्या ↑)

(स्वास्थ्य)
मांसपेशी रोग प्रतिरोधक क्षमता ↓
प्रोटीन ↓ ⟹ पशुपालन ↑ ⟹ प्रोटीन उत्पादन
भोजन की S ↑
महंगाई दर ↓
उपलब्धता पर उपभोक्ता ↑

(निर्यात) —— औद्योगिक मांग ↑ (यूरोप)
निर्यात of अण्डा, मछली
२ ↑

नारी
सबल
योग
⇓
सशक्तीकरण

पशुपालन & F.P. Industry

पशुपालन

F.P.
- F.P. का growth
- हैवल

पशुपालन से ग्रामीण विषमता कम होगी।

बढ़ाने हेतु उपाय/सुझाव है –

1) नस्ल सुधार
- नस्लों में सुधार हेतु संस्थागत प्रयास
- उन्नत नस्ल के पशुओं को आयात कर (जर्सी – स्वाइस) (आस्ट्रेलिया – फ्रिजियन)
- 1986 में उन्नत नस्ल के खरगोश का आयात
- USA की सफेद + गुलाबी सुअर का आयात

(2) पशुचारा क्षेत्र में निरंतर संकुचन

समाधान – रासायनिक चारा का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाई को बढ़ावा देना होगा।
- चारा फसलों को तरजीह देनी होगी
- वर्तमान क्षेत्र का संरक्षण

(3) F.P. संबंधित होना

(4) बाजार स्थल की उपलब्धता ↑

(5) शहरों में फार्म हाउस कम दाम पर उपलब्ध कराये जायें।

(6) फार्म हाउस दबेल्ली आधिपत्यता ↓

(7) पशु स्वास्थ्य / चिकित्सा

निवेश मॉडल

→ निवेश की एक सुनियोजित संरचना, जिसके स्पष्ट सुनिश्चित उद्देश्य हों।

⇒ निवेश का पोर्टफोलियो (विविधीकृत संरचना)

1) sectoral model

(जैसे कृषि, उद्योग, सेवा)

2) आंचलिक संरचना है

निवेश

- ग्रामीण
- शहरी
- अर्द्धशहरी

3) निवेश हेतु संसाधन

- घरेलू संसाधन (बंद निवेश मॉडल) ⇓ Closed
- विदेशी संसा० + घरेलू (खुले साँचे वाला मा०) ⇓ Open

4) वस्तु संबंधी वरीयता क्रम है

प्राथमिकता क्रम

- पूँजीगत वस्तु का उत्पादन ((Capital Intensive)
- उपभोग वस्तु का उत्पादन ((Consumer intensive)

5) विचारधारा के आधार

- मार्क्स आधारित
- गांधीवादी
- नेहरू

6) क्रियान्वयन की शैली

- by नेता / प्रशासक ⇒ प्रशासनिक I.M.
- by बाजार के कारक / निजी उद्यमी ⇒ बाजारोन्मुखी I.M.
- प्रशासक + निजी ⇒ P-P-P मॉडल

- हैरड-डोमर I.M. ⇒ पूँजी गहन निवेश मॉडल
  - ↳ युद्ध विशेषज्ञ says → Ist 5yp इसी से प्रेरित

No → bcoz पूँजी गहन नहीं
- कृषि पर
- ↳ तकनीकी सीमित
- ↳ सामुदायिक भागीदारी की सक्रियता (1952 में [illegible] शुरू)

- महालनोबिस मॉडल
  - ↳ (56 - 91)

- कुल लागत में इस मॉडल की उल्लेखनीय भूमिका

बुनियादी ढांचा

भौतिक (6) / आर्थिक ऊपरी पूंजी (Economic Overhead Capital)

- सिंचाई एवं जल निकासी संजाल
- परिवहन संजाल — भूतल (स्थल — रेल, सड़क; जल), वायु
- विद्युत आपूर्ति संजाल
- संचार सेवा आपूर्ति संजाल
- वित्तीय सेवा सं० "
- व्यवसायिक महत्व वाले भवनों का संजाल

जल — तटीय, आंतरिक जल; घरेलू, अंतरराष्ट्रीय

सामाजिक (5) / Social Overhead Capital

- निवास भवन संजाल
- स्वास्थ्य सं० "
- शिक्षण-प्रशिक्षण "
- नागरिक सुविधा "

Ex — बुनियादी ढांचा — रखरखाव हेतु क्या तैयारी — विकास

— बुनियादी ढांचे हेतु which J.M. is good

— बुनियादी ढांचा विकास हेतु

र, लोहा, तेल, बिजली, गैस, ऊर्जा — परिशोधन औद्योगिक क्षेत्र

8 उद्योग (Infra. Industry)

Infrastructure Industry — ईंधन, कोयला

— लोग

— सस्ता नहीं

① रु/के विनिमय दर में विचलन के ताजा कारण
(चीनी) येन/युआन/रुपया/रिंगित

(कारण) 2008 में → USA + यूरोप
$ यूरो S ↑

इससे SGR < यूरो/$ को S ↑
⇓
ये मुद्राएँ मजबूत होती गयी.

18 मई 2013 बर्नांके ने घोषणा की, कि उपरोक्त नीति को रोकेंगे

↳ $ भविष्य में मजबूत होगा ⇒ ∴ Ding (o
से $ खरीदने हेतु निवेश निकाला → " ,
से $ का पलायन ⇒ $ मजबूत ⇒ bull
अन्य मुद्राएँ कमजोर हो गयी।

अगस्त, 2013 ⟹ नहीं रोकेंगे
(विदेशी का आगमन ⟶ रु मजबूत)

निवेश मॉडल

व्यय, जिससे उत्पादन बढ़े

निवेश का एक आदर्श ढाँचा, जो नि० के विभिन्न aim की प्राप्ति में संसाधनों का इष्टतम दोहन सुनिश्चित करे।

निवेश

(1) संरचना
- क्षेत्रवार
  - प्राथमिक I — कृषि
  - II — उद्योग
  - III — सेवा
- उपभोक्ता वस्तु, उत्पादक वस्तु — based on वस्तु का वर्गीकरण
- पूँजीगत वस्तु
- श्रम वस्तु (जिन वस्तुओं पर श्रमिक वर्ग की आय का बड़ा हिस्सा व्यय) — श्रम वस्तु पूर्णकालिक निवेश

वकील — मजदूरी वस्तु संरचना मॉडल

(2) सिफारिश किसके द्वारा
- गांधीवादी मॉडल
- महालनोबिस (आपूर्ति पक्षीय)
- वकील ब्रह्मानंद मॉडल
- सेन मॉडल
- जगदीश भगवती

1991

(1) ECB ↑ → विदेशी कर्ज ↑

(2) FDI ↑ in उत्पादन

उपभोक्ता वस्तु में विदेशी तत्व ↑ ⇒ देशी उत्पाद ↓

Ex: कार → mostly विदेशी कार

(3) देश के जनजीवन में विज्ञापन का use ↑
- विदेशी C के पक्ष में + देशी उपभोक्ता के पक्ष में
- देशी C के पक्ष में

(4) C के मुनाफे को देश ↓

Ans FDI आधारित निवेश मॉडल भारतीय समाज हेतु अच्छा है/नहीं

(+)

० व्यापक जनहित

भगवती मॉडल है -
↳ जीडीपी पर ध्यान
↳ विशुद्ध रूप से प्रकृतिपरक
Growth centric
J. M.

सेन मॉडल
↳ उत्पादन क्यों बनाना है
↳ सिर्फ उत्पादन नहीं
. उसके साथ वितरण पर भी ध्यान

"वितरणकारी न्याय युक्त समृद्धिकारी J. M."
⇓
समृद्धि के साथ वितरणकारी न्याय भी हो
→ (+) Growth ↑
MOJ ↑

(4) होता है, और जिसके उपयोग से हम
करने की क्षमता + संवर्धन होता हो। (विभिन्न...)
कसरी सेवाएं भी शामिल है।
पूंजीगत वस्तु का उत्पादन नहीं

~~...~~ प्रधान वस्तु मॉडल → S - E विधान

(a) पूंजीगत वस्तु, तो E ↑ but S ↓.

निष्कर्ष पहले पूंजीगत बनाते, फिर वकील - ... मॉडल

१२वीं योजना

१९९१ के बाद की निवेश संरचना :
↳ वकील ब्रह्मानन्द की सिफारिशों को imp

सेन मॉडल ⇒ is a balanced मॉडल
↳ आज की थी

भगवती मॉडल
- कोई मौलिकता नहीं
- लगभग same as नारायणी
- वितरणकारी कार्य (मनरेगा, NRHM) खर्च ↑ ⇒ तो infra cost हेतु पैसा ↓
→ आधुनिक निवेश मॉडल
↳ अल्पकाल में रोजगार बनाये रखने पर बल

सेन
Growth के साथ-साथ
- वितरणकारी न्याय की प्रतिबद्धता भी रहे
कीन्सवादी विकास मॉडल

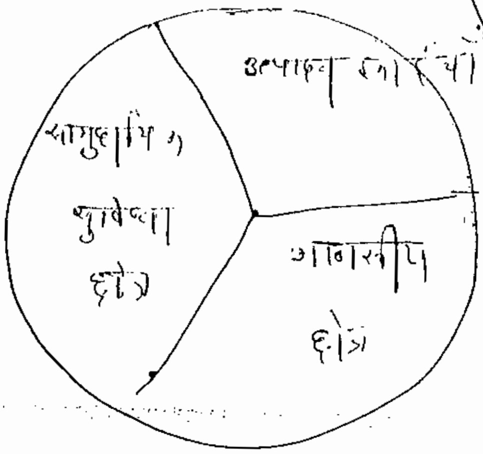

→ वर्तमान में सेन मॉडल के करीब हैं, जो केवल वैकल्पिक द्वारा वितरित नहीं किया जाता है

→ NIMZ
⇓
इनके विपरीत SEZ से संरचना केवल उत्पादन क्षेत्र होते हैं।

निवेश की प्रक्रिया में ही धन वितरण का प्रयास करे

SEZ ⇒ NIMZ की तरह विभिन्न क्षेत्र के हेतु विभाजित नहीं.

⇓

∴ उत्पादन इकाईयां का आवासीय क्षेत्र से टकराव

⇓

∴ तालमेल

⇓

∴ सफल नहीं हुए NIMZ से ज्यादा?

SEZ
⇓
निर्यात प्रेरित निवेश मॉडल

1991 ——→ 99 तक 04-05

11 करोड़ $ 40 अरब $ 68 अरब

Now निर्यात ⇒ 200 अरब डॉलर से ज्यादा

पिछले 8 साल में तिगुना

अभी नहीं का ख्याल

नुकसान → भूमि अधिग्रहण विवाद

मेगा फूड पार्क मॉडल

मेगा फूड पार्क में निवेश की संरचना क्या है

Deinvestment Model ∅ — Disinvestment Model

(i) निवेश की मात्रा को कम करना।

(i) एक संस्था द्वारा किये गये निवेश की मात्रा को कम करना।

यह निवेश की वर्तमान संरचना को संशोधित करने वाला नया नीतिगत ढाँचा, जिसमें सरकारी निवेश ↓ निजी निवेश ↑ ⇒ यह

P-P-P निवेश मॉडल

· Technology Centric F. M.

↳ ~~तकनीकी को~~ ~~[illegible]~~।

केवल तकनीकी के विकास / R&D पर विकास

Technology Driven, (Tech Driven की क्षमता)

1986 में इससे संबंधित नारा दिया गया।

↳ उत्पादन कार्य में तकनीक को बढ़ाना

Ex: कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में तकनीकी।

Technology Sector

↳ तकनीकी सेक्टर में जो कंपनियाँ हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाने हेतु कार्य करना

Q. एक क्षेत्र की कंपनियों के majority निवेश को ग्रीनफील्ड & ब्राउनफील्ड

ग्रीन फील्ड

↳ F.D.I. के गुणात्मक रूप से दो प्रकार होते हैं--

ग्रीन फील्ड F.D.I. → (विस्तार) (पैसों द्वारा क्षमता का विस्तार)

(केवल शेयर की खरीद) ← ब्राउन फील्ड F.D.I.

- जिस F.D.I. से मेजबान देश की उत्पादन क्षमता में विस्तार हो, या गुणात्मक उन्नयन हो, उसे ग्रीन फील्ड F.D.I. कहते हैं।

- इससे रोजगार अवसर प्राप्त होता।
  ↳ नयी हवा की फैक्ट्री

- जिस F.D.I. से मेजबान देश में पहले से कार्यरत कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन मात्र हो, क्षमता में विस्तार या उत्पादन सुनिश्चित ना हो, उसे ब्राउन फील्ड F.D.I. कहते हैं।

- इससे मेजबान देश को रोजगार/अर्थ. को सीमित लाभ हो

→ इसे पहले ही clear करने की नीति रहना FOT होना => अनुमोदन के समय ही दृढ़ता के साथ इसे कहा जाए

आनन्द शर्मा ने ब्राउन फील्ड को परिभाषित नहीं

✓ सिक्वेस्टर क्या है?

✓ टैपरिंग से क्या समझते हैं?

✓ IFS की बैठक → विदेश नीति को reset किया है
new पंचशील
(1) Globalisation
(2) बहुपक्षीय संबंधों को हर देश के साथ बनायेंगे।
(3) विश्व राजनीति में अग्रणी भूमिका की बात

(भारत को superpower बनाने की प्राथमिक विदेश नीति)

✓

चालू खाता घाटा ↑
→ सोना का आयात
→ तेल का आयात
→ कोयला का आयात

Capital Account पर Convertability

		पहले	now
①	व्यक्ति को विदेश में ले जाने की सीमा	2 लाख	75,000
②	कंपनी नेटवर्थ का कितना % ECB ले सकती है	400%	100%
③	F I I हेतु		

... ↑

- भारतीय द्वारा विदेश में real estate में निवेश पर पाबंदी
- तेल परिशोधन के साथ RBI का करेंसी स्वैप
- करेंसी स्वैप समझौता

पूंजी खाते के माध्यम से विदेशी मुद्रा के विनिमय की मांग घटा दी गयी। (परिवर्तनीयता)

=> जापान - India करेंसी स्वैप सीमा ↑

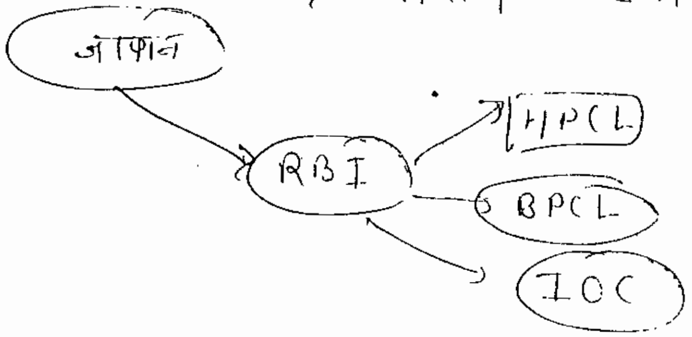

करेंसी स्वैप से विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय ↓

- फेमा के तहत RBI को Foreign Exchange Management का अधिकार है, Control का नहीं

- BOP account है - में व्यवस्था के अनुसार पर रहता है

Current Capital

- निर्यात ↑
- आयात का मूल्य ↑
- CAD

विश्लेषण :-

85 अरब $ का बांड्स का फंड विदेशी फंड माह खरीद रहा है, Since 2012 (!)

बाजार में $ की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है

(QE - 3)

यह क्वांटिटेटिव ईजिंग का तीसरा चरण है।

इससे USA के फेड बैंक की आरक्षित निधि के $ में

अनुपात कम हो रहा है ⇒ जबकि बॉण्ड

में अनावश्यक वृद्धि ⇒ जो कि व्यावहारिक

स्तर से काफी ज्यादा

⇓

उक्त के कारण Economy में समस्या

⇓

दबाव ⇒ बॉण्ड खरीदने की प्रक्रिया को

चरणबद्ध रूप से [illegible] जाये ।
कम किया

इसी प्रक्रिया को टेपरिंग कहते हैं ।

85 से 75 से 65 से 55

टेपर (कार्यक्रम)

⇓

टेपरिंग (परिणाम) Open Market में [illegible] ⇒ अगर बाजार रिकॉर्ड ऊँचाई पर (स्टॉक मार्केट)

⇒ इसमें 2008 की तरह गिरावट होने की संभावना

⇓

उच्च दोष की संभावना

⇓

∴ टेपरिंग शुरू किया जाये ।

टेपरिंग :- [illegible] में [illegible] नरमीकरण से परिसंपत्ति बाजार में आ चुकी तेजी को धीरे-2 कम करके व्यावहारिक स्तर पर लाने की की नीति

कारोबारी संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने वाले कारोबारी रणनीति, [illegible] प्रक्रिया शर्त लेकर

इस प्रक्रिया को शासन का निगमीकरण कहते हैं।
(Corporatization of Governance)

निगम शासन (Corporate Go.) :-

कंपनी के संगठन में अपने कामगारों, शेयरधारकों के हाथ तथा कंपनी संगठन के बाहर के समाज के साथ कंपनी गैर आचरण के मानकीकरण हेतु कंपनी द्वारा अपनाये गये मानक, सिद्धांत एवं नियमों की समग्र व्यवस्था को निगम शासन कहते हैं

नीतिगत लकवा के संदर्भ में सरकार के ऊपर [illegible] का आरोप यूरोप व USA मीडिया में लगाते रहे हैं।

Policy Paralysis (नीतिगत लकवा)

(i) अर्थव्यवस्था के निष्पादन में गिरावट -

but सरकार की उम्मीद के बावजूद अनुकूल नीति नहीं बन पा रही है।

or क्रियान्वयन की कमी